एजुकेशन & कॅरिअर

हार मानना आसान है, लेकिन टिके रहना ही सफलता है।

अमर उजाला Job Alert

Real-time job alerts
amarujala.com/jobs

इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड

अप्रेंटिसशिप के लिए योग्य उम्मीदवार करें आवेदन

2623 पद

आवेदन की अंतिम तिथि : 31 जनवरी, 2026
आयु-सीमा : न्यूनतम 18 साल व अधिकतम 24 वर्ष निर्धारित
यहां आवेदन करें : iocl.com/apprenticeships

इंडिया एक्जिम बैंक में रिक्तियां ■ 40 पद

मैनेजनेंट ट्रेनी के पदों पर नौकरी की संभावनाएं
आवेदन की अंतिम तिथि
01 फरवरी, 2026
योग्यताएं
ग्रेजुएशन व अन्य निर्धारित पात्रताएं
यहां आवेदन करें
eximbankindia.in

एआईआईए में आवेदन आमंत्रित ■ 33 पद

कंप्यूटर प्रोग्रामर, अकाउंट ऑफिसर आदि के पद खाली
आवेदन की अंतिम तिथि
02 मार्च, 2026
योग्यताएं
एमकॉम, एमबीए व अन्य निर्धारित पात्रताएं
यहां आवेदन करें
aiia.gov.in

दिल्ली राज्य स्वास्थ्य मिशन ■ 200 पद

मेडिकल ऑफिसर के पदों पर आवेदन आमंत्रित
आवेदन की अंतिम तिथि : 30 जनवरी, 2026
योग्यताएं : एमबीबीएस व अन्य निर्धारित
यहां आवेदन करें : dshm.delhi.gov.in

भारतीय स्टेट बैंक में संभावनाएं ■ 12 पद

वाइस प्रेसिडेंट, डिप्टी मैनेजर के पदों पर रोजगार के अवसर
आवेदन की अंतिम तिथि
05 फरवरी, 2026
आयु-सीमा
अधिकतम आयु 35-50 वर्ष तक निर्धारित
यहां आवेदन करें
sbi.bank.in

सी-डॉट में रोजगार के अवसर ■ 10 पद

साइंटिस्ट के पदों पर योग्य उम्मीदवार करें अप्लाई
आवेदन की अंतिम तिथि
16 फरवरी, 2026
आयु-सीमा
अधिकतम उम्र 40 वर्ष निर्धारित
यहां आवेदन करें
cdot.in

योग्य उम्मीदवार करें आवेदन ...

- मानव व्यवहार एवं संबद्ध विज्ञान संस्थान, दिल्ली : प्रोफेसर, सहायक प्रोफेसर व अन्य पदों पर रिक्तियां।
  आवेदन की अंतिम तिथि : 31 जनवरी, 2026
- ihbas.delhi.gov.in
- दामोदर वैली कॉरपोरेशन, कोलकाता : कार्यकारी निदेशक का पद रिक्त।
  आवेदन की अंतिम तिथि : 25 जनवरी, 2026
- dvc.gov.in

अपनी प्रतिक्रियाओं और सुझावों के लिए हमें udaan@amarujala.com पर ई-मेल करें।

कॅरिअर चुनाव में इन बातों का रखें ध्यान

कॅरिअर का फैसला करते समय अपनी रुचि और योग्यता के साथ-साथ बदलते जॉब मार्केट को समझना जरूरी होता है

मरीना मिलोशेवा
लेखिका, एडिनबर्ग नेपियर यूनिवर्सिटी

बचपन से ही हमसे पूछा जाता है कि बड़े होकर क्या बनना है। जैसे-जैसे हम आगे बढ़ते हैं, पढ़ाई के चुनाव से लेकर कॅरिअर तय करने तक हर मोड़ पर हमसे जल्दी और स्पष्ट फैसले लेने की उम्मीद की जाती है। इसी दबाव में कई युवा बिना पूरी समझ के कॅरिअर चुन लेते हैं। बाद में, 20 से 30 की उम्र के बीच उन्हें महसूस होता है कि वे शायद गलत जगह फंस गए हैं। किसी का काम में मन नहीं लगता, तो किसी की क्षमताओं का सही उपयोग नहीं हो पाता। सच यह है कि कॅरिअर चुनना आसान नहीं होता, क्योंकि इसमें अपनी रुचि, योग्यता और लगातार बदलते जॉब मार्केट, इन तीनों के बीच संतुलन बनाकर फैसला लेना पड़ता है।

■ शुरुआत लक्ष्य तय करने से करें
नौकरी और कॅरिअर एक जैसे नहीं होते। नौकरी सिर्फ रोज का काम है, जबकि कॅरिअर एक लंबी प्रक्रिया है, जिसमें हम सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं और खुद को बेहतर बनाते हैं। कॅरिअर की सही शुरुआत अपने लक्ष्य तय करने से होती है। इसके लिए खुद से पूछें कि आपको क्या करना अच्छा लगता है, आपकी कौन-सी खूबियों की लोग तारीफ करते हैं और कौन-सा काम आपको संतुष्टि देता है। अगर जवाब साफ न मिले, तो परिवार और दोस्तों से बात करें या किसी सरल कॅरिअर परीक्षण की मदद लें। इससे आपको सही दिशा समझने में आसानी होती है।

■ आसान योजना बनाएं
लक्ष्य तय करने के बाद सबसे जरूरी काम है उस लक्ष्य तक पहुंचने की सही योजना बनाना। इसके लिए पहले यह समझें कि आपको कौन-से नए कौशल सीखने हैं और क्या किसी खास ट्रेनिंग या पढ़ाई की जरूरत पड़ेगी। साथ ही यह भी तय करें कि आपका लक्ष्य किस कंपनी, संस्था या क्षेत्र में पूरा हो सकता है। अगर आप कॅरिअर में छोटा बदलाव करना चाहते हैं, तो अपने मौजूदा काम में ही नई भूमिका तलाशना एक अच्छा विकल्प हो सकता है। जरूरत पड़ने पर कॅरिअर सलाहकार से सलाह लें या ऑनलाइन उपलब्ध फ्री गाइडेंस का सहारा लें। अपनी योजना को छोटे-छोटे चरणों में बांटें, जैसे कुछ महीनों में नई स्किल सीखना या तय समय में खुद को नई भूमिका के लिए तैयार करना। इससे आपका सफर ज्यादा स्पष्ट, आसान और आत्मविश्वास से भरा होगा।

■ जो दिल को सुकून दे
हर किसी को तुरंत सपनों की नौकरी नहीं मिलती, और यह बिल्कुल सामान्य है। जब तक ऐसी नौकरी नहीं मिलती है, तब तक ऐसा काम चुनना बेहतर होता है, जो आपकी जरूरतें पूरी करे और आपको भीतर से ठीक महसूस कराए। अच्छा काम वह है, जिससे आमदनी स्थिर रहे, नौकरी का डर न हो और काम आपकी सेहत व मन पर बोझ न बने। वही सही मायने में अच्छा काम होता है, जो आपकी सोच और मूल्यों से जुड़ा हो, जहां आप कुछ सीख सकें, खुद को उपयोगी महसूस करें और जीवन में संतुलन बना रहे। -द कन्वर्सेशन

खुद को परखें

1. हाल ही में खबरों में छाया असोला-भट्टी वन्यजीव अभयारण्य किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है?
   (a) विंध्य
   (b) अरावली
   (c) शिवालिक
   (d) सतपुड़ा
2. कोंडा रेड्डी जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है?
   (a) कर्नाटक
   (b) महाराष्ट्र
   (c) आंध्र प्रदेश
   (d) ओडिशा
3. ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट-2026 किस संगठन द्वारा जारी की गई थी?
   (a) विश्व बैंक
   (b) अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष
   (c) संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम
   (d) विश्व आर्थिक मंच

उत्तर-1.b, 2.c, 3.d

आवेदन आमंत्रित

एनसीईआरटी डॉक्टोरल फेलोशिप प्रोग्राम

एनसीईआरटी डॉक्टोरल फेलोशिप के लिए छात्रों से आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। इस फेलोशिप कार्यक्रम का उद्देश्य युवा विद्वानों को शिक्षा और संबंधित विषयों में डॉक्टोरल शोध करने में सक्षम बनाना तथा समकालीन संदर्भ में शिक्षा के ज्ञान आधार को सुदृढ़ करना है। आवेदन के लिए आवश्यक है कि उम्मीदवार ने स्नातक और परास्नातक दोनों स्तरों पर न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हों और उसका शैक्षणिक रिकॉर्ड अच्छा हो। इसके अतिरिक्त, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में पीएचडी के लिए पंजीकृत उम्मीदवार ही आवेदन के पात्र होंगे। आवेदक की आयु 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। चयनित उम्मीदवारों को उनकी योग्यता के अनुसार 35,000 या 37,000 रुपये प्रतिमाह फेलोशिप प्रदान की जाएगी। साथ ही, फेलोशिप अवधि के दौरान उन्हें प्रति वर्ष 10,000 रुपये का आकस्मिक अनुदान भी मिलेगा। आवेदक आधिकारिक लिंक forms.ncert.gov.in/df/ पर जाकर आवेदन सकते हैं।

अंतरराष्ट्रीय पहल

नाइट फोटोग्राफी एग्जीबिशन में हों शामिल

सिटी लाइट्स की नाइट फोटोग्राफी एग्जीबिशन में आवेदन आमंत्रित हैं। इस प्रदर्शनी में रात्रिकालीन शहरी जीवन को स्पष्टता और उद्देश्य के साथ दर्शाने वाली रचनाएं स्वीकार की जाएंगी, जिनमें सड़कें, वास्तुकला, मानवीय गतिविधियां और कृत्रिम प्रकाश शामिल हो सकते हैं।

■ मानदंड
यह प्रतियोगिता विश्वभर के 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के फोटोग्राफरों के लिए खुली है। प्रत्येक प्रतिभागी एक ओपन कॉल में अधिकतम तीन फोटो जमा कर सकता है।

■ सहभागिता के लाभ
चयनित प्रतिभागियों की एक या अधिक तस्वीरें वर्चुअल ऑनलाइन प्रदर्शनी में प्रदर्शित की जाएंगी। उन्हें प्रदर्शनी कैटलॉग की निःशुल्क पीडीएफ, मान्यता प्रमाण पत्र तथा सोशल मीडिया पर अपनी रचनाएं प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा। साथ ही, तस्वीरें इंस्टाग्राम @carlottagallery पर कलाकार विवरण के साथ स्थायी रूप से प्रदर्शित की जाएंगी।

■ ऐसे करें आवेदन
प्रतिभागी 20 फरवरी, 2026 तक आधिकारिक लिंक carlottagallery.co.uk/opencalls पर जाकर इस एग्जीबिशन में भाग ले सकते हैं।

एग्जाम अलर्ट हफ्ते की परीक्षाएं

बिहार पुलिस एसआई परीक्षा-2025

- **परीक्षा की तिथि :**
  21 जनवरी, 2026
- इस परीक्षा में सामान्य ज्ञान और समसामयिक मुद्दों से संबंधित कुल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न के लिए दो अंक निर्धारित हैं। परीक्षा की अवधि दो घंटे होगी।
- **यहां से प्रवेश-पत्र डाउनलोड करें**
  tinyurl.com/3mzp5bph

बीपीएससी 70वीं सीसीई साक्षात्कार

- **साक्षात्कार की तिथि :**
  21 जनवरी से 28 फरवरी, 2026
- बीपीएससी 70वीं सीसीई साक्षात्कार में अभ्यर्थियों से उनकी रुचि, सामाजिक कौशल और करंट अफेअर्स से संबंधित 120 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे।
- **यहां से प्रवेश-पत्र डाउनलोड करें**
  bpsconline.bihar.gov.in

सामान्य ज्ञान

हवाना सिंड्रोम

■ क्या है
यह ऐसे मानसिक स्वास्थ्य लक्षणों का समूह है, जो अलग-अलग देशों में अमेरिकी खुफिया और दूतावास अधिकारियों में देखे गए हैं।

■ चर्चा में क्यों
पेंटागन के एक गुप्त रेडियो तरंग छोड़ने वाले उपकरण के अमेरिका में परीक्षण से हवाना सिंड्रोम पर फिर सवाल उठने लगे हैं।

■ लक्षण
यह कोई एक तय बीमारी नहीं है, बल्कि कुछ लक्षणों का समूह है, जो साथ-साथ दिखाई देते हैं और जिनका असली कारण पता करना मुश्किल होता है। इनमें बिना आवाज के अजीब ध्वनियां सुनना, याददाश्त कमजोर होना और संतुलन बिगड़ना शामिल हैं।

■ इसकी उत्पत्ती
यह सिंड्रोम पहली बार 2016 में क्यूबा के हवाना में सामने आया, जब वहां तैनात अमेरिकी राजनयिकों को इसके लक्षण दिखे। दूतावास खुलने के करीब एक साल बाद कुछ अधिकारियों को अचानक तेज सिरदर्द, भ्रम और नींद न आने की समस्या होने लगी। भारत में पहला मामला 2021 में दर्ज हुआ। अब तक इसके कारणों को लेकर कोई पक्की जानकारी नहीं है।

रोशनी यहां है

इस बार : विकास धनमल नाहर
क्यों : सीमित संसाधनों के बीच खड़ा किया करोड़ों का कारोबार

एक किसान परिवार में पैदा हुए हैप्पिलो के संस्थापक व सीईओ विकास धनमल नाहर ने 20 से अधिक असफलताओं और पेट पालने के लिए किए गए छोटे-मोटे कामों के बावजूद, हार नहीं मानी। मात्र 10 हजार रुपये और दो कर्मचारियों के साथ शुरू हुई उनकी कंपनी 'हैप्पिलो' आज 500 करोड़ रुपये का साम्राज्य बन चुकी है।

किसान के बेटे हैं, संघर्षों में पले-बढ़े, सूखे मेवों ने दिलाई पहचान, आज है करोड़ों रुपये का ब्रांड

यह प्रेरणादायी कहानी है कर्नाटक के एक साधारण किसान परिवार में जन्मे एक युवा की, जिसे अपनी मंजिल तक पहुंचने से पहले बीस से भी ज्यादा बार असफलताओं का सामना करना पड़ा। कई बार तो हालात ऐसे बने कि पेट पालने के लिए उसे छोटे-मोटे काम भी करने पड़े। पर उसने कभी खुद को और अपने सपने को टूटने नहीं दिया। आखिरकार, कई ठोकरों के बाद उसने अपनी एक छोटी-सी कंपनी शुरू की। कारोबार धीरे-धीरे संभल ही रहा था कि कोरोना महामारी ने उस पर ब्रेक लगा दिया। गोदाम में लाखों का माल पड़ा रह गया। वह युवा जब जरूरी सप्लाई की अनुमति के लिए कमिश्नर के पास पहुंचा, तो उसे जवाब मिला कि ड्राई फ्रूट्स जरूरी सामान की सूची में नहीं आते। अब उसके सामने सबसे बड़ा सवाल था कि कर्मचारियों को वेतन कैसे मिलेगा? लेकिन यहीं उसने हार मानने के बजाय अपनी सोच बदलने का फैसला किया। ई-कॉमर्स को अपनाया और अपने उत्पाद ऑनलाइन बेचने शुरू किए। यही फैसला उसकी किस्मत का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। लगातार मेहनत, सही रणनीति और कभी न हार मानने वाली सोच के दम पर सिर्फ 10 हजार रुपये से शुरू हुई उसकी कंपनी आज 500 करोड़ रुपये से ज्यादा का कारोबार कर रही है। हम बात कर रहे हैं हैप्पिलो के संस्थापक और सीईओ विकास धनमल नाहर की, जो हमें सिखाते हैं कि सपने टूटने से नहीं, छोड़ देने से मरते हैं।

एक फैसले ने बदली दिशा

वर्ष 1984 में जन्मे विकास के परिवार की आजीविका कॉफी और काली मिर्च की खेती से चलती थी। खेती-किसानी से ही उन्होंने धैर्य और संघर्ष का पहला पाठ सीखा। उनके पिता धनमल नाहर कॉफी और काली मिर्च का व्यापार भी करते थे, इससे विकास को बचपन से ही व्यापार की बुनियाद समझ मिलने लगी थी। विकास ने शुरुआती पढ़ाई गांव के स्कूलों से ही पूरी की। सीमित संसाधनों के बावजूद आगे की पढ़ाई के लिए वह बंगलूरू यूनिवर्सिटी पहुंचे और वर्ष 2005 में कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएशन पूरा किया। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने एक बड़ी कंपनी में तीन वर्षों तक वरिष्ठ आयात प्रबंधक (एशिया) के रूप में काम किया। एक स्थिर नौकरी के बावजूद विकास संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि वह अपनी पहचान खुद बनाना चाहते थे। इसलिए, उन्होंने नौकरी छोड़ दी और अपने सपनों को सही दिशा देने के लिए सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी से एमबीए करने का निर्णय लिया। यहीं से उनके उद्यमी बनने की यात्रा शुरू हुई।

सीखे हुए सबक आए काम

एमबीए के दौरान कैंपस प्लेसमेंट के जरिये विकास का चयन एक नामचीन बैंक में हुआ। हालांकि, उन्होंने महज छह महीने बाद ही नौकरी छोड़ दी। इसके बाद उन्होंने एक स्टार्टअप में लगभग साढ़े चार साल तक प्रबंध निदेशक के रूप में काम किया। यह कंपनी सेहत से जुड़े उत्पादों, जैसे सूखे मेवे आदि, पर केंद्रित थी। यहीं पर हासिल किए अनुभव और सबक ने उन्हें व्यापार के लिए पूरी तरह तैयार किया। अंततः उन्होंने अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने का निर्णय लिया।

दो कर्मचारियों के साथ शुरू हुआ सफर

भले ही विकास को व्यवसाय की समझ विरासत में मिली थी, लेकिन खुद की कंपनी हैप्पिलो शुरू करने में उन्हें बीस से ज्यादा बार असफलताओं का सामना करना पड़ा। जब वह अपने विचार लेकर निवेशकों के पास जाते, तो हर बार निराशा ही हाथ लगती। इस संघर्ष के दौर में उन्होंने खुदरा विक्रेता और वितरक के रूप में भी काम किया। जब निवेशकों ने हाथ पीछे खींच लिए, तो अपनी जमापूंजी के महज 10 हजार रुपये और दो कर्मचारियों के साथ विकास ने हैप्पिलो की शुरुआत की। बाद में उनकी पत्नी ने 20 लाख रुपये का लोन लेकर निवेश किया। कुछ समय बाद सरकार की सीजीटीएमएसई योजना के तहत 75 लाख रुपये की सहायता मिली, जिसने कंपनी को आगे बढ़ने की मजबूत नींव दी।

विकास की उड़ान

आज हैप्पिलो केवल एक ब्रांड नहीं, बल्कि भारतीय उद्योग जगत में एक प्रेरक मिसाल बन चुका है। 40 से अधिक किस्मों के पैकेटबंद सूखे मेवे, 100 से ज्यादा चॉकलेट वैरायटी और 60 से अधिक मसालों के साथ कंपनी ने सेहत और स्वाद, दोनों में अपनी अलग पहचान बनाई है। आज 500 करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार कर रही यह कंपनी दूरदर्शी नेतृत्व और नवाचार की मिसाल है। पांच भाषाओं में दक्ष विकास की वैश्विक दृष्टि और निरंतर सीखने की ललक उन्हें भीड़ से अलग खड़ा करती है। 'शार्क टैंक इंडिया' में मौजूदगी, फोर्ब्स और टाइम्स की '40 अंडर 40' सूची में स्थान और अनेक प्रतिष्ठित पुरस्कार विकास के धैर्य और मेहनत का प्रमाण हैं।

युवाओं को सीख

- असफलताओं से घबराने के बजाय उनसे सबक लेना चाहिए।
- बड़े सपने देखें, लेकिन शुरुआत छोटी करने से न डरें।
- धैर्य और निरंतर प्रयास ही सफलता की कुंजी हैं।
- दूरदर्शिता और आत्मविश्वास से ही स्थायी सफलता मिलती है।

आज का दिन

19 जनवरी, 1825

अमेरिकी एज्रा डैगेट और थॉमस केनसेट को टिन के डिब्बों में खाद्य पदार्थों को संरक्षित करने वाली प्रक्रिया (कैनिंग) का पेटेंट मिला था। इससे खाद्य संरक्षण में बड़ी प्रगति हुई।

- 1853 : ग्यूसेप वर्डी के ओपेरा 'इल ट्रोवाटोर' का प्रीमियर रोम में हुआ था।
- 1946 : अमेरिकी गायिका डॉली पार्टन का जन्म हुआ था।
- 1955 : अमेरिकी राष्ट्रपति ड्वाइट डी आइजनहावर ने पहली बार टीवी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी।
- 2013 : अमेरिकी बेसबॉल खिलाड़ी स्टेन मुसिअल का निधन हुआ था।

व्रत त्योहार

आज : माघ शुक्ल पक्ष प्रतिपदा।
कल : शिशिर ऋतु, सूर्य उत्तरायणे, दक्षिण गोले।
राहुकाल : दिन में 15.00 से 16.30 तक।

कल का पंचांग

विक्रमी संवत 2082, 30 पौष मास शक 1947, माघ मास 07 प्रविष्टे, 30 रज्जब हिजरी 1447, माघ शुक्ल पक्ष द्वितीया 26.42 तक उपरांत तृतीया, श्रवण नक्षत्र 13.06 तक उपरांत धनिष्ठा नक्षत्र, सिद्धि योग 20.00 तक उपरांत व्यतिपात योग, बालव करण 14.28 तक उपरांत कौलव करण, चंद्रमा कुंभ राशि में 25.32 बजे।

- सूर्योदय : 07.18
- सूर्यास्त : 17.46

(भारतीय मानक समयानुसार)

राशिफल

amarujala.com/astrology
■ पं. विनोद त्यागी

मेष : राजकाज में सफलता मिलेगी। नौकरी में पदोन्नति हो सकती है। सरकारी क्षेत्र से अर्थ प्राप्ति हो सकती है।

वृष : मानसिक उत्तेजना पर नियंत्रण रखें। अटकी योजना सफल होगी। प्रभावी व्यक्ति से जान-पहचान बढ़ सकती है।

मिथुन : व्यवहार कुशलता बनाए रखें। नए कार्य में पूंजी निवेश से हानि होगी। नौकरी में स्थिति सामान्य रहेगी।

कर्क : मनोबल बना रहेगा। नौकरी में वर्चस्व बढ़ेगा। साझेदारी में मनमुटाव की स्थिति आ सकती है।

सिंह : स्वास्थ्य में सुधार आएगा। कानूनी मामला सुलझ सकता है। नौकरी में उन्नति के संकेत मिल सकते हैं।

कन्या : सकारात्मक सोच बनाए रखें। नौकरी में अधिकारी अनुकूल रहेंगे। व्यवसाय का विस्तार हो सकता है।

तुला : सरकारी कार्य में अवरोध आ सकते हैं। नौकरी में कार्यभार बढ़ेगा। व्यवसाय में आय-व्यय सम रहेंगे।

वृश्चिक : लोकप्रियता में वृद्धि होगी। राजनीतिक क्षेत्र में सम्मान बढ़ेगा। व्यवसाय में लाभ के अवसर मिलेंगे।

धनु : स्वजनों से मतभेद रहेंगे। आर्थिक क्षेत्र में सावधानी बरतें। नौकरी में मान-सम्मान बना रहेगा।

मकर : मनोत्साह बना रहेगा। नौकरी में उन्नति या नई नौकरी का अवसर मिल सकता है। विरोधी परास्त होंगे।

कुंभ : मानसिक उथल-पुथल बनी रहेगी। किसी समस्या का समाधान संभव है। नौकरी में स्थिति यथावत रहेगी।

मीन : सरकारी क्षेत्र में अटके कार्य बनेंगे। मित्र सहायक रहेंगे। संपत्ति में वृद्धि होगी। व्यवसाय में लाभ होगा।

जन्मदिन

वरुण तेज, अभिनेता

इस वर्ष सामाजिक मान-सम्मान बढ़ेगा। शुभचिंतकों का सहयोग मिलेगा। अल्प श्रम से ही योजनाओं में अनुकूल सफलता मिलेगी। आर्थिक दृष्टि से वर्ष महत्वपूर्ण रहेगा। उच्चस्तरीय परीक्षाओं में सफलता मिलेगी। लेखन कार्य में लगे जातकों को नई पहचान मिलेगी। स्वास्थ्य अनुकूल रहेगा।

सुडोकू

			1				9	
							5	7
	7		8	2	4		1	
				1			3	
		7	4		3	5		
	2			6				
	4		6	9	1		2	
9	6							
	3				2			

सुडोकू 81 वर्गों का ग्रिड है, जो 9 वर्गों के ब्लॉक में बंटा हुआ होता है। कुछ वर्गों के अंक लिखे हैं और खाली वर्गों में 1 से लेकर 9 तक के अंक लिखने होते हैं। कोई नंबर 1 पंक्ति, कॉलम या 9 वर्ग वाले छोटे ब्लॉक में दोबारा नहीं आ सकता है।

उत्तर

3	8	6	1	7	5	2	9	4
2	1	4	9	3	6	8	5	7
5	7	9	8	2	4	6	1	3
6	5	8	2	1	7	4	3	9
1	9	7	4	8	3	5	6	2
4	2	3	5	6	9	7	8	1
7	4	5	6	9	1	3	2	8
9	6	2	3	4	8	1	7	5
8	3	1	7	5	2	9	4	6

डेली हेल्थ कैप्सूल

ओट्स की रोटी है बहुत स्वास्थ्यवर्धक

ओट्स की रोटी पाचन तंत्र को बेहतर बनाने, वजन घटाने और कई समस्याओं में लाभदायक होते हैं।

ज्यादातर घरों में गेंहू के आटे से रोटियां बनाई और खाई जाती हैं, लेकिन आप ओट्स की रोटी का सेवन करके कई लाभ पा सकते हैं। इसमें विटामिन-ए, बी, प्रोटीन, फाइबर, कैल्शियम, आयरन, जिंक, मैग्नीशियम और पोटैशियम होता है। इस रोटी में में मौजूद फाइबर पेट को लंबे समय तक भरा हुआ रखता है। इससे वजन कम करने में मदद

मिलती है। साथ ही फाइबर शरीर में इंसुलिन स्पाइक को रोकने में भी सहायक है। इससे आंतों की सफाई भी अच्छे से हो जाती है। इससे पाचन क्रिया दुरुस्त रहती है। इस रोटी के नियमित सेवन से गैस और कब्ज से छुटकारा मिल सकता है। ओट्स में पाए जाने वाले प्रोटीन और घुलनशील फाइबर ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखता है। यह कोलेस्ट्रॉल कम करने में सहायक है। इसमें मौजूद ओमेगा-3 एसिड दिल को सेहतमंद रखने में मदद करते हैं। ओट्स की रोटी में विटामिन्स, मिनरल्स और प्रोटीन होते हैं, जो इम्युनिटी को बढ़ाकर कई बीमारियों से बचाव करते हैं। ओट्स की रोटी बनाने के लिए पैन में बिना तेल के ओट्स को भूनें। फिर इसे मिक्सी में महीन पीसकर आटा गूंथ लें। अब इस आटे से रोटियां तैयार करें।

क्या कहते हैं विशेषज्ञ

ओट्स की रोटी का अधिक सेवन करने से पेट फूलना या गैस की समस्या हो सकती है। इसलिए इसका सीमित मात्रा में ही सेवन करें। गर्भावस्था या किसी अन्य गंभीर बीमारी में सेवन से पहले चिकित्सक से सलाह जरूर लें।
-पायल शर्मा, आहार विशेषज्ञ

प्रवाह
77 साल बेमिसाल
निर्भीक पत्रकारिता का आठवां दशक
स्थापना : 18 अप्रैल 1948 • आगरा

आपस में जुड़ी हुई इस डिजिटल दुनिया में, साइबर सुरक्षा की जिम्मेदारी हम सभी की है। -न्यूटन ली

आठ यूरोपीय देशों पर टैरिफ लगाकर ट्रंप ने जाहिर किया है कि वह ग्रीनलैंड पर अमेरिकी कब्जे को लेकर किस कदर गंभीर हैं। आर्कटिक क्षेत्र में जिस तरह से महाशक्तियों के हित गुंथे दिख रहे हैं, उसमें देखना होगा कि कहीं हम शीतयुद्ध के अगले दौर की तरफ तो नहीं बढ़ रहे?

ग्रीनलैंड और ट्रंप

वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले पर बहस अभी थमी भी नहीं थी कि अब ग्रीनलैंड पर अमेरिकी नियंत्रण को लेकर डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से आमादा दिख रहे हैं, उससे अंतरराष्ट्रीय राजनीति में तो हलचल मची ही है, आधुनिक वैश्विक राजनीति में भी एक नए किस्म के उपनिवेशवाद पर चर्चा ने जोर पकड़ लिया है। ट्रंप टैरिफ को अपना पसंदीदा शब्द कहते हैं और इसका उपयोग करते हुए उन्होंने ग्रीनलैंड पर अमेरिकी कब्जे का विरोध करने वाले आठ यूरोपीय देशों पर आगामी एक फरवरी से दस फीसदी टैरिफ लगाने की धमकी दी है। ट्रंप पहले भी कई बार ग्रीनलैंड पर नियंत्रण की बात कह चुके हैं और पिछले वर्ष तो उन्होंने इस क्षेत्र के लिए एक विशेष दूत की नियुक्ति भी की थी। दरअसल, इस क्षेत्र में ट्रंप की बढ़ती रुचि की वजहें भूराजनीतिक होने के साथ सामरिक व आर्थिक भी हैं। ग्रीनलैंड आर्कटिक क्षेत्र के केंद्र में स्थित एक द्वीप है, जो डेनमार्क के अधीन रहते हुए कई तरह की स्वायत्तता रखता है। रूस इस क्षेत्र में नए सैन्य अड्डे बना रहा है, जबकि चीन भी खुद को आर्कटिक की ही नजदीकी शक्ति साबित करने पर तुला है। यह भी माना जाता है कि दुनिया के एक-चौथाई दुर्लभ खनिज इसी क्षेत्र में हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए ये खनिज बहुमूल्य हैं, क्योंकि इनका उपयोग इलेक्ट्रिक कारों से लेकर सैन्य उपकरणों तक के निर्माण में होता है। यह कोई छिपी बात नहीं है कि दुर्लभ खनिजों के मामले में चीन पूरी दुनिया में सबसे आगे है। उसका ग्रीनलैंड की खनन कंपनियों में निवेश तो है ही, पिछले कई साल से वह ग्रीनलैंड में अपनी उपस्थिति सशक्त बनाने की भी कोशिश कर रहा है और अमेरिका पर दबाव भी बना रहा है। नैतिक और संप्रभुता संबंधी चिंताएं महत्वपूर्ण हैं, लेकिन इन स्थितियों में अमेरिका का ग्रीनलैंड को अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी मानना अतार्किक नहीं कहा जा सकता। ऐसा मानने वाले ट्रंप कोई पहले अमेरिकी राष्ट्रपति नहीं हैं। उनसे पहले भी कई अमेरिकी राष्ट्रपतियों ने इसका समर्थन किया है, यह दीगर बात है कि वे आगे बढ़ नहीं सके। ट्रंप विशुद्ध व्यापारी सोच वाले व्यक्ति हैं, लेकिन व्यापार आदर्शवाद से नहीं चलते। अपनी यही सोच वह अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर भी लागू कर रहे हैं। व्यापार और अर्थव्यवस्था हमेशा से ही कूटनीति के प्रभावी औजार रहे हैं, जिनका ट्रंप भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं। ग्रीनलैंड के मुद्दे पर भी ट्रंप के इरादे और घोषणाएं नेतृत्व की उसी शैली को दर्शाते हैं, जिसके लिए वह जाने जाते हैं। अमेरिका के हितों के लिहाज से हो सकता है कि वह सही हों, लेकिन आज की जुड़ी हुई दुनिया में विश्व का सबसे ताकतवर देश सिर्फ और सिर्फ खुद के हित के बारे में सोचे, तो यह वैश्विक व्यवस्था के लिए सुसंकेत नहीं है।

निर्णायक प्रहार का वक्त

कानूनी एजेंसियों के नाम पर डिजिटल अरेस्ट करके ठगी करने के मामले आए दिन बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी तस्दीक न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, बल्कि एनसीआरबी व गृह मंत्रालय के आंकड़े भी करते हैं। अब समय आ गया है कि साइबर अपराध और डिजिटल अरेस्ट की जड़ों पर प्रहार हो।

विराग गुप्ता
सुप्रीम कोर्ट के वकील

सीबीआई और जजों के नाम पर बुजुर्गों को डिजिटल अरेस्ट करने वाले अपराधियों का हौसला लगातार बढ़ता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा ने भरी अदालत में खुलासा किया कि साइबर ठगों ने उन्हें फर्जी ट्रैफिक चालान के जाल में फंसाने की कोशिश की, लेकिन वह बच गए। जज के साथ ठगी की कोशिश सुनामी की तरह सभी के लिए बड़ी चेतावनी है।

पिछले साल दिल्ली में 73 साल के सेवानिवृत्त बैंक कर्मी को डिजिटल अरेस्ट करके 23 करोड़ रुपये की साइबर ठगी हुई थी। उसके बाद अमेरिका से भारत वापस आई 77 साल की महिला डॉक्टर के साथ 14.85 करोड़ रुपये की और अब नए साल में 70 साल की बुजुर्ग महिला को डिजिटल अरेस्ट करके सात करोड़ रुपये से ज्यादा की ठगी हुई है। ठगी के 22 करोड़ रुपये के इन दो मामलों में अभी तक 4.89 करोड़ रुपये ही जब्त हो सके हैं। शुरुआती जांच के अनुसार, सिर्फ इन दो मामलों में ही छह से सात चरणों में फैले 5,500 म्यूल, यानी फर्जी खातों, के माध्यम से पैसा अपराधियों तक गया है।

कानून से डरने वाले पढ़े-लिखे बुजुर्ग और सेवानिवृत्त लोग डिजिटल अरेस्ट का ज्यादा शिकार हो रहे हैं। अधिकांश मामलों में बुजुर्गों के बैंक खातों में बड़ी रकम होती है। कई मामलों में मोबाइल में लोन देने वाले एप्स को डाउनलोड करवाकर पैसों का जुगाड़ करने के भी मामले सामने आए हैं। डिजिटल अरेस्ट में पुलिस और कोर्ट के नाम पर धमकाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल डिजिटल अरेस्ट के मामलों का स्वतः संज्ञान लिया था। उस मामले में एक दिसंबर को जारी आदेश के अनुसार, साइबर ठगी के सभी तरह के मामलों का प्रकोप बढ़ रहा है। इसलिए, डिजिटल इंडिया में अपराध के नए आयाम से जुड़े सभी पहलुओं को एकजुट नजरिये से देखने की जरूरत है।

डिजिटल अरेस्ट की सबसे बड़ी वजह लोगों के डाटा का खुले बाजार में कौड़ियों के भाव बिकना है। जब मोबाइल नंबर, आधार, इंटरनेट सर्च

और बैंक खातों से जुड़ी जानकारी अपराधियों के पास होती है, तो पुलिस, सीबीआई या जज बनकर लोगों को डराना बहुत आसान हो जाता है। इसे दुरुस्त करने के लिए संसद से साल 2023 में पारित डाटा सुरक्षा कानून को तुरंत लागू करने की जरूरत है।

भारत के किसी भी कानून में डिजिटल अरेस्ट का प्रावधान नहीं है। वीडियो कॉल से पूछताछ, जांच या गिरफ्तारी का वारंट देने का भी कोई नियम नहीं है। उसके बावजूद, ठग पुलिस, सीबीआई, ईडी, कस्टम, इनकम टैक्स या नारकोटिक्स अधिकारी की यूनिफॉर्म पहनकर लोगों को वीडियो कॉल करते हैं। नकली सरकारी आईडी कार्ड से लैस ठग डराने के लिए बैंकग्राउंड में पुलिस स्टेशन या अदालत जैसे दिखने वाले स्टूडियो का इस्तेमाल करते हैं। डिजिटल अरेस्ट में पार्सल या कूरियर में ड्रग्स, बैंक खाते में गलत ट्रांजेक्शन, मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप जैसे ठगी के तरीके ज्यादा प्रचलित हैं। सरकारी रोब दिखाकर पीड़ित व्यक्ति को मानसिक तौर पर तोड़ने और डराने के लिए डिजिटल गिरफ्तारी का पूरा स्वांग रचा जाता है। ई-मेल और कॉल के जरिये गतिविधियों को ट्रैक करने वाले सॉफ्टवेयर को मोबाइल फोन में इंस्टॉल करवाकर बुजुर्ग और महिलाओं को आतंकित करने के मामले भी आए हैं।

ठग अंतरराष्ट्रीय कॉल करने के लिए अवैध सिम बॉक्स का उपयोग करते हैं। इससे विदेश से आने वाली कॉल पीड़ित के फोन पर भारतीय नंबर के रूप में दिखाई देती है। सरकारी खाते बता कर जिन खातों में पैसे ट्रांसफर करवाए गए, वे जनधन या किराये में लिए गए गरीब लोगों के बैंक खाते होते हैं। कई राज्यों में फैले अपराधियों के नेटवर्क के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई में विलंब का फायदा उठाकर साइबर ठगी की रकम क्रिप्टो करेंसी, गेमिंग एप या हवाला के जरिये कंबोडिया, वियतनाम और लाओस जैसे देशों में बैठे साइबर अपराधियों के पास ट्रांसफर हो रही है। इस मर्ज को ठीक करने के लिए फर्जी सिम कार्ड और बोगस बैंक खातों के लिए टेलीकॉम कंपनियां, यूपीआई प्लेटफॉर्म और बैंकों की आपराधिक जवाबदेही तय होनी चाहिए। साथ ही, आईटी नियमों के तहत शिकायत और अनुपालन (कंप्लायंस) अधिकारियों का विवरण सार्वजनिक नहीं करने वाली एक्स और ग्रोक जैसी तकनीकी कंपनियों की सेफ हार्बर की कानूनी सुरक्षा खत्म होनी चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद केंद्र सरकार ने इस मामले में वित्त, गृह, विदेश, आईटी मंत्रालय, सीबीआई तथा रिजर्व बैंक के अधिकारियों वाली एक उच्चस्तरीय समिति का गठन करके निर्णायक प्रहार का संकल्प लिया है, लेकिन साइबर अपराधों की प्राथमिकी राज्य पुलिस थानों में दर्ज होती है। इसलिए, इस समिति को सफल बनाने के लिए राज्य सरकारों का प्रतिनिधित्व जरूरी है। दिल्ली की जिला अदालत ने ठगी के मामले में अग्रिम जमानत देने से मना करने के साथ ही कहा है कि साइबर अपराधों की बाढ़ से सामाजिक और आर्थिक संरचना को बुरी तरह से नुकसान पहुंच रहा है।

आरबीआई के 2017 के नियमों के अनुसार, राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग के नए फैसले के अनुसार ठगी की रकम 10 दिन में बैंक को लौटानी चाहिए, ताकि पीड़ितों को अदालतों के चक्कर न लगाने पड़ें। गृह मंत्रालय की नई एसओपी के अनुसार, 50 हजार रुपये से कम की ठगी के मामलों में अदालत के आदेश के बगैर ही रिफंड दिया जा सकता है।

नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो (एनसीआरबी) के आंकड़ों के अनुसार, 2021 से 2023 के बीच लगभग 2.05 लाख साइबर अपराध के मामलों में एफआईआर दर्ज हुई, जबकि केंद्रीय गृह मंत्रालय की हेल्पलाइन में 2022 से 2024 के दौरान लगभग 48.93 लाख मामले दर्ज किए गए। गृह मंत्रालय के आईफोरसी के आंकड़ों के मुताबिक, पिछले छह सालों में भारतीयों के 52,976 करोड़ रुपये साइबर अपराध में ठगे गए हैं।

हकीकत यह है कि करोड़ों लोगों के साथ खरबों रुपयों की साइबर धोखाधड़ी हो रही है, पर ऐसे अनेक मामलों में एफआईआर तक दर्ज नहीं हो पाती। ऐसे में, असली अपराधी पुलिस की गिरफ्त से बाहर रहते हैं। नए आपराधिक कानूनों के अनुसार साइबर अपराध से जुड़े सभी मामलों में एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। इससे समस्या की विकरालता का पता चलने के साथ ठगी के मामलों को रोकने और लोगों को रकम वापसी के प्रयास तेज हो सकेंगे।

edit@amarujala.com

जीवन धारा

माता अमृतानंदमयी

जैसे कोई फिल्म देखते समय हम जानते हैं कि यह केवल फिल्म है, तभी उसका आनंद ले पाते हैं, उसी तरह जीवन को भी एक दिव्य लीला की तरह देखें। उससे पहचान न बनाएं, बल्कि उसे समझें।

जीवन के हर पल का आनंद उठाएं

जीवन का सबसे गहन और मूल्यवान पाठ यही है कि संसार में रहते हुए भी उससे बंधना नहीं है। कर्म करें, पर कर्म का बोझ न ढोएं। जीवन में हम सबको कर्म करना है, पर यह भी ध्यान रहे कि हमें उससे बंधे नहीं रहना है। जो भी करना है, उसे पूरे प्रेम और समर्पण से करें, फिर उसे ईश्वर को अर्पित कर आगे बढ़ जाएं। एक कर्म पूरा हुआ, तो उसे छोड़ दें। दूसरा आया, उसे अपनाएं, पर उससे चिपके न रहें। जीवन यात्रा में अतिरिक्त बोझ रास्ते को कठिन बना देता है, ठीक उसी तरह अनावश्यक इच्छाएं, असंयमित सपने और मोह हमारी आत्मा को थका देते हैं।

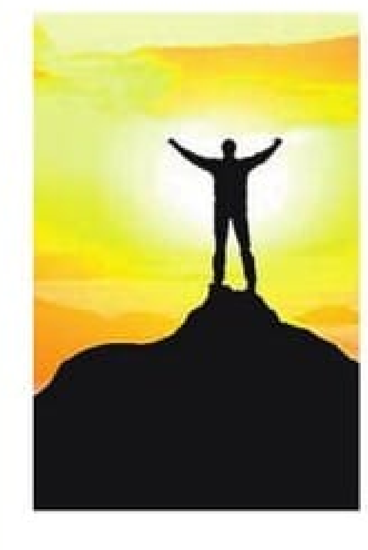

इतिहास साक्षी है कि बड़े-बड़े राजा और विजेता भी अंत समय में शांति नहीं पा सके, क्योंकि उन्होंने जीवन भर धन, सत्ता, संबंधों, और सबसे बढ़कर अहंकार का संग्रह किया। सिकंदर महान ने संसार का बड़ा भाग जीत लिया, पर मृत्यु के सामने वह भी विवश था। उसकी अंतिम इच्छा थी कि ताबूत में दोनों ओर छेद बनाकर उसके दोनों हाथ बाहर निकाले जाएं और हथेलियां खुली रखी जाएं, ताकि संसार देख सके कि जो सारे विश्व पर कब्जा जमाना चाहता था, संसार से खाली हाथ विदा ले रहा है। वह अपना शरीर भी साथ न ले जा सका। इसलिए, मृत्यु के द्वार पर वही व्यक्ति शांत होता है, जिसने जीवन में निर्लिप्तता, यानी सांसारिक मोहमाया से दूर रहने की कला सीख ली हो। जीवन भर जो कुछ भी हम कमाते हैं, वह यहीं छूट जाता है। जब यह शरीर ही साथ नहीं जाता, तो फिर किसी चीज की लालसा रखने का क्या अर्थ है? निर्लिप्तता जीवन से भागना नहीं, बल्कि जीवन को सही दृष्टि से देखना है। लिप्तता मन पर भार डालती है, निर्लिप्तता उस भार को उतार देती है। जितना बोझ बढ़ता है, उतना ही तनाव बढ़ता है और जितना बोझ उतरता है, उतनी ही शांति गहराती है। निर्लिप्तता अपने आप नहीं आती, उसके लिए जागरूकता चाहिए। जागरूकता से संकल्प जन्म लेता है, और संकल्प से आंतरिक स्वतंत्रता।

आज मनुष्य का मन नकारात्मक विचारों से भरा है, इसलिए भीतर कहीं न कहीं मुक्ति की पुकार भी है। हम सब यात्री हैं। जैसे रेल या बस में मिलने वाले सहयात्री हमारे साथ कुछ दूर तक ही होते हैं, वैसे ही जीवन में मिलने वाले लोग, स्थान और परिस्थितियां भी। प्रेम करें, सीखें, उसे बांटें, पर यह भी स्मरण रहे कि एक दिन इस दुनिया से विदा होना ही है। जब यह स्मृति भय नहीं, बोध बन जाए, तो हर क्षण आपको सही दिशा दिखाएगी। जब आप सच में अनासक्त होते हैं, तो जीवन ही नहीं, मृत्यु के भी साक्षी बन जाते हैं।

जैसे कोई फिल्म देखते समय हम जानते हैं कि यह केवल फिल्म है, तभी उसका आनंद ले पाते हैं, उसी तरह जीवन को भी एक दिव्य लीला की तरह देखें। उससे पहचान न बनाएं, बल्कि उसे समझें।

त्याग करना सीखें

सूत्र

संसार एक रंगमंच है, जहां हमें केवल अपना सर्वश्रेष्ठ अभिनय करना है, कहानी का नायक नहीं बनना। जब हम कर्म को कर्तव्य मानकर ईश्वर को सौंप देते हैं, तो चित्त भारी नहीं होता। संग्रह अहंकार को बढ़ाता है, जबकि त्याग आत्मा को शुद्ध करता है। इसलिए, अपनी ऊर्जा वस्तुओं को बटोरने में नहीं, बल्कि स्वयं को जानने में लगाएं।

दूसरा पहलू

पत्तियां पेड़ की रसोई भी होती हैं। सूरज की रोशनी को पेड़ों के लिए भोजन में बदलने का काम यही करती हैं।

पेड़ से क्यों गिरती हैं पत्तियां

क्या आपने कभी सोचा है कि पेड़ अपनी उन पत्तियों को क्यों गिरा देते हैं, जो उनका भोजन बनाती हैं। दरअसल, पत्तियां केवल पेड़ का एक हिस्सा भर नहीं होतीं, वे उसकी रसोई भी होती हैं। सूरज की रोशनी को पेड़ों के लिए भोजन में बदलने का काम पत्तियां ही करती हैं। लेकिन इस प्रक्रिया के लिए पानी जरूरी है, जो मिट्टी से जड़ों तक और फिर तने-टहनियों की महीन नलिकाओं से होकर पत्तियों तक पहुंचता है। ऊंचे पेड़ों के लिए यह यात्रा किसी लंबी चढ़ाई से कम नहीं होती।

मटिल्डा ब्राउन

जब पत्तियों का काम पूरा हो जाता है, तो पेड़ उन्हें थामे नहीं रखता। नतीजतन, पत्तियां जमीन पर गिर जाती हैं।

जब पानी की कमी होती है, तो पत्तियां अपना काम ठीक से नहीं कर पातीं। ऐसे में पेड़ पत्तियों में मौजूद पोषक तत्वों को वापस अपने तने और जड़ों में खींच लेता है, ताकि कुछ भी व्यर्थ न जाए। जब पत्तियां अपना काम पूरा कर देती हैं और भीतर से खाली हो जाती हैं, तो पेड़ उन्हें थामे नहीं रखता। नतीजतन, पत्तियां जमीन पर गिर जाती हैं या हवा के झोंके में उड़ जाती हैं। इस तरह उन्हें रीसाइकल किया जा सकता है। कुछ पेड़ हर साल अपनी पत्तियां गिराते हैं। इन्हें पर्णपाती पेड़ कहा जाता है। ये आमतौर पर उन इलाकों में पाए जाते हैं, जहां सर्दियां ठंडी और बर्फीली होती हैं। ठंड में पेड़ के भीतर का पानी जम सकता है, जिससे पत्तियां नष्ट हो जाती हैं। इसलिए मौसम बदलते ही पेड़ पहले से तैयारी कर लेते हैं और पोषक तत्व बचाकर पत्तियां गिरा देते हैं। दिलचस्प बात यह है कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में भी पर्णपाती पेड़ होते हैं, जहां ठंड नहीं पड़ती। वहां सर्दी का मतलब होता है-सूखा। जब बारिश रुक जाती है और पानी की कमी होने लगती है, तो पेड़ अपनी पत्तियां गिरा देता है।

कभी-कभी पेड़ के लिए पत्तियों को छोड़ देना ही बेहतर होता है। पेड़ अच्छी चीजों को बचाकर रखते हैं और पर्याप्त पानी होने पर उसका इस्तेमाल करके बिल्कुल नए पत्ते उगा सकते हैं।

ऐसे समय में पेड़ खाना बनाने के बजाय, आराम करता है। जैसे भालू सर्दियों में शीतनिद्रा में चला जाता है और पूरी सर्दी सोता रहता है, वैसे ही पेड़ भी लंबी नींद में चले जाते हैं। यह नींद तब तक रहती है, जब तक तनों की नलिकाओं में पानी फिर से बहना शुरू नहीं हो जाता। यह वसंत ऋतु में हो सकता है या तब, जब बारिश शुरू होती है। तब पेड़ जागता है और नए पत्ते निकालता है, ताकि वह फिर से भोजन बना सके। कुछ पेड़ साल भर हरे-भरे रहते हैं-इन्हें सदाबहार पेड़ कहा जाता है। पर उनकी पत्तियां भी हमेशा नहीं रहतीं। पुरानी, खराब या जानवरों द्वारा चबाई गई पत्तियां अंततः गिर जाती हैं, क्योंकि वे अपना काम सही से नहीं कर पाती हैं।

बेशक, पत्तियां पेड़ के लिए अनमोल होती हैं, लेकिन कभी-कभी पेड़ के लिए उन्हें छोड़ देना ही बेहतर होता है। ऐसे में, पेड़ अच्छी चीजों को बचाकर रखते हैं और पर्याप्त पानी होने पर उसका इस्तेमाल करके बिल्कुल नए पत्ते उगा सकते हैं। - द कन्वर्सेशन से

आंकड़े

ऐतिहासिक उपलब्धि

भारत ने विदेश व्यापार में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की और पिछले वर्ष वस्तुओं व सेवाओं का कुल निर्यात 825.25 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर तक पहुंचाया।

अमेरिका	11.40
चीन	11.01
यूएई	8.63
रूस	5.93
सऊदी अरब	3.61

आंकड़े वर्ष 2024-25 में देशों को होने वाले निर्यात के, प्रतिशत में। स्रोत : वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

श्रीहरि ने नारद मुनि को समझाया कि संत को अहंकारी नहीं होना चाहिए। एक तपस्वी के मन में सांसारिक आकर्षण का जागना साधना के मार्ग से विचलन है।

संत और अहंकार

अंतर्यात्रा
संकलित

पौराणिक मान्यता के अनुसार, एक बार विश्वमोहिनी नामक अत्यंत रूपवती राजकुमारी का स्वयंवर रचा गया। उसके दिव्य सौंदर्य को देखकर देवर्षि नारद की उससे विवाह करने की इच्छा हुई। वह श्रीहरि विष्णु के पास पहुंचे और प्रार्थना की कि उन्हें भी ऐसा अनुपम सौंदर्य प्रदान किया जाए, जिससे राजकुमारी उन्हें वर चुन सकें।

नारायण ने अपनी लीला के जरिये नारद जी को वानर रूप प्रदान किया, किंतु नारद मुनि को इसका तनिक भी आभास न हुआ और उसी रूप में वह स्वयंवर में जा पहुंचे। जब वरमाला का समय आया, तो राजकुमारी ने नारद जी को अनदेखा कर भगवान विष्णु के गले में वरमाला डाल दी। यह देखकर नारद मुनि क्रोधित हो उठे और उन्होंने भगवान विष्णु को स्त्री-वियोग का श्राप दे दिया तथा कठोर वचन कहे।

जब नारद मुनि का क्रोध शांत हुआ, तब भगवान विष्णु ने इस लीला का मर्म प्रकट किया। उन्होंने समझाया कि नारद मुनि, आपके भीतर अहंकार का बीज अंकुरित हो गया था, जबकि एक संत के लिए अहंकार का कोई स्थान नहीं होता। स्वयंवर और राजकुमारी, दोनों मेरी ही माया के रूप थे, और एक तपस्वी के मन में सांसारिक आकर्षण का जागना साधना के मार्ग से विचलन है।

यह सत्य सुनकर नारद मुनि को अपनी चूक का गहन बोध हुआ। उन्होंने प्रभु के चरणों में नतमस्तक होकर क्षमा याचना की और चक्रपाणि का आभार व्यक्त किया।

अमर उजाला

पुराने पन्नों से — 19 जनवरी, 1956

देहातों में स्वयंसेवक सेना गठित होगी

देहातों में स्वयं सेवक सेना संगठित होगी
गांवपंचायतों की सहायता करेगी
उत्तर प्रदेश सरकार का महत्वपूर्ण कदम

ग्रामीण गणतंत्र व्यवस्था को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार एक और महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। वह देहातों के लिए एक बड़ी स्वयंसेवक सेना खड़ी कर रही है। इस सेना में देहात के 45 वर्ष तक के जवान भर्ती हो सकेंगे।

सड़क सुरक्षा बने एक जन आंदोलन

सड़क सुरक्षा लंबे समय से उपेक्षित विषय रहा है। अब जरूरी है कि सड़क सुरक्षा को हर सड़क, हर शहर और हर गांव तक पहुंचाया जाए।

सुभाष नागपाल

मुद्दा

आचार्य दीप चंद भारद्वाज के अनुसार, सूर्य के उत्तरायण होने का प्रतीकात्मक अर्थ है-अंधकार से प्रकाश की ओर यात्रा। सड़क दुर्घटनाओं के संदर्भ में हम इसे वर्षों से छाया घना कोहरा छंटने की शुरुआत मान सकते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा दिसंबर, 2025 में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ की गई सड़क-सुरक्षा समीक्षा बैठक इस बात का स्पष्ट संकेत है कि अब सड़क सुरक्षा को केवल औपचारिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि परिणाम-आधारित मिशन के रूप में आगे बढ़ाया जाएगा।

सड़क दुर्घटनाओं की लगातार बढ़ती संख्या यह बताती है कि वर्तमान स्थिति में समस्त प्रदेश की सरकारों को कड़े प्रयास करने होंगे। जागरूकता, एवं सड़क इंजीनियरिंग से पहले एक कुशल सरकार ही सुरक्षा, नियमों का पालन, उसके लिए प्रशासन की प्रतिबद्धता, एवं जवाबदेही और सड़क सुरक्षा कार्यक्रमों की सफलता सुनिश्चित कर सकती है। इसके लिए एक ठोस एक्शन

प्लान तैयार किया जाना जरूरी है, जिसमें उठाए जाने वाले प्रत्येक कदम, संबंधित विभागों की जिम्मेदारी और समयसीमा स्पष्ट रूप से निर्धारित हों। सरकार का पहला मिशन यह होना चाहिए कि सभी नागरिकों को यातायात नियमों की स्पष्ट जानकारी हो। इसके लिए सड़क पर यातायात चिह्नों, लेन चिह्नांकन, जेब्रा क्रॉसिंग और गति-सीमा का स्पष्ट उल्लेख हो, और उनका बराबर रख-रखाव किया जाए। सड़कों पर नियमित अंतराल पर यह अंकित किया जाए कि कौन-सी लेन किस प्रकार के वाहनों के लिए है। सड़क पर तैनात कर्मचारियों को समय-समय पर यातयात नियमों का प्रशिक्षण और उनसे जुड़ी नई जानकारियां देना अनिवार्य है। एक्शन प्लान के पहले छह से 12 महीनों में प्रवर्तन पर विशेष बल दिया जाए। दुर्घटना के मुख्य कारणों जैसे-तेज गति, गलत दिशा में ड्राइविंग व मोबाइल फोन के प्रयोग आदि पर प्राथमिकता से कार्रवाई हो। गंभीर उल्लंघन के मामलों में किसी भी प्रकार की ढिलाई न बरती जाए। चालानों का विवरण घटनास्थल पर 'डेट एंट्री' की जाए, ताकि दोबारा उल्लंघन करने वालों के लाइसेंस समाप्त करने जैसी सख्त कार्रवाई की जा सके। तकनीकी प्रणालियों और यातायात प्रबंध प्रणाली की क्षमताओं का पूर्ण उपयोग हो।

ट्रैफिक पुलिस और आरटीओ पर पूरा बोझ डालना व्यावहारिक नहीं है। मुख्यमंत्री के सुझावानुसार, उनकी सहायता के लिए, पुलिस कर्मी के संरक्षण में, होमगार्ड, डिफेंस कर्मी और शिक्षित बेरोजगार युवाओं को जोड़ा जाए। इनमें महिलाओं की पर्याप्त भागीदारी भी सुनिश्चित की जाए। इन्हें 'रोड सेफ्टी एंबेसडर' के रूप में पहचान और सम्मान दिया जाए। आरटीओ और ट्रैफिक पुलिस विभाग में सड़क सुरक्षा से जुड़े अलग अनुभाग बनाए जाएं। इनके लिए अलग से सरकारी कर्मी, संसाधन और स्पष्ट दायित्व तय हों। उनके लिए चालान या राजस्व नहीं, बल्कि दुर्घटनाओं में कमी लाना मुख्य लक्ष्य बनाया जाए। सड़क या उसके आसपास की किसी भी ऐसी स्थिति, जिससे दुर्घटना की आशंका बढ़ती हो, के लिए व्यक्तियों/विभागों की स्पष्ट जिम्मेदारी तय की जाए। घने और तेज यातायात वाले क्षेत्रों में पैदल यात्रियों के लिए संकेत लाइटें (पेडेस्ट्रियन लाइट) लगाई जाएं, और सुरक्षित पार पथ बनाए जाएं। स्थानीय स्तर पर नियमित सड़क नियम जागरूकता, और सुरक्षित ड्राइविंग प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जाएं। इनमें कॉलोनियों, पंचायतों, नगर पालिकाओं, आवासीय समितियों, गैर-सरकारी संस्थाओं, सरकारी कार्यालयों और निजी संस्थानों की भागीदारी सुनिश्चित हो। इसमें पंजीकृत ड्राइविंग स्कूल की सेवाएं भी ली जा सकती हैं। इसके अलावा, जिला स्तर पर एक नोडल अधिकारी नामित किया जाए, जो विभागों के बीच समन्वय स्थापित कर समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करे। इसके कार्यान्वयन की नियमित समीक्षा भी हो। स्थानीय समाचार पत्रों और सोशल मीडिया के माध्यम से हर माह की गई कार्रवाइयों, अच्छे सड़क व्यवहार के उदाहरणों और जुर्माने की जानकारी जनता तक पहुंचाई जाए। इसी क्रम में व्यावहारिक नवाचार एवं सड़क सुरक्षा के समाधान भी आमंत्रित किए जाएं। इससे आम नागरिकों में जागरूकता, कानून के प्रति सम्मान, एवं सड़क-सुरक्षा अभियान में भागीदारी बढ़ेगी।

सड़क सुरक्षा लंबे समय से उपेक्षित विषय रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यह अवसर है कि इसे जन आंदोलन का रूप दिया जाए। प्रशासनिक इच्छाशक्ति और नागरिक सहभागिता के साथ सड़क सुरक्षा को हर सड़क, हर शहर और हर गांव तक पहुंचाया जा सकता है। यह आवश्यक होगा कि शासन स्तर पर नामित एक वरिष्ठ अधिकारी या मंत्री की पूरे सड़क सुरक्षा प्रोग्राम के प्रति अकेली जिम्मेदारी हो। मुख्यमंत्री का राज्य की जनता को संबोधन (योगी की पाती, 12 जनवरी, 2026) शासन की इस विषय पर सतत् निगरानी का स्पष्ट आश्वासन है। सड़क सुरक्षा की अपेक्षित दशा, और उत्तर प्रदेश में अच्छे परिणामों के बीच का फासला वास्तव में ज्यादा लंबा नहीं है।

- लेखक नेशनल रोड सेफ्टी काउंसिल के सदस्य हैं।

हिन्दुस्तान
1936
सत्य • सार्थक • सदैव

तेज हो गए रोबोट

रोबोट की दुनिया में तरक्की फिर तेज हो गई है। मानवीकृत रोबोट की मांग बढ़ी है, तो रोबोट के बढ़ते इस्तेमाल की आलोचना भी शुरू हो गई है। रोबोटिक्स या रोबोट विज्ञान की तरक्की प्रशंसनीय है और इस पर चीन में नहीं, अमेरिका में विरोध के स्वर मुखर हो रहे हैं। सीनेटर बर्नी सैंडर्स ने आपत्ति जताते हुए कहा है कि अलबामा में रोबोट द्वारा अल्ट्रासाउंड करना अच्छा नहीं है। यह मामला व्हाइट हाउस भी पहुंचा है। वास्तव में, अमेरिका में चिकित्सा क्षेत्र में काम करने वालों की कमी हो गई है या वह बहुत महंगे हो गए हैं। ऐसे में, अल्ट्रासाउंड जैसा काम रोबोट करने लगे हैं। अमेरिका में दिग्गज नेताओं को भी यह लगता है कि रोबोट अगर इलाज में भागीदारी करेंगे, तो मानवीयता खतरे में पड़ जाएगी। हालांकि, इसमें कोई दोराय नहीं कि जहां भी संभव होगा, वहां रोबोट के बढ़ते इस्तेमाल को रोकना मुमकिन नहीं होगा।

बहरहाल, रोबोटिक्स की तरक्की चीन में सबसे तेज है। पिछले तीन महीनों से बड़े पैमाने पर ह्यूमनॉइड या मानवीकृत रोबोट बनाने की योजनाएं घोषित हो रही हैं। ह्यूमनॉइड रोबोट की क्षमताओं में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है, जिसका श्रेय सस्ते पुर्जों, बेहतर बैटरी क्षमता और कृत्रिम बुद्धिमत्ता एल्गोरिदम जैसे नवाचारों को जाता है। चीनी कंपनी यूबीटेक ने दुनिया में पहली बार बड़े पैमाने पर ह्यूमनॉइड रोबोट की डिलीवरी की है। वॉकर एस2 मॉडल के 1,000 से अधिक ह्यूमनॉइड रोबोट 2025 में कारखानों में काम करने के लिए भेजे गए हैं। चांदी जैसे सफेद रंग का यह ह्यूमनॉइड रोबोट खुद चल सकता है। किसी वस्तु को पकड़कर एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकता है। शुरुआती चरण में सफलता मिल रही है, लेकिन यह देखना बाकी है कि क्या ह्यूमनॉइड रोबोट कंपनियों का समय या पैसा बचा रहे हैं? हां, इतना तो तय है कि ह्यूमनॉइड्स एक दशक पहले की तुलना में इस सपने के कहीं अधिक करीब हैं, इसका श्रेय उन सघन बैटरियों को जाता है, जो रोबोट को मिनटों के बजाय घंटों तक ऊर्जा प्रदान करती हैं। ह्यूमनॉइड का प्रयोग कार कारखानों में सफल हो रहा है। बोस्टन डायनेमिक्स और टेस्ला सहित कुछ अमेरिकी रोबोटिक्स डेवलपर अपनी मूल कंपनी के औद्योगिक संयंत्रों में ह्यूमनॉइड रोबोट के पायलट प्रोजेक्ट चला रहे हैं। अनेक तरह के कार्य रोबोट अब करने लगे हैं, लेकिन दो क्षेत्रों में चुनौती आ रही है। किसी भी रोबोट में सीमित डाटा होता है और उसके अनुरूप उसके काम भी सीमित होते हैं। दूसरी चुनौती, रोबोट को सामान्य कार्यबल का हिस्सा बनाना है। एक मनुष्य हजारों क्रियाओं को अंजाम देते हुए खड़ा रहता है, पर ऐसा करने में रोबोट को अभी सक्षम बनाया जा रहा है। विशेषज्ञ मानते हैं कि आने वाला समय रोबोटिक्स का होगा और इसमें एआई की वजह से तरक्की तेज होती चली जाएगी।

ह्यूमनॉइड रोबोट की क्षमताओं में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है, जिसका श्रेय सस्ते पुर्जों, बेहतर बैटरी क्षमता और कृत्रिम बुद्धिमत्ता एल्गोरिदम जैसे नवाचारों को जाता है।

वैश्विक रोबोटिक्स बाजार में तेज वृद्धि हो रही है, जिसका मूल्य 2025-26 में लगभग 50-88 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। भारत के रोबोटिक्स बाजार का आकार 2025 में 1.98 अरब अमेरिकी डॉलर था। यह 2034 तक 7.38 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच जाएगा। दुनिया में पचास लाख के करीब रोबोट सेवा दे रहे हैं और भारत में करीब दस हजार रोबोट काम में लगे हैं। रोबोटिक्स में भारत छठे या सातवें स्थान पर आता है। यहां 180 से ज्यादा कंपनियां रोबोटिक्स पर काम कर रही हैं, पर मानवीकृत रोबोट बनाने में लगी करीब दस कंपनियों पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। भारत में काम करने वाले इंसानों की कोई कमी नहीं है, लेकिन हमें रोबोटिक्स पर जरूर काम करना चाहिए।

हिन्दुस्तान | 75 साल पहले
19 जनवरी, 1951

चीन का उत्तर

संयुक्त राष्ट्र संघ की राजनीतिक समिति ने कोरिया में युद्ध बन्द करवाने और दूर पूर्व की समस्याओं को हल करने के लिए एक पंचसूत्री योजना स्वीकार की थी। यह योजना पेकिंग सरकार को भेज दी गई थी और उससे अनुरोध किया गया था कि वह अपनी प्रतिक्रिया जल्दी से जल्दी सूचित करे।

चीन के विदेश मंत्री श्री चौ एन लाई ने इस योजना पर अपनी सरकार की प्रतिक्रिया संयुक्त राष्ट्र संघ को भेज दी है। चीन के उत्तर से यह तो स्पष्ट ही है कि उसने संयुक्त राष्ट्र संघ की योजना को ज्यों का त्यों स्वीकार नहीं किया है। चीन को यह बात स्वीकार नहीं है कि पहले कोरिया में युद्ध विराम हो और उसके बाद कोरिया और दूर पूर्व की शेष समस्याओं को हल करने के लिए बातचीत की जाये। यद्यपि चीन ने यह स्वीकार किया है कि... उसके दिल में यह शंका... है कि अमरीका कोरिया में युद्ध विराम इसलिए चाहता है कि अमरीकी फौजों को सांस लेने का अवसर मिल जाये और एक बार युद्ध विराम हो जाने के बाद समझौते की बातचीत लम्बी पड़ जायेगी तथा कोई समस्या हल नहीं हो सकेगी। इस सम्भावना को निर्मूल करने के लिए चीन की मांग है कि पहले समझौते की बातचीत हो ले और उसके बाद कोरिया में लड़ाई अपने आप बन्द हो जायेगी।

चीन ने कुछ सुझाव संयुक्त राष्ट्र संघ को भेजे हैं। उसका पहला सुझाव तो यह है कि समझौते की बातचीत इस आधार पर शुरू की जाये कि तमाम विदेशी फौजों को कोरिया से हटा लिया जायेगा और कोरिया का आन्तरिक प्रश्न स्वयं कोरिया के लोगों पर छोड़ दिया जायेगा। दूसरे, समझौते की बातचीत के विषयों में फारमोसा और उसके आसपास से अमरीकी फौजों को हटाने का प्रश्न और दूर पूर्व की अन्य समस्याओं का समावेश होगा। तीसरे, बातचीत में चीन गणराज्य, रूस, ब्रिटेन, अमरीका, फ्रांस, भारत और मिस्र को शामिल किया जायेगा और चीन गणराज्य का संयुक्त राष्ट्र संघ में उचित स्थान मान लिया जायेगा।

चौथे, संयुक्त राष्ट्र संघ में चीन गणराज्य के कानूनी दर्जे के बारे में सात राष्ट्रों का उपरोक्त सम्मेलन फैसला करेगा। पांचवें, सात राष्ट्रों का सम्मेलन चीन में बुलाया जायेगा।

सोने के गहने क्या सपना बन जाएंगे

आलोक जोशी | वरिष्ठ पत्रकार

यहां स्कैन करें

जौहरी भी चिंतित हैं कि क्या करें? वे कुछ वर्षों से हल्के गहने बनाने लगे हैं। 'वन ग्राम गोल्ड ज्वेलरी' इसी का एक रूप है, ताकि लोग कम खर्च में भी शौक पूरे कर सकें।

हिंदू मान्यताओं में धनतेरस के दिन घर के लिए कुछ खरीदना शुभ माना जाता है। साधन-संपन्न लोग इस दिन सिर्फ बर्तन खरीदकर शगुन पूरा नहीं करते, बल्कि सोना या चांदी खरीदते हैं। दीपावली पर लक्ष्मी पूजन के लिए भी चांदी के सिक्के खरीदने का प्रचलन रहा है। यही वजह है, उस समय सोने-चांदी के दाम तेज हो जाते हैं। जिन लोगों को जल्दी नहीं होती, वे इंतजार करते हैं कि त्योहार के बाद बाजार मंदा होगा, तब गहने या सोना-चांदी खरीदेंगे। इस बार ऐसा सोचने वाले लोग हाथ मलते रह गए, बल्कि अभी तक मल रहे हैं।

धनतेरस के दिन दस ग्राम सोना 1,32,400 रुपये का था, वहीं एक किलो चांदी 1,70,000 रुपये की थी। बीते शुक्रवार को दिल्ली के सर्राफा बाजार में दस ग्राम सोने का भाव 1,43,760 रुपये था। धनतेरस से करीब 11,000 रुपये ऊपर। इस बीच चांदी एक नया पहाड़ चढ़ चुकी है। दुनिया के बाजारों में नरमी के बावजूद एक किलो चांदी 2,95,000 रुपये की हो चुकी थी। धनतेरस से करीब 60 प्रतिशत ऊपर। सवाल है, आगे क्या होगा? सोने-चांदी में तेजी का यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा या उस पर ब्रेक लगेगा?

इन सवालों पर विद्वानों में मतभेद है। मतभेद से ज्यादा अनिश्चय की स्थिति दिखती है। दरअसल, कोरोना के बाद से, खासकर पिछले एक साल में दोनों कीमती धातुओं ने जिस तरह की छलांग लगाई है, उसकी कल्पना या भविष्यवाणी किसी ने नहीं की थी। शायद इसीलिए आज भी कोई साफ राय सामने नहीं आ रही है। यह आर्थिक विशेषज्ञों या उन लोगों के बीच सोच-विचार का विषय है, जो चांदी-सोने को निवेश या सट्टेबाजी की नजर से देखते हैं, लेकिन जरा उन लोगों की सोचिए, जिनके घरों की रौनक ही सोने-चांदी से होती रही है। शादी-ब्याह जैसा जश्न हो या फिर तीज-त्योहार, घर की महिलाओं की सजावट में इन दोनों की अहम भूमिका है।

पूरे भारत में सोने-चांदी का इस्तेमाल अधिकतर आभूषणों या पारिवारिक संपत्ति के रूप में ही होता रहा है। हां, यह बात भी साथ में जुड़ी रही है कि अगर कोई मुसीबत आ पड़ी, तो यही गहने या बर्तन बेचकर या गिरवी रखकर पैसे का इंतजाम किया जा सकता है। वैसे, इनको बेचना आम तौर पर अच्छा नहीं माना जाता। भारत की क्यों, अंग्रेजों तक में 'सेलिंग द फैमिली सिल्वर' काफी खराब अर्थों में इस्तेमाल होता है, यानी नालायक औलाद पुरखों की कमाई हुई संपत्ति बेचकर गुजारा करती है।

ऐसे में, सोने-चांदी की तेजी ने अनगिनत परिवारों को चिंता में डाल दिया है। जो महिलाएं घर खर्च में से थोड़ा-थोड़ा पैसे बचाकर पायल, बिछिया, बाली या अंगूठी जैसी चीजें जमा करती हैं; जिन घरों में शादी-ब्याह जैसे आयोजन होने वाले हैं या जो भविष्य में न जाने कब होने वाले किसी मांगलिक कार्य के लिए बचत करने में जुटे हैं कि वे उस वक्त गहने खरीदेंगे, इन सबकी फिक्र का अंदाजा लगाना मुश्किल है।

एक मित्र हैं। शेयर बाजार और निवेश से जुड़े विषयों का विश्लेषण करते हैं, राजनीति पर भी चर्चा करते हैं। कई साल पहले बाजार में घूमते वक्त उन्हें एक सोने की चेन पसंद आ गई। अस्सी ग्राम की चेन थी, 75,000 रुपये के आसपास की मिल गई। अब अंदाजा लगाइए कि आज उनके गले से कितनी बड़ी संपत्ति लिपटी हुई है? फर्ज कीजिए, किसी के पास तब इतने पैसे न हों और उसने सोचा था कि कुछ साल बचत करके वह ऐसी चेन खरीदेगा। आज वह इसी चेन का कौन सा हिस्सा खरीद पाता? सवाल है, ऐसे ही चलता रहा, तो क्या आम भारतीय परिवार को अपनी प्रथाएं और परंपराएं बदलनी पड़ेंगी? क्या आम आदमी को सोने-चांदी के गहनों का ख्याल दिल से निकाल देना चाहिए या इनके दाम कम होने की कोई उम्मीद बाकी है?

जवाब बहुत दूर नहीं हैं। सन् 1950 में दस ग्राम सोना 99 रुपये का था, बीच में 120 रुपये तक चढ़ने और 63 रुपये तक गिरने के बाद 1975 में यह 540 रुपये का हुआ और सन् 2000 में 4,400 रुपये का था। वहां से यहां तक का सफर तो आपके सामने है। बीच-बीच में दाम में गिरावट भी आती रही, पर पिछले 25 वर्षों में सोना जबर्दस्त छलांग लगा चुका है। निवेशकों की भाषा में कहें, तो लंबी रेस का घोड़ा है यह। महंगाई बढ़ने के साथ भी सोना बढ़ता है और देश की मुद्रा कमजोर होने के साथ भी। चांदी भी उसके साथ ही चलती थी, मगर इधर निवेशकों की नजर भी चांदी पर मेहरबान हो गई है और उसका औद्योगिक इस्तेमाल भी बहुत बढ़ गया है। इसी कारण चांदी सोने से ज्यादा तेजी से भाग रही है।

ऐसे में, जौहरी और सर्राफा व्यापारी भी चिंतित हैं कि क्या करें? पिछले कई साल से वे हल्के गहने बनाने में जुटे हैं। 'वन ग्राम गोल्ड ज्वेलरी' इसी का एक रूप है, ताकि इंसान कम खर्च में भी अपने शौक पूरे कर सके। इसी तरह, बहुत से बड़े आभूषण निर्माता ईएमआई स्कीम भी चलाने लगे हैं, जिसमें ग्राहक पहले पैसा जमा करते हैं और आखिर में उन्हें आभूषण मिल जाते हैं। इस तरह के नुस्खों के अलावा बुजुर्गों की पुरानी सीख भी कारगर है। आधुनिक 'फाइनेंशियल प्लानर' भी यही सलाह दे रहे हैं कि अपनी जरूरतों का हिसाब पहले लगाकर उस हिसाब से योजना बनाएं। जब गहनों की जरूरत पड़ने वाली हो, उसके काफी समय पहले से धीरे-धीरे सोना खरीदकर जमा करते रहें।

दाम बढ़ने का बजट पर, गहनों के वजन पर और खरीदारी पर असर पड़ना तो स्वाभाविक है। इससे निपटने के लिए खरीदार और बिकवाल तरह-तरह की कोशिशें भी करते रहेंगे, लेकिन तेज गिरावट की उम्मीद में बैठे रहना महंगा पड़ सकता है। हां! अगर पहले से तैयारी कर रखी हो, तो फिर गिरावट का फायदा जरूर उठाया जा सकता है। इस वक्त सोने के दाम में गिरावट का सबसे बड़ा संकेत अमेरिका से आएगा। हालांकि, ईरान पर ट्रंप के बयान में कुछ नरमी आई है, लेकिन वह काफी नहीं है।

इसमें बड़ी गिरावट के लिए जरूरी है कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था में मजबूती दिखे, वहां महंगाई काबू में आती दिखे और ब्याज दरें घटाने का सिलसिला रुके या फिर ब्याज दरें बढ़ने के आसार बनें। सोने से ज्यादा मुश्किल है, अब चांदी में गिरावट, क्योंकि सोने की तेजी के सारे कारणों के अलावा चांदी में तेजी की बड़ी वजह इसकी औद्योगिक खपत और ईटीएफ निवेश की मांग में आया तेज उछाल है। इन दोनों के कम होने के फिलहाल कोई आसार नहीं दिखते।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

हर बार औरतों के हाथ रहा ईरानी इंकलाब का परचम

सुहेल वहीद | वरिष्ठ पत्रकार

यहां स्कैन करें

ईरान में 1979 में जब इस्लामी क्रांति ने दस्तक दी और आयतुल्लाह खुमैनी पेरिस से तेहरान पहुंचे, तब उनके स्वागत में ईरानी औरतें आगे-आगे थीं। इन्हीं औरतों ने शाह पहलवी के खिलाफ जबर्दस्त प्रदर्शन किए थे। अब वही औरतें उसी मजहबी सत्ता के खिलाफ जंग लड़ रही हैं। ईरान के मौजूदा हालात के पसमंजर में हिजाब के खिलाफ शुरू हुए आंदोलन का बड़ा हाथ है, जो सितंबर 2022 में महसा अमीनी के कत्ल के बाद से ईरान ही नहीं, विदेशों में भी फैल गया था।

ईरान में लगातार उस आंदोलन का दमन किया जाता रहा, पर वह रह-रहकर उभर आता है। नवंबर 2024 में तेहरान यूनिवर्सिटी में एक छात्रा हिजाब के खिलाफ इतनी गुस्से में आ गई कि वह अपने पूरे कपड़े उतारकर कैंपस में घूमने लगी थी। हिजाब, महिला अधिकार और मानव अधिकारों के हनन के खिलाफ जद्दोजहद के लिए पूर्व अभिनेत्री और इंजीनियर नरगिस मोहम्मदी करीब 13 साल जेल में गुजार चुकी हैं, उन्हें साल 2023 में शांति के नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था।

ईरान में जब कभी कोई आंदोलन हुआ या क्रांति आई, उसमें ईरानी औरतों ने जबर्दस्त रोल अदा किया है। 1979 के 'इस्लामी इंकलाब' के लिए भी ईरानी औरतों ने गोलियां खाई थीं। इस ऐतिहासिक घटना के करीब आठ साल पहले विख्यात लेखिका पद्म विभूषण कुर्रतुल ऐन हैदर ईरान गई थीं और वापस आने के बाद उन्होंने एक शानदार रिपोर्ताज *कोहे दमावंद* लिखा। उसमें उन्होंने उस वक्त के शाही ईरान का बड़ा उम्दा मंजरनामा पेश किया है। ज्ञानपीठ से सम्मानित कुर्रतुल ऐन हैदर तब ईरान के शाह की मेहमान थीं।

खुमैनी को जब 1964 में निकाला गया, तब ईरानी औरतों ने प्रदर्शन किए थे और 1978 के आते-आते औरतें शाह के खिलाफ आ चुकी थीं।

एक कार्यक्रम के बारे वह में लिखती हैं, 'तीसरे रोज अमजदिया स्टेडियम में तकरीबन पचास हजार नौजवान लड़के-लड़कियों ने वर्जिशी मुकाबले पेश किए। लड़कियां लड़कों के साथ कराटे लड़ीं, मोटर बाइक सवार जनाना पुलिस की लड़कियों ने हैरतअंगेज करतब दिखाए। आग के चक्करों से अपनी मोटरसाइकिलें कुदा ले गईं। ईरानी महिलाओं की यह तरक्की वाकई काबिले तारीफ थी, इसकी शुरुआत रजा शाह कबीर ने की थी। प्रोग्राम में पूरे ईरान की महिला कॉलेजों और स्कूलों की लड़कियां हिस्सा ले रही थीं। तब रानी शहबानो के सानो गुमान में न था कि यही छात्र और बुद्धिजीवी शहंशाहियत के खिलाफ संघर्ष का आगाज करेंगे। उनकी तस्वीरें जलाएंगे, 'मर्ग बरशाह' के नारे लगाएंगे और खुशी-खुशी मशीनगनों का निशाना बनेंगे। ये मोटर बाइक सवार और जूडो-कराटे करने वाली लड़कियां कौमी जद्दोजहद के सिंबल के तौर पर सियाह चादरें ओढ़कर उस इंकलाब में शामिल होंगी। उनको और मुझ समेत अनेक लोगों को उस वक्त मालूम न था कि ये नई मिडिल क्लास लड़कियां आठ साल बाद शहंशाहियत के खिलाफ मोर्चा लगाकर तेहरान के इस मैदान में गोलियों का निशाना बन जाएंगी, जिसे अब ईरानी 'शिकारगाहे शहंशाही' कहते हैं।'

दिलचस्प यह है कि खुमैनी को जब 1964 में देश निकाला दिया गया, तब ईरानी औरतों ने सड़कों पर जबर्दस्त प्रदर्शन किए थे और 1978 आते-आते हर तबके की ईरानी औरतें शाह के खिलाफ मोर्चा खोल चुकी थीं। इन प्रदर्शनों में 1963 की पश्चिमी सभ्यता को थोपने वाले 'काफूरी इंकलाब' व शाह की खुफिया पुलिस के रवैये का भी बड़ा हाथ था।

इस समय ईरान का सबसे बड़ा हिमायती रूस है। उसी के खिलाफ 1911 में ईरानी औरतों ने संसद के सामने जबर्दस्त प्रदर्शन किए थे, बहारिस्तान स्क्वॉयर में जोरदार तकरीरें कीं और नज्में पढ़ी थीं। रजा शाह कबीर ने 1937 में गर्ल्स कॉलेज खोला और ईरानी औरतों की दुनिया बदल दी। 1962 में ईरानी औरतों को वोट का अधिकार भी शाह ने ही दिया था। लेकिन, अब वहां की इविन जेल औरतों के लिए काल-कोठरी बन गई है। कितनी महिलाएं जेल में हैं, कोई नहीं जानता। पिछले साल मार्च में एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा था ईरान में औरतों व लड़कियों के खिलाफ व्यवस्थागत भेदभाव, हिंसा तथा महिला अधिकारों का खुला हनन हो रहा है। पिछले वर्ष जब ईरान ने इजरायल पर जवाबी हमले किए, तब वार कंट्रोल रूम की मॉनिटरिंग करते हुए ईरानी लड़कियों के वीडियो भी आए थे।

(ये लेखक के अपने विचार हैं।)

मनसा वाचा कर्मणा

अंधेरे पलों के चौकीदार बनें

सभी लोग अंधेरे से डरते हैं। अंधेरा बाहर का ही नहीं, अंदर का भी होता है। यह डर बहुत पुराना है। कल्पना करें, आदिमकाल में जब पृथ्वी पर रोशनी जलाने का कोई साधन नहीं था; सूरज के डूबते ही घुप्प अंधेरा छा जाता था, तब आदमी कितना असहाय अनुभव करता होगा! कोई भी जानवर कभी भी आकर उन पर हमला कर दे या आदमी की शक्ल में ही जानवर आ जाएं और मार दें। अब बाहर का अंधेरा तो खत्म हो चुका है, लेकिन भीतर का अंधकार बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि उसके बारे में कोई सोचता नहीं है। इस अंधेरे का एक ही इलाज है, उसे देखना। अगर आप उसे देखें, तो वह बिखरने लगता है।

बाल शेम नाम के एक यहूदी संत थे। वह आधी रात को नदी की तरफ जाते और आंखें बंद करके बैठे रहते थे बस। उसी नदी के किनारे एक अमीर आदमी की हवेली थी, जिसका चौकीदार बाल शेम को देखकर हैरान रहता था। हर रात, जैसे ही टावर की घंटी बारह बजने के संकेत देती, बाल शेम अंधेरे में प्रवेश करते। एक दिन गरीब चौकीदार खुद को पूछने से रोक नहीं पाया, 'आप हर रात यहां क्यों आते हैं और अंधेरे में नदी के पास क्यों बैठते हैं? इसका क्या मकसद है?'

चौकीदार को जवाब देने के बजाय बाल शेम ने पूछा, 'तुम्हारा काम क्या है?'

उसने कहा, 'मैं एक चौकीदार हूं।'

बाल शेम ने कहा, 'बिल्कुल! यही मेरा काम है। मैं भी चौकीदार हूं।'

चौकीदार ने कहा, 'अजीब है। आप चौकीदार हैं, तो यहां क्या कर रहे हैं? आपको उस घर की रखवाली करनी चाहिए, जहां आप चौकीदार हैं।'

बाल शेम ने कहा, 'वही कर रहा हूं। तुम किसी और के घर की रखवाली करते हो; मैं अपने घर की रखवाली करता हूं। यह मेरा घर है। मैं जहां भी जाता हूं, अपने घर के साथ जाता हूं, लेकिन मैं निरंतर चौकीदार हूं।'

सभी अंधेरे पलों के चौकीदार बने रहें, वे विलीन हो जाएंगे। असल में, यही परिभाषा है: जिसे भी आप देखते हैं, अगर वह देखने से गायब हो जाता है, तो इसका मतलब है कि वह कुछ गलत था। अगर देखने से वह ज्यादा साफ, अधिक करीब आता है, तो इसका मतलब है कि वह कुछ ऐसा था, जिसे अपनाना था। अच्छे और बुरे की कोई दूसरी परिभाषा नहीं है। देखना ही तय करता है- यही एकमात्र पैमाना है।

बाहर का अंधेरा तो खत्म हो चुका है, लेकिन भीतर का अंधकार बढ़ता ही जा रहा है। इस अंधेरे का एक ही इलाज है, उसे देखना। अगर आप उसे देखें, तो वह बिखरने लगता है।

सवाल यह भी है कि पाप क्या है और पुण्य क्या है? जो गायब हो जाता है, वह पाप है, और जो करीब आता है, ज्यादा साफ होता है, तुम्हारा हिस्सा बनना चाहता है, वह पुण्य है। देखना निश्चित रूप से आध्यात्मिक जीवन की सुनहरी चाभी है।

अमृत साधना

राजनाथ सिंह | केंद्रीय रक्षा मंत्री

सेना ने भारत की सामाजिक एकता को सुदृढ़ करने में भी अतुलनीय योगदान दिया है। यही कारण है कि भारतीय सेना केवल एक सैन्य बल नहीं, बल्कि राष्ट्र-निर्माण का एक प्रमुख स्तंभ है।

अनुलोम-विलोम
गिग वर्कर

देर से ही सही पर बिल्कुल दुरुस्त फैसला

सरकार ने गिग कामगारों पर 10 मिनट में सामान पहुंचाने की पाबंदी हटाकर बेहद सराहनीय कार्य किया है। आजकल की भागदौड़ वाली जिंदगी में लोग समय की बचत के लिए ऑनलाइन सामान मंगाने को अधिक तवज्जो देने लगे हैं। इस कारण कंपनियां अपने नाम और काम को बढ़ाने के लिए कम से कम समय में सामान पहुंचाने की प्रतियोगिता में लग गईं, फिर चाहे इसके लिए डिलीवरी पार्टनर को जोखिम के बीच सामान क्यों न पहुंचाना पड़े? डिलीवरी पार्टनर की मजबूरी यह है कि आर्थिक वजहों से वे यह सब करने को मजबूर थे। सड़कों पर आड़ी-तिरछी गाड़ी चलाकर वे दस मिनट के भीतर ऑर्डर पूरा कर रहे थे। इस कारण उनके साथ हादसे भी हो रहे थे। अब मजबूर होकर वे ऐसा नहीं करेंगे। उन पर सामान पहुंचाने के लिए 10 मिनट की पाबंदी हटाने से जहां वे खुश हैं, वहीं उनके परिजन भी निश्चिंत होंगे। काश! यह फैसला पहले ले लिया जाता, तो कई घरों के चिराग न बुझते।

शैलबाला कुमारी, गृहिणी

क्विक कॉमर्स की दुनिया में रफ्तार के नाम पर जो अंधी दौड़ चल रही थी, उस पर ब्रेक लगाना जरूरी कदम है। 10 मिनट डिलीवरी का वादा सुनने में जितना आकर्षक लगता था, उसकी कीमत डिलीवरी पार्टनर्स, यानी गिग कामगार अपनी जान, सेहत और सुरक्षा से चुका रहे थे। ट्रैफिक नियमों की अनदेखी, तेज रफ्तार में गाड़ी चलाना, समय का दबाव और लक्ष्य पूरा करने की मजबूरी ने इन कामगारों को इंसान से ज्यादा मशीन बना दिया था। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया के हस्तक्षेप के बाद 10 मिनट डिलीवरी वाली व्यवस्था का खत्म होना इस बात का संकेत है कि अब सरकार गिग कामगारों की समस्याओं को गंभीरता से ले रही है। श्रम मंत्रालय और कंपनियों के बीच हुई चर्चा में यह साफ हुआ कि सख्त समय-सीमा सीधे तौर पर दुर्घटनाओं व जोखिम को बढ़ाती है, जिसका खामियाजा डिलीवरी पार्टनर भुगतता है, जबकि लाभ कंपनियों व ग्राहकों को मिलता है। मंत्री का यह कहना भी उचित है कि सुविधा और मुनाफे के लिए किसी की जान से समझौता नहीं किया जा सकता। संसद में आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने भी गिग कामगारों के सम्मान, सुरक्षा, उचित मजदूरी और सामाजिक सुरक्षा की मांग की थी। हालांकि, यह भी समझना होगा कि सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के लागू होने के साथ पहली बार गिग वर्कर्स और इस तरह के कामगारों को कानूनी पहचान मिली है, जो अपने आप में एक बड़ा बदलाव है। उम्मीद है, अब इन कामगारों का जीवन कुछ सुखद बन सकेगा।

सुभाष बुड़ावन वाला, टिप्पणीकार

गिग कामगारों पर दबाव कम न होगा

गिग कामगारों के लिए सामान-आपूर्ति में 10 मिनट की बाध्यता खत्म कर देने से उनको निश्चय ही राहत मिली होगी, पर सिर्फ इसी बूते हम उनके उन्नत जीवन का ख्वाब नहीं देख सकते। कई ऐसी चुनौतियां हैं, जिनसे पार पाना जरूरी है। अन्यथा, गिग कामगारों की सुरक्षा, सम्मान और कार्यदशाओं को लेकर चल रही बहस निरर्थक साबित हो जाएगी। सबसे पहले यह समझना होगा कि क्विक कॉमर्स ने इतनी तेजी से तरक्की कैसे की? वास्तव में, लोगों को घर पर ही सुविधा पाने की लालसा है। सरकार ने 10 मिनट की सेवा तय नहीं की थी। यह तो कंपनियों की आपस की होड़ थी। अब यदि सरकार ने इस पर अंकुश लगाने का प्रयास किया है, तो यह स्वागतयोग्य है, लेकिन इससे यह दावा नहीं किया जा सकता कि तुरंत सुविधा उपलब्ध कराने वाली यह सेवा बंद हो जाएगी। अलबत्ता, इसका रूप बदल सकता है। अब कंपनियां दस मिनट कहकर अपना प्रचार नहीं करेंगी, लेकिन डिलीवरी पार्टनरों पर यह दबाव डाल सकती हैं कि वे जल्द उपभोक्ताओं को सामान पहुंचा दें। मुमकिन है, इसके लिए वे अलग से इंसेंटिव की व्यवस्था करें, जिसकी लालसा में डिलीवरी पार्टनर फिर से सड़कों पर रेस लगाते दिख जाएं। 10 मिनट में डिलीवरी की होड़ से जिस तरह की अस्वस्थ प्रतिस्पर्द्धा का जन्म हुआ था, वह इस सेवा के बंद होने के बाद भी नए रूप में जारी रह सकती है, जबकि कई अध्ययन बताते हैं कि ऐसे मॉडल से सड़क दुर्घटनाओं की आशंका कई गुना अधिक रहती है।

हालांकि, इसके अलावा भी कुछ मुश्किलें गिग कामगारों के सामने हैं। आय में अनिश्चितता, एल्गोरिदम आधारित इंसेंटिव तंत्र की अपारदर्शिता, लंबे कार्य घंटे और दुर्व्यवहार जैसे मुद्दे अब भी गिग कामगारों के सामने बने हुए हैं। इनके लिए न्यूनतम आय गारंटी की भी दरकार है, जिसकी वकालत अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन करता रहता है और हमारे यहां भी, विशेषकर विपक्ष के नेता इस बात को लेकर अपनी आवाज बुलंद करते रहते हैं। यह समझना होगा कि सुविधा और मुनाफे की दौड़ में इंसानी जान को जोखिम में नहीं डाला जाना चाहिए। सरकारों को चाहिए कि वे गिग कामगारों के हित में और प्रयास करें। यह करना इसलिए भी जरूरी है, क्योंकि क्विक कॉमर्स की सफलता इन्हीं गिग कामगारों की सेहत पर निर्भर करती है। कुल मिलाकर, इनको पर्याप्त सुरक्षा देना, इनकी सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना और इनके लिए कामकाज का माहौल बेहतर बनाना हमारे नियामक तंत्रों की जिम्मेदारी है, जो उन्हें हर हाल में निभानी चाहिए।

दीपक कुमार, टिप्पणीकार

एआई को आदत नहीं ताकत बनाएं

इसमें दोराय नहीं कि एआई की मदद से घंटों के काम मिनटों में पूरे हो रहे हैं, लेकिन हर बात पर एआई का सहारा, हमारी सोचने की क्षमता छीन रहा है। हमें याद रखना होगा कि स्मार्ट टूल्स ध्यान करने की सलाह दे सकते हैं, हमारे बदले ध्यान कर नहीं सकते। मानसिक शांति के लिए 'डिजिटल माइंडफुलनेस' का अभ्यास बेहद जरूरी है।

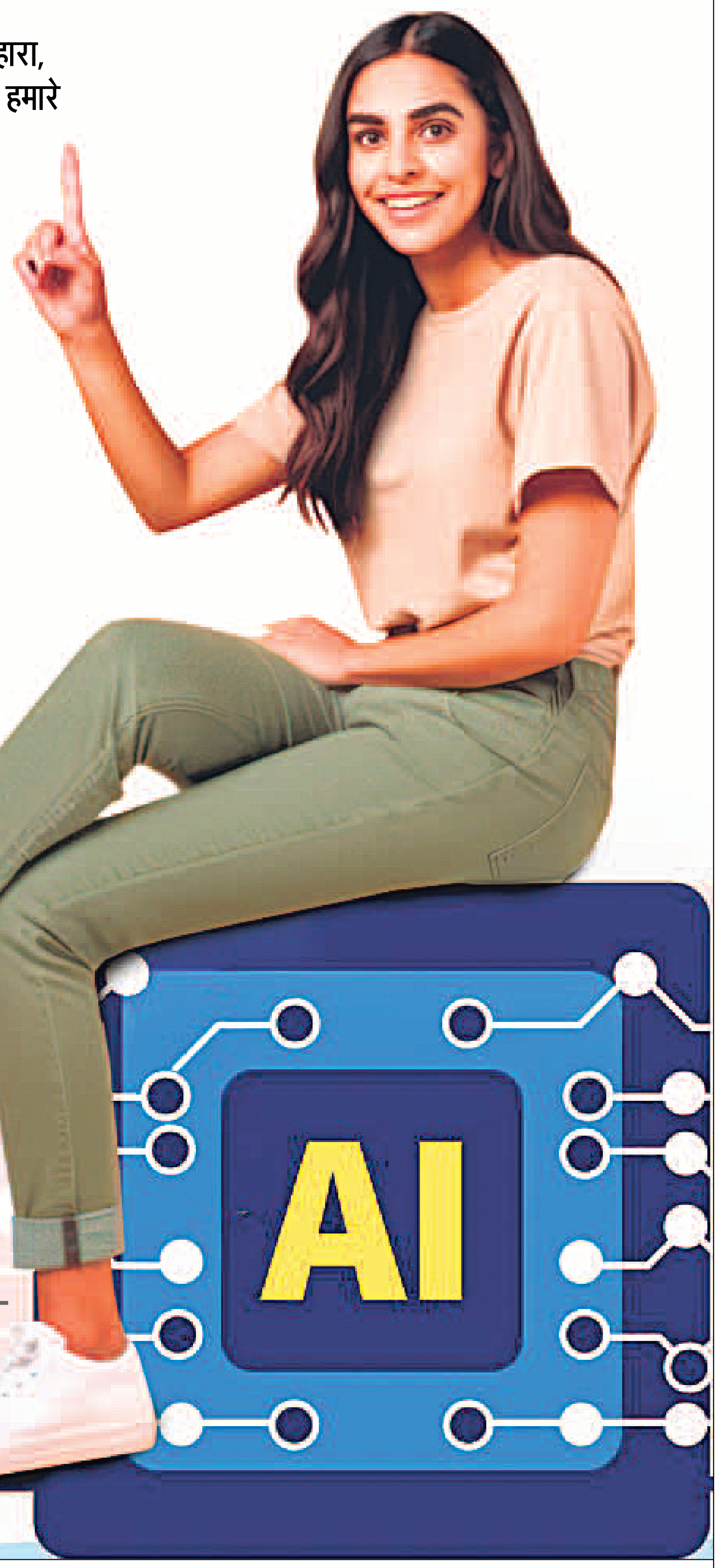

क्रिस केज
मानसिक स्वास्थ्य सलाहकार। नए तौर तरीकों और तकनीक के बीच मानसिक स्पष्टता और सीमाओं पर जोर

एआई आपका असिस्टेंट है। यह असिस्टेंट आपके दिन की योजना बना सकता है, आपके ईमेल को संक्षेप में लिख सकता है और आपके कामों को रफ्तार दे सकता है। पर क्या एआई सब कुछ है? मेरा मानना है कि एआई आपको ध्यान करने की सलाह दे सकता है, लेकिन वह आपके लिए ध्यान नहीं कर सकता। ध्यान तो आपको ही करना होगा।

अगर एआई तकनीक और हमारे डिजिटल उपकरण हमारी जगह ध्यान भी कर सकते, तो मेरे पास 'माइंडफुलनेस' के बेहतरीन आंकड़े होते। हर कोई ध्यान के हर सत्र में मौजूद होता और शायद हर किसी को 'आंतरिक शांति' का गोल्ड मेडल मिल जाता। हममें से अधिकांश लोगों की तरह मैंने यही सीखा है कि हमारे उपकरण कितने भी स्मार्ट क्यों न हो जाएं, वे हमारे हिस्से के 'महसूस' करने वाले काम नहीं कर सकते। जिन कामों से हमारी भावनाएं, हमारी प्रेरणाएं जुड़ी होती हैं, वे काम हमारे स्मार्ट उपकरण नहीं कर सकते। वे हमारी सांसें धीमी नहीं कर सकते या यह याद नहीं दिला सकते कि हमारे लिए क्या जरूरी है। वह काम आज भी, सौभाग्य से, इंसान के हिस्से ही है।

तकनीक संग ऐसा हो रिश्ता...

तकनीक के साथ हमारा ऐसा रिश्ता होना चाहिए, जो थकाने की बजाय हमारा सहायक हो। आइए तकनीकी उपकरणों के इस्तेमाल से जुड़ी एक संतुलित दिनचर्या बनाने की कोशिश करते हैं। मैं इसे 'माइंडफुल टेक रूटीन' कहता हूं। एक ऐसी दिनचर्या, जो स्पष्टता बढ़ाने के लिए एआई का उपयोग करे, उसे और उलझाने के लिए नहीं।

एआई ने आधुनिक जीवन को काफी कुछ बदला है। जैसे, नोशन एआई प्रोजेक्ट्स को व्यवस्थित कर सकता है। 'ग्रामरली' आपके लेखन को निखारता है। आपकी कॉफी ठंडी होने से पहले चैटजीपीटी आपके 80 प्रतिशत ईमेल्स के ड्राफ्ट तैयार कर देता है, लेकिन, इस शक्ति की छिपी हुई कीमत भी चुकानी पड़ती है: निरंतर उत्तेजना। हम न केवल अपने काम, बल्कि सोच को भी बाहर ठेके पर देने लगे हैं। हम टैब्स और नोटिफिकेशन के बीच कूदते रहते हैं और दोपहर 2 बजे तक हमारा दिमाग उस ब्राउजर विंडो की तरह लगता है, जिसमें बहुत सारे टैब खुले हैं। एआई खलनायक नहीं है, चुनौती यह है कि हम इसे कैसे उपयोग करते हैं? लक्ष्य 'डिजिटल मिनिमलिज्म' यानी तकनीक का कम इस्तेमाल नहीं, बल्कि डिजिटल माइंडफुलनेस है। हम तकनीक का उपयोग विवेक से करें।

thementallens

'माइंडफुल टेक रूटीन' के पांच कदम

1 दिन की शुरुआत 'एनालॉग' ढंग से। इसका मतलब है- स्क्रीन से दूर। कुछ भी ऐसा करें, जो डिजिटल दुनिया से परे हो। मसलन, डायरी लिखना, स्ट्रेचिंग करना या नोटिफिकेशन चेक करने से पहले सुकून से कॉफी पीना। दुनिया या आपका इनबॉक्स, आपसे क्या चाहता है, यह देखने से पहले खुद से मिलें।

2 एआई आकर्षक है। जल्दी ही आप हर छोटी चीज के लिए इस पर निर्भर हो सकते हैं। एआई का उपयोग करने से पहले ऐसा करें।
- **रुकें:** मैं क्या हासिल करना चाहता हूं?
- **साधन:** एआई का उपयोग मदद के लिए करें, निर्णय लेने के लिए नहीं?
- **सोचें:** क्या नतीजे मेरे व्यक्तित्व के अनुरूप हैं?

3 आत्म-चिंतन करें, इसलिए कि आप किसी चीज को तकनीक के जरिये कर सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको उसे करना ही चाहिए। किसी काम को एआई को सौंपने से पहले खुद से पूछें, 'क्या मैं अपना समय बचा रहा हूं या मैं सोचने से बच रहा हूं?'

4 **दोपहर में कुछ देर अपने लिए:** दूसरी कॉफी और लगातार आ रहे नोटिफिकेशन के बीच, कुछ देर तकनीक से दूर हटें। 10 मिनट का डिजिटल डिटॉक्स करें। कोई स्क्रीन नहीं, कोई ईयरबड नहीं। थोड़ा टहलें, पानी पिएं या लिखें कि आज मैंने सार्थक काम क्या किया? आगे क्या किया जाना है? दिमाग को व्यवस्थित होने में मदद मिलेगी।

5 दिन का अंत 'मानवीय' तरीके से करें। अगर मन की सतह पर कई टैब यानी दिन भर के जरूरी या गैर जरूरी मुद्दे खुले रह गए हैं, तो सोने से पहले उनमें से कुछ को बंद कर दीजिए।

सोने से पहले

- कुछ गहरी सांसें लें। सांस लेते समय चार तक गिनती करें और बाहर छोड़ते समय छह तक गिनें। इससे तंत्रिका तंत्र को विश्राम मोड में जाने का संकेत मिलेगा
- दो-तीन मिनट के लिए शांत बैठें या ध्यान करें।
- पूरे शरीर पर ध्यान दें और देखें कि कहीं तनाव तो नहीं है। अगर तनाव महसूस हो तो खुद को सहज करें।
- अंत में पूछें: 'कल क्या जरूरी किया जाना है?'
- इस अभ्यास से आप समझ पाएंगे कि अब और तकनीक की जरूरत नहीं है।

हर दिन बेहतर बनने की तैयारी

डिजिटल डिटॉक्स का मतलब अपने ऐप्स डिलीट करना या तकनीकी उपकरणों से दूरी बनाना नहीं है। इसका मतलब यह याद रखना है कि जब आप उन्हें खोलते हैं, तो कंट्रोल किसके हाथ में है। वे आपके ऊपर हावी तो नहीं हो रहे? इन्हें अपनी बेड़ी बनाने से बचें।

काम की बात

घर का बिखरा होना केवल आलस का नतीजा नहीं है। इसके पीछे कई मनोवैज्ञानिक कारण और घर में रहने वालों की गलत आदतें भी जिम्मेदार होती हैं। सामान को कैसे व्यवस्थित करें, जानते हैं विशेषज्ञों से-

घर को बिखेरिए नहीं संवारकर रखिए

घर व्यवस्थित रखना केवल अलमारी में समान लगाना या नए-नए सामान रखने के डिब्बे खरीदना नहीं है। घर की अस्त व्यस्तता दूर करने के लिए अपनी भावनाओं से जुड़ना और अपनी आदतें सुधारना भी जरूरी है। वॉशिंगटन पोस्ट के एक लेख में कुछ पेशेवर ऑर्गेनाइजर इस बारे में महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान देने की सलाह देते हैं-

1 **'स्पेशल' की परिभाषा समझें:** प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजर मैगन केसमैन के अनुसार, 'अगर सब कुछ खास है, तो कुछ भी खास नहीं।' अलमारी के दराजों में या संदूकों में सामान को ठूसकर भरने से आप अपनी खास चीजों का सम्मान नहीं कर पाते। जो चीजें आपके लिए खास हैं, उन्हें रखें और बाकी छोड़ दें।

2 **उतना ही लें, जितना खा सकें :** प्रोजेक्ट की बात हो या फिर कमरे की सफाई, हम एक साथ सब कुछ पूरा करना चाहते हैं। ऐसा करना हमें जल्दी थका देता है। इस बारे में ऑर्गेनाइजर विशेषज्ञ ओलिविया पार्क्स कहती हैं, 'ज्यादा बेहतर है कि हम एक-एक कोने या एक अलमारी के शेल्फ की सफाई करते हुए आगे बढ़ें। इस तरह काम का उत्साह बना रहता है।'

3 **अपने आज को जगह दें :** अक्सर हमारी अलमारियां या बक्से, उन कपड़ों या चीजों से भरे होते हैं, जो हम कभी पहनते थे या फिर शायद भविष्य में पहनेंगे। ऐसे में आपके आज के लिए जगह कहां है? अपने आज से जुड़े सामान को रखें, बाकी चीजों को विदा करें।

4 **'शायद कभी' की आदत छोड़ें:** ऑर्गेनाइजर सलिसन फिलन कहती हैं कि 'जस्ट-इन-केस' यानी शायद कभी जरूरत पड़ जाए एक बीमारी की तरह है। एक बार खुद से जोर देकर पूछें कि यह वस्तु कब काम आएगी? अगर कोई सामान पिछले काफी समय से इस्तेमाल नहीं हुआ और आप सोच नहीं सोच पा रहे कि आगे कब इसे इस्तेमाल करेंगे, तो आप उस सामान को हटा दें।

5 **कीमत वसूलने का मोह छोड़ें :** अक्सर हम महंगी चीजें इसलिए नहीं फेंकते, क्योंकि उन पर बहुत पैसा खर्च हुआ था। सच यह है कि पैसा तो पहले खर्च हो चुका है। अब वह वस्तु केवल जगह घेर रही है। उसे किसी जरूरतमंद को देना ज्यादा बेहतर है।

6 **चीजों को सही जगह पर रखें :** चीजों को उनके उपयोग के स्थान के करीब रखने से उन्हें वापस अपनी जगह पर रखना व ढूंढना आसान हो जाता है। इससे सुविधा और व्यवस्था दोनों बढ़ती है।

7 **अपराध बोध में न जिएं :** ऑर्गेनाइजर मैट पैक्सटन कहते हैं, 'हम ऐसी चीजें जोड़कर रखते हैं, जो हमसे अलग हो चुके, दूर जा चुके लोगों से जुड़ी होती हैं। कई चीजें केवल इसलिए कि उन लोगों को बुरा लग जाएगा। याद रखें- प्यार दिलों में होता है, चीजों में नहीं।'

8 **परफेक्शन नहीं, सहजता चुनें :** सामान की व्यवस्था ऐसी रखें, जो सुविधाजनक हो, जिसे आप थकान और तमाम व्यस्तता के बावजूद भी बनाए रख सकें।

बुजुर्ग मां-बाप की चुप्पियों को गौर से समझिए

विविध

एक अफ्रीकी कहावत है कि किसी बुजुर्ग का जाना, एक बड़े पुस्तकालय का जलकर राख हो जाना है। नए को महत्व और पुराने को खारिज करने की जल्दबाजी में अक्सर अपने बुजुर्गों को ठहरकर सुनना-समझना रह जाता है। लेखक टोनी कॉलिन्स यहां बता रहे हैं कि क्यों वे अब अपनी वृद्ध मां की बातें ज्यादा संवेदना से सुनते हैं।

जीवन के अधिकांश समय मुझे यही लगता था कि बुढ़ापा सिर्फ शरीर का धीमे हो जाना है- बालों का सफेद होना, याददाश्त धुंधलाना और चाल धीमी हो जाना, लेकिन अपनी 96 साल की मां की देखभाल ने मेरी इस सोच को बदल दिया है। अब मैं कुछ और भी गहरा और दर्दनाक देख पा रहा हूं। मैं एक ऐसी संस्कृति में ज्ञान और अनुभव को धीरे-धीरे मिटते देख रहा हूं, जो केवल नया होने को महत्व देती है, पुराने को खारिज कर देती है और देख नहीं पाती कि क्या छूट रहा है।

एक दोपहर मेरी मां मुझे अपने पिता की बात बता रही थी। उस क्षण मुझे एहसास हुआ कि अगर मैंने अपनी मां के साथ ढंग से समय बिताना नहीं सीखा, तो मैं न केवल उन्हें खो दूंगा, बल्कि उनके जीवन के अनुभवों को आगे ले जाने और शायद खुद को गहराई से जानने का मौका भी खो दूंगा।

वह पल जब मुझे एहसास हुआ

दोपहर का समय था। मां सामने बैठी अपने बचपन की बातें याद कर रही थीं- युद्ध के समय के राशन कार्ड, पहली बार रेडियो पर सुना संगीत। तभी वह वाक्य के बीच में ही रुक गईं। सन्नाटा खिंच गया। ऐसे पलों में, मैं बेचैन हो जाता हूं। चाहता हूं कि मां जल्दी वाक्य पूरा करें और मैं अपने अधूरे काम पूरा कर सकूं, लेकिन इस बार, मैं उनके साथ बैठा रहा। मैंने महसूस किया कि वह चुप्पी उनकी कोशिशों से, उनकी गरिमा से भरी थी। उसमें समय के पीछे जाकर उस चीज को खोजने का प्रयास था, जो उनके लिए मायने रखती थी। उस पल मैं समझ गया कि सुनना सिर्फ एक दयालुता नहीं है। यह 'संरक्षण' है- उनकी कहानी का, हमारे रिश्ते का और मेरी उस क्षमता का, जो मुझे कठिन समय में धैर्य से टिके रहना सिखाती है।

जरूरी है अंत तक महत्व दिया जाना

किसी बुजुर्ग की देखभाल करना, केवल उन्हें सुरक्षित रखने, खिलाने या दवा देने तक सीमित नहीं है। यह उनके सिकुड़ते संसार का 'साक्षी' बनने के बारे में है। साक्षी बनना कोई निष्क्रिय नहीं, एक सक्रिय प्रयास है- उनकी आवाज के लहजे में आने वाले बदलावों को गौर से देखना, उनकी आंखों में उस चमक को पहचानना, जो किसी पुराने गाने को सुनकर आती है। उस गर्व को महसूस करना, जो उन्हें तब होता है, जब वे कोई ऐसी कहानी सुनाते हैं, जो अब किसी और को याद नहीं। इस प्रक्रिया ने मुझे सिखाया कि गरिमा का मतलब हमेशा मजबूत बने रहना नहीं है। गरिमा का अर्थ है- अंत तक महत्व दिया जाना। यह एक ऐसी चीज है, जो हम एक-दूसरे को दे सकते हैं, बशर्ते हम अपनी गति धीमी करने को तैयार हों। बुढ़ापे, कमजोरी व मृत्यु से आंखें फेर लेना आसान है, लेकिन हर बार जब हम नजरें फेरते हैं, तो भावनात्मक स्तर पर कुछ ऐसा खो देते हैं, जिसकी भरपाई नहीं हो सकती।

जब हों अपने बुजुर्गों के साथ

सवाल पूछें: कभी-कभी उनसे छोटे-छोटे सवाल पूछें। जैसे 'जब आप दस साल के थे, तब रविवार कैसे बिताते थे? या फिर कोई त्योहार कैसे मनाते थे?'
प्रतीक्षा करें: उन्हें यादें बटोरने के लिए पूरा समय दें।
बातें सहेजें: उनकी बातें कहीं लिखें या रिकॉर्ड करें। बचाई गई एक याद भी उस 'पुस्तकालय' का एक हिस्सा है, जिसे आपने जलने से बचा लिया।

मां के साथ बिताए समय ने मुझे दिखाया है कि प्यार बड़े और नाटकीय कामों से नहीं, बल्कि साथ बने रहने की इच्छा से नापा जाता है। सुनना एक 'पूजा' की तरह है, यह कहने का एक तरीका है कि आप अभी भी मायने रखते हैं। आपकी आवाज अभी भी महत्वपूर्ण है।'

बुजुर्ग हमें पीछे नहीं खींच रहे हैं। वे उस रास्ते का 'नक्शा' थामे खड़े हैं, जहां से हम आए हैं, ताकि हम कहीं भटक न जाएं, इसलिए, मैं रुकने, सुनने और उस चीज का सम्मान करने का चुनाव करता हूं, जो धीरे-धीरे धुंधली हो रही है।

tinybuddha.com

एकदा

सेवा

एक आदमी ने एक विद्यालय शुरू किया। एक दिन विद्यालय में वाद-विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसका विषय था- जीव दया और प्राणी मात्र की सेवा।

तय समय पर विद्यालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में प्रतियोगिता आरंभ हुई। किसी छात्र ने सेवा के लिए संसाधनों की महत्ता पर दिया और कहा कि हम दूसरों की तभी सेवा कर सकते हैं, जब हमारे पास उसके लिए पर्याप्त संसाधन हों। वहीं कुछ छात्रों का यह भी कहना था कि सेवा के लिए संसाधन नहीं, भावनाओं का होना जरूरी है।

इस तरह तमाम प्रतिभागियों ने सेवा के विषय में शानदार भाषण दिए। आखिर में जब पुरस्कार देने का समय आया, तो उस आदमी ने एक ऐसे विद्यार्थी को चुना, जो मंच पर बोलने के लिए ही नहीं आया था। यह देखकर सामने बैठे लोगों में रोष के स्वर उठने लगे। आदमी ने सबको शांत कराया और कहा, 'आपको शिकायत है कि मैंने ऐसे विद्यार्थी को क्यों चुना, जो प्रतियोगिता में शामिल ही नहीं हुआ था? दरअसल, मैं जानना चाहता था कि हमारे छात्रों में कौन-सा विद्यार्थी सेवाभाव को सबसे बेहतर ढंग से समझता है। प्रतियोगिता स्थल के द्वार पर एक घायल बिल्ली कराह रही थी। आप सब उसी द्वार से अंदर आए, परंतु किसी ने भी उस बिल्ली की ओर आंख उठाकर नहीं देखा। यह अकेला प्रतिभागी था, जिसने वहां रुक कर उसका उपचार किया और उसे सुरक्षित स्थान पर छोड़ आया।'

व्यक्ति ने आगे कहा- सेवा या सहायता वाद-विवाद का विषय नहीं है, यह जीवन जीने की कला है। जो अपने आचरण से शिक्षा देने का साहस न रखता हो, उसके वक्तव्य कितने भी प्रभावी क्यों न हों, वह पुरस्कार पाने के योग्य नहीं हैं।

रोजनामचा

पं. राघवेन्द्र शर्मा
ज्योतिषाचार्य

स्कैन करें
भविष्यफल और व्रत-त्योहार जानने के लिए

मेष : आत्मविश्वास भरपूर रहेगा। किसी मित्र के सहयोग से कारोबार में वृद्धि होगी। परिवार का साथ मिलेगा। कारोबार के लिए यात्रा लाभप्रद रहेगी। खर्च बढ़ेंगे।

वृष : आत्मविश्वास बहुत रहेगा। मन प्रसन्न रहेगा। किसी राजनेता से भेंट हो सकती है। नौकरी में कार्यक्षेत्र में बदलाव हो सकता है। परिश्रम अधिक रहेगा।

मिथुन : आत्मविश्वास में कमी रहेगी। सेहत के प्रति सचेत रहें। नौकरी में स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। भागदौड़ अधिक रहेगी। रहन-सहन अव्यवस्थित रहेगा।

कर्क : आत्मविश्वास भरपूर रहेगा। मन में उतार-चढ़ाव रहेंगे। परिवार का साथ मिलेगा। नौकरी में अफसरों का सहयोग मिलेगा। कार्यक्षेत्र में वृद्धि हो सकती है।

सिंह : मन परेशान रहेगा। आत्मविश्वास में कमी रहेगी। आत्मसंयत रहें। बेकार के क्रोध से बचें। किसी मित्र के सहयोग से नौकरी के अवसर मिल सकते हैं।

कन्या : आत्मविश्वास भरपूर रहेगा, लेकिन मन परेशान हो सकता है। नौकरी में तरक्की के मार्ग प्रशस्त होंगे। आय में वृद्धि होगी। कार्यक्षेत्र में बदलाव हो सकता है।

तुला : मन में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं। कारोबार में बदलाव हो सकता है। किसी दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। परिवार का साथ मिलेगा। आय में वृद्धि होगी।

वृश्चिक : आत्मविश्वास भरपूर रहेगा। नौकरी में तरक्की के मार्ग प्रशस्त होंगे। आय में वृद्धि होगी। शैक्षिक कार्यों के प्रति सचेत रहें। व्यवधान आ सकते हैं।

धनु : पठन-पाठन में रुचि बढ़ेगी। मन में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं। बातचीत में संतुलित रहें। सेहत का ध्यान रखें। नौकरी में बदलाव के योग बन रहे हैं। आय बढ़ेगी।

मकर : मन में उतार-चढ़ाव रहेंगे। आत्मविश्वास बहुत रहेगा। माता-पिता का साथ रहेगा। कला व संगीत के प्रति रुझान बढ़ सकता है। कारोबार बढ़ेगा।

कुंभ : मन परेशान हो सकता है। परिवार की सेहत का ध्यान रखें। खर्चों में वृद्धि। किसी नए कारोबार की शुरुआत के लिए परिवार से दूर किसी दूसरे स्थान पर जाने का योग।

मीन : आत्मविश्वास तो भरपूर रहेगा। मन में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं। कारोबार में बदलाव के योग बन रहे हैं। लाभ में वृद्धि होगी। मित्रों का साथ और सहयोग मिलेगा।

व्रत और त्योहार | पंचांग | पं. ऋभुकांत गोस्वामी

19 जनवरी, सोमवार, **शक संवत्:** 29 पौष (सौर) 1947, **पंजाब पंचांग:** 06 माघ मास प्रविष्टे 2082, **इस्लाम:** 29 रज्जब, 1447, **विक्रमी संवत् :** माघ शुक्ल प्रतिपदा तिथि रात्रि 02.15 बजे तक पश्चात द्वितीया तिथि, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र प्रातः 11.53 बजे तक पश्चात श्रवण नक्षत्र, वज्र योग रात्रि 08.45 बजे तक पश्चात सिद्धि योग, किंस्तुघ्न करण, चंद्रमा मकर राशि में (दिन-रात)। **सूर्य उत्तरायण।** सूर्य दक्षिण गोल। शिशिर ऋतु। प्रातः 07.30 बजे से प्रातः 09 बजे तक राहुकालम्। माघ शुक्ल पक्ष प्रारंभ। गुप्त नवरात्र प्रारंभ।

वास्तु सलाह | आचार्य मुकुल रस्तोगी

कृपया बताएं कि जानवर एवं पक्षी की सेवा करने से कौन से ग्रह ठीक होते हैं?
-रिंकी सिंह, देहरादून

- गाय की सेवा करने से नवग्रह प्रसन्न होते हैं।
- कुत्तों की सेवा करने से केतु ग्रह प्रसन्न होते हैं।
- पक्षी, कबूतर की सेवा करने से राहु ग्रह प्रसन्न होते है व जीवन में खुशहाली आती है।
- बंदरों की सेवा करने से सूर्य एवं मंगल ग्रह प्रसन्न होते है। इससे ऊर्जा बढ़ती है।
- कौवों की सेवा से शनि देव प्रसन्न होते है। इससे जीवन की समस्याएं दूर होती हैं।
- मछलियों की सेवा करने से राहु ग्रह प्रसन्न होते हैं। जीवन में सुख-शांति आती है।

वर्ग पहेली : 8214

बाएं से दाएं
2. आक्षेप लगाना; व्यंग्य करना (2,3)
5. परिमाण करना; नापना (3)
7. पुत्र; माणिक; सुर्ख (2)
8. उत्तीर्ण होना; जांच में खरा उतरना; परीक्षा में पूरा उतरना (3,3)
10. आनंदित होना; उत्साहित होना; ध्वजारोहण करना; फहराना; हिलना-डुलना; हिलोर मारना (4)
11. जलवायु; वातावरण (2,2)
13. जुर्माना वसूलना; रसीद लिख कर देना (3,3)
14. अतिकाल; विलंब; वक्त; समय (2)
15. रसास्वादन करना; स्वाद देखना (3)
16. अस्वीकार करना; निषिद्ध करना; रोकना; वर्जित करना (2,3)

ऊपर से नीचे
1. अस्थिर; उतावला; चंचल; चालाक (3)
3. नगर का; नगर संबंधी; नगरीय; नगर में रहने वाला; निवासी (4)
4. जान न्योछावर करना; शहादत देना; मरना (2,4)
5. धन धान्य से भरना; संपन्न करना; समृद्ध करना (4,3)
6. टालमटोल करना; अनसुनी करना; अड़चन पैदा करना (4,3)
9. प्राप्त होना; मिलना; वसूला जाना (4,2)
12. भर्त्सना; झिड़की; लानत मलानत; फटकारने की क्रिया (4)
14. अवलोकन करना; खोजना; ढूंढना; आजमाना (3)

हरीश चन्द्र सन्सी, विविधा विधा, दिल्ली
(उत्तर अगले अंक में)

वर्ग पहेली : 8213

1 ब	लि	2 का	ब	3 क	रा		4 अ	
खा		र		म		5 चा	ल	क
6 न	म	क	7 ह	रा	8 म		वि	
क			ता		धु		9 दा	10 स
र		11 क	श	मा	र	ना		न
12 ना	13 व		हो		त			स
	र		14 ना	15 का	म	16 क	र	ना
17 ख	प	त		ली		मा		ह
	क्ष		18 घ	न	घ	ना	ह	ट

सुडोकू : 8196

* कठिन

			5				7	
	9	1				8		
				2		5		6
			7				3	8
	7						2	
9	8				4			
8		3		5				
		4				6	5	
	5				1			

खेलने का तरीका : दिमागी खेल और नंबरों की पहेली है यह। ऊपर नौ-नौ खानों के नौ खाने दिए गए हैं। आपको 1 से 9 की संख्याएं इस तरह लिखनी हैं कि खड़ी और पड़ी लाइनों के हरेक खाने में 1 से 9 की सभी संख्याएं आएं। साथ ही 3×3 के हरेक बक्से में भी 1 से 9 तक की संख्याएं हों। पहेली का हल हम कल देंगे।

सुडोकू : 8195

8	5	2	4	7	6	1	3	9
1	6	3	2	8	9	4	5	7
4	9	7	5	3	1	6	8	2
3	8	6	9	5	7	2	4	1
5	7	4	3	1	2	8	9	6
2	1	9	6	4	8	5	7	3
7	3	5	1	2	4	9	6	8
9	4	1	8	6	3	7	2	5
6	2	8	7	9	5	3	1	4

ग्रीनलैंड टैरिफ: सोना-चांदी चमकेंगे, शेयर बाजार में बढ़ेगी हलचल

नई दिल्ली। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड को लेकर एक बार फिर वैश्विक राजनीति और बाजारों में हलचल मचा दी है। ट्रंप ने संकेत दिए हैं कि यदि ग्रीनलैंड मुद्दे पर सहयोग नहीं मिला तो अमेरिका नाटो के कुछ यूरोपीय देशों पर भारी टैरिफ लगा सकता है।

इस संभावित फैसले का असर सिर्फ अमेरिका और यूरोप तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसका प्रभाव सोना-चांदी की कीमतों से लेकर भारतीय शेयर बाजार तक दिख सकता है।

भारतीय शेयर बाजार में निकट भविष्य में अस्थिरता देखने को मिल सकती है। हालांकि, लंबी अवधि में भारत के लिए नए व्यापारिक अवसर भी उभर सकते हैं।

ग्रीनलैंड विवाद और टैरिफ की धमकी

रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रंप ने डेनमार्क समेत नाटो के कई सदस्य देशों पर टैरिफ लगाने की बात कही है। ग्रीनलैंड डेनमार्क का स्वायत्त क्षेत्र है और पहले भी ट्रंप इसे खरीदने की इच्छा जता चुके हैं। अब इस मुद्दे को लेकर व्यापारिक दबाव बनाने की रणनीति अपनाई जा सकती है। अगर यह टैरिफ लागू होते हैं, तो वैश्विक व्यापार तनाव बढ़ना तय माना जा रहा है।

सोना और चांदी में और उछाल की संभावना

भू-राजनीतिक तनाव बढ़ते ही निवेशक सुरक्षित निवेश की ओर रुख करते हैं। ऐसे में सोना और चांदी हमेशा पहली पसंद बनते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रंप की टैरिफ धमकी से वैश्विक अनिश्चितता बढ़ेगी, जिससे सोने और चांदी की कीमतों में तेजी आ सकती है। डॉलर में कमजोरी आने की स्थिति में भी कीमती धातुओं को समर्थन मिलता है। भारत में भी इसका असर दिख सकता है और घरेलू बाजार में सोना-चांदी महंगे हो सकते हैं।

भारतीय शेयर बाजार में बढ़ सकती है अस्थिरता

यूरोप और अमेरिका के बीच व्यापारिक तनाव बढ़ता है, तो इसका असर भारतीय शेयर बाजार पर भी पड़ेगा। अल्पकाल में भारतीय बाजारों में उतार-चढ़ाव बढ़ सकता है। खासकर आईटी, मेटल, ऑटो, फार्मा, टेक्सटाइल और जेम्स-ज्वेलरी जैसे सेक्टरों पर दबाव आ सकता है, जो वैश्विक व्यापार और निर्यात पर काफी हद तक निर्भर हैं।

कुछ सेक्टरों को मिल सकता है फायदा

अगर यूरोपीय देश अमेरिका से आयात कम करते हैं, तो भारत के लिए नए व्यापारिक अवसर खुल सकते हैं। इसके अलावा, भारत और यूरोपीय संघ के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौता इस स्थिति में तेजी पकड़ सकता है। यदि यह समझौता आगे बढ़ता है, तो भारतीय निर्यातकों को लंबे समय में फायदा मिल सकता है।

निवेशकों के लिए क्या है संकेत

शेयर बाजार के विशेषज्ञ सलाह दे रहे हैं कि इस माहौल में निवेशक फिलहाल सतर्क रहें। अल्पकाल में बाजार में उतार-चढ़ाव से इनकार नहीं किया जा सकता। सुरक्षित निवेश के तौर पर सोना-चांदी में रुचि बढ़ सकती है। लंबी अवधि के निवेशक मजबूत फंडामेंटल वाले शेयरों पर ध्यान दें और घबराहट में फैसले न लें।

बाजार 30s

टाटा ट्रस्ट की प्रस्तावित बोर्ड बैठक रद्द

नई दिल्ली। सर रतन टाटा ट्रस्ट की एक प्रस्तावित बोर्ड बैठक कोरम की कमी के कारण शनिवार को रद्द कर दी गई। इस बैठक में टाटा ट्रस्ट्स के चेयरमैन नोएल टाटा के बेटे नेविल टाटा को ट्रस्टी के रूप में नियुक्त किया जाना था। नेविल टाटा को आरएसटीटी के बोर्ड में शामिल करने की कोशिश दो महीने पहले भी असफल हो चुकी है। एक जानकार ने कहा, सभी ट्रस्टी बैठक में शामिल नहीं हो सके, जो नए ट्रस्टी की नियुक्ति के लिए एक अनिवार्य शर्त है।

इरेडा के पहले अंतरराष्ट्रीय हरित ऋण को मंजूरी

नई दिल्ली। इरेडा ग्लोबल ग्रीन एनर्जी फाइनेंस आईएफएससी लिमिटेड जाम्बिया में 100 मेगावाट की स्वच्छ ऊर्जा परियोजना के विकास के लिए स्वर्णा सोलर को 2.25 करोड़ डॉलर का हरित ऋण देगी। आईजीजीईएफआईएल, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड (इरेडा) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है।

कपड़ा, दवा, इंजीनियरिंग को मिलेगा बड़ा बढ़ावा

नई दिल्ली। भारत और यूरोपीय संघ के बीच होने वाले मुक्त व्यापार समझौते से कपड़ा, दवा, रसायन, रत्न और आभूषणों के निर्यात को जबरदस्त बढ़ावा मिलेगा। इस समझौते के लिए वार्ता पूरी होने की घोषणा 27 जनवरी को हो सकती है। उद्योग का अनुमान है कि एफटीए के कारण शुल्क समाप्त होने से अगले तीन वर्षों में यूरोपीय संघ को होने वाला निर्यात दोगुना हो जाएगा।

वुड मैकेंजी की शीर्ष 10 सूची में अदाणी सोलर

नई दिल्ली। वुड मैकेंजी की 2025 की पहली छमाही की वैश्विक सौर मॉड्यूल विनिर्माण सूची में अदाणी सोलर शामिल है। अदाणी न्यू इंडस्ट्रीज की सौर फोटोवोल्टिक विनिर्माण इकाई अदाणी सोलर को वैश्विक ऊर्जा और प्राकृतिक संसाधन परामर्शदाता ने श्रेणी ए वर्गीकरण दिया गया है। इस सूची में कंपनी को 8वां स्थान मिला। जेए सोलर और ट्रिनासोलर ने क्रमशः 91.7 और 91.6 अंकों के साथ संयुक्त रूप से शीर्ष स्थान प्राप्त किया।

कच्चे जूट के निजी व्यापार पर प्रतिबंध की मांग

कोलकाता। इंडियन जूट मिल्स एसोसिएशन (आईजेएमए) ने केंद्र सरकार से कच्चे जूट की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने और फाइबर की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए तत्काल हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है। उद्योग निकाय ने इसके साथ ही 31 मार्च के बाद निजी व्यापारियों द्वारा कच्चे जूट के व्यापार पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव भी दिया है।

शादीशुदा जोड़ों को मिल सकता है साथ में रिटर्न भरने का विकल्प

बजट उम्मीदें

■ जितेंद्र सिंह

नई दिल्ली। केंद्रीय बजट 2026 से पहले टैक्स को लेकर एक नई चर्चा तेज हो गई है। माना जा रहा है कि सरकार शादीशुदा लोगों के लिए 'संयुक्त कराधान' का विकल्प पेश कर सकती है। अगर यह व्यवस्था लागू होती है, तो पति और पत्नी मिलकर एक साथ आयकर रिटर्न भर सकेंगे।

इससे खासकर उन परिवारों को राहत मिल सकती है, जहां कमाई का जिम्मा एक ही व्यक्ति पर है। अगर यह प्रस्ताव लागू होता है, तो खासकर एकल कमाई वाले परिवारों को कर में लाखों रुपये की बचत हो सकती है।

बजट से पहले इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने वित्त मंत्रालय को बजट को लेकर एक खास सलाह दी है। उसने पति-पत्नी को संयुक्त रिटर्न फाइल का विकल्प देने की सलाह दी है। अभी पति और पत्नी को अलग-अलग रिटर्न फाइल करना पड़ता है। फिलहाल नई कर व्यवस्था ही आयकर रिटर्न के लिए डिफॉल्ट व्यवस्था है। हालांकि, करदाता पुरानी कर व्यवस्था को भी चुन सकते हैं। दोनों में ही टैक्स की अलग-अलग स्लैब हैं जहां आमदनी बढ़ने के साथ-साथ कर की दर बढ़ती हैं। नई टैक्स व्यवस्था के तहत जहां तीन लाख रुपये सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं है, वहीं पुरानी टैक्स व्यवस्था में यह 2.5 लाख रुपये सालाना के लिए लागू है।

mint

विवाहितों पर बढ़ता है बोझ

बहुत से घरों में एक ही व्यक्ति नौकरी करता है। दूसरा जीवनसाथी घर की देखभाल करता है। कर प्रणाली में इसकी कोई कीमत नहीं मानी जाती है। ऐसे परिवारों पर कर का बोझ ज्यादा पड़ता है। मौजूदा समय में हर व्यक्ति को आय पर अलग-अलग कर देना होता है। चाहे वह शादीशुदा ही क्यों न हो। पति-पत्नी दोनों को अलग-अलग बेसिक छूट, स्लैब और कटौतियां मिलते हैं। इस वजह से शादीशुदा होने के बावजूद दूसरे जीवनसाथी को कर छूट का पूरा फायदा नहीं मिल पाता है।

सरचार्ज पर भी राहत संभव

अभी 50 लाख रुपये से ज्यादा आय पर सरचार्ज लगता है, लेकिन संयुक्त कराधान में इसकी सीमा 75 लाख रुपये या ज्यादा की जा सकती है। इससे उच्च कर दायरे में आने वाले परिवारों को भी राहत मिलेगी। अगर यह प्रस्ताव लागू होता है, तो यह भारत के टैक्स सिस्टम में एक बड़ा और ऐतिहासिक बदलाव माना जाएगा। इससे कुल करयोग्य आय कम हो जाएगी और परिवार के पास खर्च करने के लिए ज्यादा पैसे बचेंगे।

इन देशों में है संयुक्त कराधान प्रणाली

अमेरिका, जर्मनी, स्पेन, पुर्तगाल जैसे कई देशों में शादीशुदा जोड़ों को संयुक्त कर रिटर्न दाखिल करने की सुविधा मिलती है। वहां परिवार को एक आर्थिक इकाई माना जाता है। भारत भी ऐसी प्रणाली से कर कानून आसान बना सकता है।

क्या है संयुक्त कराधान प्रणाली

इसका मतलब है कि शादीशुदा जोड़े अपनी कमाई को जोड़कर एक साथ आयकर रिटर्न फाइल करें। इसके लिए दोनों के पास पैन कार्ड होना जरूरी होगा। माना जा रहा है कि बुनियादी छूट सीमा को भी बढ़ाया जा सकता है। जैसे अभी अगर एक व्यक्ति को तीन लाख रुपये तक टैक्स छूट मिलती है, तो जॉइंट फाइलिंग में यह सीमा छह लाख रुपये या उससे ज्यादा हो सकती है। इससे मध्यम वर्गीय परिवार को सीधा फायदा मिलेगा। इसके अलावा आवास ऋण ब्याज, चिकित्सा बीमा और दूसरी कटौतियों को भी बेहतर तरीके से समायोजित किया जा सकेगा। अगर दोनों पति-पत्नी कमाते हैं, तो भी उन्हें अलग-अलग मानक कटौती मिलने की बात कही जा रही है।

बीते साल भारत से वाहन निर्यात 24 प्रतिशत बढ़ा

नई दिल्ली, एजेंसी। वाहन विनिर्माताओं के संगठन सियाम के ताजा आंकड़ों के अनुसार विदेशी बाजारों में कारों, दुपहिया वाहनों और वाणिज्यिक वाहनों की मजबूत मांग के कारण 2025 में भारत से वाहन निर्यात 24 प्रतिशत बढ़ा।

पिछले साल भारत से कुल निर्यात 24.1 प्रतिशत बढ़कर 63,25,211 इकाई हो गया, जबकि 2024 में यह 50,98,474 इकाई था। इस दौरान यात्री वाहनों का निर्यात 16 प्रतिशत बढ़कर 8,63,233 इकाई रहा, जो 2024 में 7,43,979 इकाई था।

- मोटरसाइकिल का निर्यात 27 प्रतिशत
- स्कूटर का निर्यात आठ प्रतिशत बढ़ा

उपयोगिता वाहनों का निर्यात पिछले साल सालाना आधार पर 32 प्रतिशत बढ़कर 4,27,219 इकाई रहा। इस दौरान यात्री कारों का निर्यात तीन प्रतिशत बढ़कर 4,25,396 इकाई हो गया।

भारतीय मिशनों को निर्यात बढ़ाने के दिशानिर्देश जारी

नई दिल्ली, एजेंसी। सरकार ने वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच बाजार विविधीकरण के जरिए निर्यात को बढ़ावा देने के प्रयासों के तहत विदेश में स्थित भारतीय मिशनों के लिए विशिष्ट दिशानिर्देश तैयार किए हैं।

एक अधिकारी ने बताया कि विदेश में मिशनों के लिए व्यापार प्रोत्साहन संबंधी इन दिशानिर्देशों में गैर-शुल्क बाधाओं का प्रबंधन, बाजार सहभागिता गतिविधियां, योजना एवं संसाधन प्रबंधन, व्यापार सूचना और बाजार अनुसंधान शामिल हैं। ये दिशानिर्देश इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि व्यापार के क्षेत्र में मेजबान देश के हितधारकों के लिए वाणिज्यिक प्रतिनिधि ही संपर्क के पहले बिंदु होते हैं।

कारोबारी विश्वास सूचकांक पांच तिमाही के उच्च स्तर पर

नई दिल्ली, एजेंसी। उद्योग मंडल सीआईआई का कारोबारी विश्वास सूचकांक वित्त वर्ष 2025-26 की तीसरी तिमाही में बढ़कर 66.5 के स्तर पर पहुंच गया है। आंकड़ों के अनुसार मांग, मुनाफे और निवेश की स्थिति में सुधार के चलते यह पांच तिमाही के उच्चतम स्तर पर है।

सर्वेक्षण के मुताबिक घरेलू मांग सबसे बड़ा कारक बनी हुई है। दो-तिहाई कंपनियों ने दूसरी तिमाही में बेहतर मांग दर्ज की, जबकि 72 प्रतिशत को तीसरी तिमाही में जीएसटी कटौती और त्योहारी खपत के कारण और अधिक वृद्धि की उम्मीद है। यह सूचकांक देश के विभिन्न क्षेत्रों में एमएसएमई सहित सभी औद्योगिक क्षेत्रों के नमूना सर्वेक्षण पर आधारित है।

यह सर्वे दिसंबर 2025 में किया गया था, जिसमें सार्वजनिक और निजी विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों से जुड़ी 175 कंपनियां शामिल थीं।

आम आदमी को फायदा

- रोजगार के अवसरों में वृद्धि
- नया कारोबारी निवेश बढ़ेगा
- स्थिरता से ब्याज में कटौती
- वस्तु-सेवा उपलब्धता में वृद्धि

इक्विटी कर में राहत बढ़ाने की मांग की

नई दिल्ली, एजेंसी। बाजार प्रतिभागियों ने 2026-27 के आम बजट से पहले सरकार से पूंजी बाजार कराधान को आसान बनाने का आग्रह किया है, जिसमें दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ (एलटीसीजी) पर उच्च छूट सीमा की मांग शामिल है।

उन्होंने सुझाव दिया कि सरकार को लेनदेन करों में और वृद्धि करने से बचना चाहिए। निवेशकों को अधिक राहत देने के लिए इक्विटी निवेश से होने वाले एलटीसीजी पर छूट सीमा को बढ़ाने की मांग की है। जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज ने कहा कि एलटीसीजी के लिए कर-मुक्त छूट सीमा को 1.25 लाख रुपये से बढ़ाकर दो लाख रुपये करना चाहिए।

एफपीआई की बिकवाली का सिलसिला जनवरी में भी जारी

नई दिल्ली, एजेंसी। अमेरिकी बॉन्ड प्रतिफल में बढ़ोतरी और डॉलर की मजबूती के बीच विदेशी निवेशकों ने इस महीने अब तक भारतीय शेयरों से 22,530 करोड़ रुपये से अधिक निकाले हैं।

यह निकासी 2025 में दर्ज की गई 1.66 लाख करोड़ रुपये की बिकवाली के बाद हुई। ऐसा मुद्रा की अस्थिरता, वैश्विक व्यापार तनाव और अमेरिकी शुल्क में बढ़ोतरी की आशंका तथा बाजार के ऊंचे मूल्यांकन के कारण हुआ।

एफपीआई के लगातार बिकवाली के दबाव ने 2025 के दौरान डॉलर के मुकाबले रुपये के मूल्य में लगभग पांच प्रतिशत की गिरावट लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

बीते पखवाड़े में रिटर्न की तस्वीर (% में)

सोना (एमसीएक्स)	5.22
चांदी (एमसीएक्स)	22.09
निफ्टी	-1.67
बैंक निफ्टी	0.86
सेंसेक्स	-1.94
रुपया	0.92

कारोबारी चर्चा

कंज्यूमर कनेक्ट इनिशिएटिव

आई.एम.ई. कॉलेज द्वारा स्वामी विवेकानंद की जयंती पर रन फॉर स्वदेशी का आयोजन

दिनांक 12 जनवरी को आई.एम.ई. कॉलेज द्वारा स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया। संस्थान द्वारा भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के निर्देशानुसार राष्ट्रीय जागरूकता आउटरीच कार्यक्रम "रन फॉर स्वदेशी" का आयोजन सफलतापूर्वक किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य युवाओं में स्वदेशी के प्रति जागरूकता, आत्मनिर्भर भारत, तथा विकसित भारत की भावना को प्रोत्साहित करना था। कार्यक्रम में महाविद्यालय के सभी संकाय सदस्य एवं छात्र-छात्राओं ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की।

कार्यक्रम की शुरुआत महाविद्यालय के प्रांगण में की गई जहां प्रतिभागियों ने स्वामी विवेकानंद जी के चित्रों, स्वदेशी का

महत्व, विकसित भारत तथा प्रेरणादायी उद्धरणों से युक्त हस्तलिखित स्लोगन चार्ट प्रदर्शित किए। इस कार्यक्रम के उपलक्ष्य में दोपहर 2:00 बजे महाविद्यालय से मोहन नगर की ओर लगभग 2 किलोमीटर की दौड़ आयोजित की गई, जिसमें छात्रों एवं शिक्षकों ने पूरे जोश और अनुशासन के साथ भाग लिया।

कीट विदेशी छात्रों को आकर्षित करने वाला देश का 5वां सर्वोत्तम विश्वविद्यालय बना

ओडिशा उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विदेशी छात्रों के लिए एक पसंदीदा हब के तौर पर तेजी से उभर रहा है। इसी ट्रेंड को दर्शाते हुए, कीट विदेशी छात्रों को आकर्षित करने वाला देश का 5वां सर्वोत्तम विश्वविद्यालय बन गया है। हाल ही में प्रकाशित हुई नीति आयोग की एक रिपोर्ट के मुताबिक, अंतरराष्ट्रीय छात्रों को आकर्षित करने के मामले में ओडिशा भारत के शीर्ष 10 राज्यों में शामिल है।

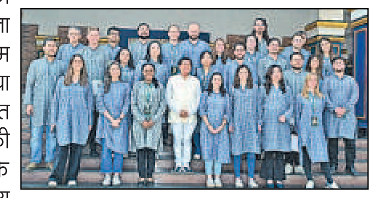

ओडिशा की भौगोलिक स्थिति पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जैसे पड़ोसी राज्यों से बेहतर है। इसीलिए, भुवनेश्वर कोलकाता और हैदराबाद से ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहा है। जैसा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 में उल्लिखित है, उच्च शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी गई है। हालांकि कीट ओडिशा के भुवनेश्वर में स्थित है जो एक टियर-II शहर है, लेकिन इस समय यह पूर्वी भारत के अलग-अलग विश्वविद्यालयों के कुल 2,362 विदेशी छात्रों में से 70 देशों के 2,000 से ज्यादा अंतरराष्ट्रीय छात्रों का आवास स्थल है और साथ ही 5,000 से ज्यादा विदेशी छात्रों का एक मजबूत वैश्विक एलुमनाई बेस भी है।

प्रो. अनुज कुमार चंदेल का जेयूआईटी वाकनाघाट दौरा, अंतरराष्ट्रीय शैक्षणिक सहयोग पर हुई अहम चर्चा

साओ पाउलो विश्वविद्यालय (यूएसपी), ब्राजील के प्रो. अनुज कुमार चंदेल ने 9-10 जनवरी 2026 को जेयूआईटी, वाकनाघाट का दो दिवसीय दौरा किया। इस दौरे का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय शैक्षणिक सहयोग, अनुसंधान साझेदारी और ज्ञान के आदान-प्रदान को सुदृढ़ करना रहा। प्रो. चंदेल ने कुलपति प्रो. (डॉ.) राजेंद्र कुमार शर्मा, डीन रिसर्च एंड इंटरनेशनलाइजेशन प्रो. सुधीर स्याल तथा विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों के साथ यूएसपी और जेयूआईटी के बीच संयुक्त अनुसंधान, संकाय एवं छात्र विनिमय कार्यक्रमों और शैक्षणिक साझेदारी के अवसरों पर विस्तृत चर्चा की। इस अवसर पर प्रो. स्याल ने सीईओ प्रो. मनु भास्कर गौर को सहयोग के लिए धन्यवाद दिया।

पीएनबी ने भारतीय सेना के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किया

सार्वजनिक क्षेत्र में भारत के अग्रणी बैंकों में से एक पंजाब नैशनल बैंक (पीएनबी) ने 13 जनवरी 2026 को भारतीय सेना के साथ अपने एमओयू का नवीनीकरण किया है। इस एमओयू के तहत पीएनबी अपनी प्रमुख योजना "पीएनबी रक्षक प्लस" के जरिए भारतीय सेना के सभी सेवारत कर्मियों व पेंशनभोगियों को बेहतर बीमा कवर व अन्य लाभों के साथ विभिन्न सेवाएं प्रदान करेगा। सेना मुख्यालय के एडिशनल जनरल पर्सनल सर्विसेज (एडीजीपीएस) निदेशालय, एडजुटेंट जनरल शाखा के कार्यालय में पीएनबी के कार्यपालक निदेशक श्री बिभु प्रसाद महापात्र

और भारतीय सेना की ओर से महानिदेशक मैनपावर प्लानिंग एंड पर्सनल सर्विसेज (डीजी एमपी एंड पीएस) लेफ्टिनेंट जनरल राजीव पुरी, एवीएसएम, वीएसएम की उपस्थिति में एमओयू का आदान-प्रदान किया गया।

अपना देश

आतंकी फंडिंग में 'क्रिप्टो हवाला' का प्रयोग

श्रीनगर/नई दिल्ली, एजेंसी। सुरक्षा एजेंसियों ने जम्मू-कश्मीर में आतंक और अलगाववादी गतिविधियों को दोबारा सक्रिय करने की एक नई साजिश का खुलासा किया है।,

एजेंसियों के मुताबिक, विदेशी फंडिंग के लिए अब पारंपरिक हवाला की जगह अत्याधुनिक 'क्रिप्टो हवाला' नेटवर्क का इस्तेमाल किया जा रहा है।

अधिकारियों का कहना है, यह नेटवर्क देश की वित्तीय निगरानी व्यवस्था को चकमा देकर बिना पहचान के विदेशी पैसा घाटी तक पहुंचा रहा है। इस धन का इस्तेमाल उन अलगाववादी तत्वों को दोबारा मजबूत करने के लिए किया जा रहा है, जिन्हें पिछले कुछ वर्षों में पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई से लगभग निष्क्रिय कर दिया गया था।

चीन-मलेशिया से ट्रांसफर क्रिप्टो नकद में बदल रहे : चीन, मलेशिया, म्यांमार और कंबोडिया जैसे देशों में बैठे हैंडलर स्थानीय लोगों को बिना केवाईसी वाले निजी क्रिप्टो वॉलेट बनाने के लिए उकसा रहे हैं। इन वॉलेट को वीपीएन से संचालित किया जाता है, ताकि पहचान और लोकेशन छिपी रहे। विदेशी हैंडलर सीधे इन वॉलेट में क्रिप्टोकरेंसी ट्रांसफर करते हैं। इसके बाद, वॉलेट धारक दिल्ली या मुंबई जैसे शहरों में जाकर पीयर-टू-पीयर (पी2पी) ट्रेडरों के माध्यम से क्रिप्टो को नकद में बदल लेते हैं। इस प्रक्रिया में डिजिटल लेनदेन और नकद के बीच का पूरा वित्तीय सुराग टूट जाता है। 'म्यूल अकाउंट' से लेनदेन को छिपा लिया जाता है।

- पारंपरिक हवाला नेटवर्क की जगह अत्याधुनिक तरीका
- वित्तीय एजेंसियों को चकमा देकर घाटी में पहुंच रही फंडिंग

वीपीएन के इस्तेमाल पर सख्ती की गई

सुरक्षा एजेंसियों ने चेतावनी दी है कि 'क्रिप्टो हवाला' ऑफ-एक्सचेंज और ग्रे मार्केट में काम करता है। इससे मनी लॉन्ड्रिंग कानूनों से बच निकलना आसान हो जाता है। इसी खतरे को देखते हुए जम्मू-कश्मीर में वीपीएन के इस्तेमाल पर भी सख्ती की गई है।

'मैजिकविन' के खिलाफ चार्जशीट

नई दिल्ली, एजेंसी। प्रवर्तन निदेशालय ने ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप 'मैजिकविन' के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

सट्टेबाजी ऐप के निदेशक पाकिस्तानी नागरिक हैं और यूएई में रहते हैं। मैजिकविन के खिलाफ मामले में 14 लोगों और कंपनियों को आरोपी बनाया गया है। ईडी ने यह जांच अहमदाबाद साइबर क्राइम पुलिस द्वारा मैजिकविन और अन्य के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी के आधार पर शुरू की थी।

नया ट्रेंड | सोने-चांदी की बढ़ती कीमतों ने जेवरों को खुशी नहीं तनाव का कारण बनाया, अंगूठी-कान के बाले और हाथ के कड़े जैसे उपहार पहुंच से बाहर

शादी-ब्याह में सोने के बदले सोना नहीं, नगद दे रहे उपहार

■ आशीष दीक्षित

कानपुर। कानपुर माल रोड निवासी व्यापारी मुकेश कुमार के करीबी दोस्त के घर शादी है। तीन साल पहले मुकेश की बहन की शादी में इसी दोस्त ने सोने की अंगूठी उपहार में दी थी।

अब जब व्यवहार की बारी आई तो मुकेश असमंजस में हैं। वे कहते हैं कि मौजूदा भाव पर अगर उतने ही वजन की अंगूठी उपहार में दी जाए, तो बजट बिगड़ जाएगा। वजह साफ है, उस समय के मुकाबले आज अंगूठी के दाम तीन से चार गुना तक बढ़ चुके हैं। यह मजबूरी सिर्फ मुकेश की नहीं, बल्कि आज हजारों मध्यम वर्गीय परिवारों की हकीकत बन चुकी है।

सोने-चांदी की बढ़ती कीमतों ने समाज के ताने-बाने को झकझोर कर रख दिया है। जो जेवर कभी रिश्तों में मिठास और अपनापन घोलते थे, वही अब तनाव, असहजता शिकायतों की वजह बनते जा रहे हैं। हालात यह हैं कि लोग चाहकर भी सोने-चांदी के जेवर उपहार में नहीं दे पा रहे। आखिर मजबूरी में नकद का सहारा लेना पड़ रहा है। बीते दो से तीन वर्षों में सोने-चांदी के दामों में आई तेज उछाल ने मामूली गहनों की कीमतें चार गुना तक बढ़ा दी हैं। सहालग के मौसम में भी पायल-बिछिया जैसी पारंपरिक चीजों की मांग में करीब 70 फीसदी तक गिरावट आ चुकी है। सोने की अंगूठी, कान के बाले और हाथ के कड़े जैसे उपहार अब आम परिवार की पहुंच से बाहर होते जा रहे हैं।

70 फीसदी गिरावट सहालग में पायलों की मांग में आई

02 से 3 साल में चार गुना तक बढ़ गए मामूली गहने के दाम

30 फीसदी हिस्सा उपहार आइटम का रहता था बाजार में

मध्यम वर्ग पर सर्वाधिक पड़ा असर

सराफा कारोबार पुष्पेंद्र जायसवाल कहते हैं कि महंगाई का सबसे गहरा असर मध्यम वर्ग पर पड़ा है। सीमित आय, बढ़ती जिम्मेदारियां और सामाजिक अपेक्षाओं के बीच परिवार असमंजस में हैं। कई घरों में यह बात अब चुभने लगी है कि 'पहले उनके यहां शादी थी तो हमने दिया था, अब अपने घर में है'। यह तुलना रिश्तों में धीरे-धीरे खटास घोल रही है। सराफा बाजार भी इस बदलाव से अछूता नहीं है।

बाजार में पहले जैसी रौनक नहीं

कानपुर सराफा कमेटी नयागंज के पूर्व महामंत्री नटवर मिश्रा कहते हैं कि उनके कुल कारोबार का लगभग 30 फीसदी हिस्सा उपहार आइटम पर निर्भर रहता था, जो अब सिमट रहा है। सहालग के बावजूद बाजार में पहले जैसी रौनक नहीं दिख रही। ग्राहक पूछताछ तो करते हैं, लेकिन कीमत सुनते ही कदम पीछे खींच लेते हैं। व्यापारियों के अनुसार अब बाजार के भाव सीधे पारिवारिक फैसलों को प्रभावित कर रहे हैं।

चिंतन

जनहित को राजनीति से ऊपर रखें राज्य सरकारें

भारत का संघीय लोकतंत्र केंद्र और राज्यों के सहयोग पर आधारित है। संविधान की मूल भावना यह है कि केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर जनता के हित में काम करें और जनकल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दें, लेकिन बीते कुछ वर्षों में यह सहयोग कई बार राजनीतिक टकराव में बदलता दिखाई देता है। हाल ही में पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ममता बनर्जी सरकार पर आरोप लगाया कि राज्य में केंद्र सरकार की योजनाएं लागू नहीं की जा रहीं, जिससे लोग उनके लाभ से वंचित रह जा रहे हैं। यह आरोप केवल बंगाल तक सीमित नहीं है, बल्कि केरल, तेलंगाना, तमिलनाडु और पंजाब जैसे गैर-भाजपा शासित राज्यों पर भी केंद्र की योजनाओं की अनदेखी के आरोप लगते रहे हैं। इससे पहले दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार और केंद्र के बीच भी नीतियों को लेकर लगातार खींचतान देखने को मिली थी। केंद्र सरकार की योजनाएं देश के सभी नागरिकों को ध्यान में रखकर बनाई जाती हैं। आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, जल जीवन मिशन या किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं का उद्देश्य यह है कि सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों तक सरकारी मदद पहुंचे। इन योजनाओं के लिए धन पूरे देश के करदाताओं से आता है। ऐसे में यदि कोई राज्य सरकार राजनीतिक कारणों से इन्हें लागू नहीं करती या आधे-अधूरे मन से लागू करती है, तो यह सीधे-सीधे जनता के अधिकारों पर चोट है। गैर-भाजपा शासित राज्यों का तर्क अक्सर यह होता है कि केंद्र योजनाओं के नाम पर राज्यों पर अपनी नीतियां थोपना चाहता है, या फिर वह राज्यों को पर्याप्त वित्तीय सहायता नहीं देता। कुछ राज्यों का यह भी कहना है कि उनके पास पहले से बेहतर या समानांतर योजनाएं मौजूद हैं, इसलिए वे केंद्र की योजनाओं को लागू करना जरूरी नहीं समझते। यह तर्क कुछ हद तक समझ में आता है, लेकिन सवाल यह है कि क्या इन राजनीतिक और प्रशासनिक मतभेदों की कीमत आम जनता को चुकानी चाहिए? हकीकत यह है कि जब केंद्र और राज्य सरकारें आमने-सामने खड़ी हो जाती हैं, तो सबसे ज्यादा नुकसान गरीब, किसान, मजदूर, महिलाएं और बच्चे उठाते हैं। यदि किसी राज्य में स्वास्थ्य योजना लागू नहीं होती, तो उसका खामियाजा बीमार और असहाय व्यक्ति को भुगतना पड़ता है। अगर आवास या पोषण से जुड़ी योजनाएं रोकी जाती हैं, तो उसका असर सीधे जीवन स्तर पर पड़ता है। आम नागरिक के लिए यह मायने नहीं रखता कि योजना केंद्र की है या राज्य की, उसके लिए अहम यह है कि मदद समय पर मिले। प्रधानमंत्री द्वारा बंगाल में ममता सरकार पर किया गया हमला इसी पृष्ठभूमि में देखा जाना चाहिए। राज्य सरकारों को यह समझना होगा कि लोकतंत्र में सत्ता अस्थायी होती है, लेकिन जनता की जरूरतें स्थायी। जनभावना से राजनीति को दूर रखना आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। यदि किसी योजना में खामियां हैं, तो उसे बेहतर बनाने के लिए केंद्र से संवाद किया जाना चाहिए, न कि उसे पूरी तरह ठुकरा दिया जाए। राज्य चाहें तो योजनाओं में स्थानीय जरूरतों के अनुसार बदलाव करें, उनका नाम बदलें या उन्हें अपनी योजनाओं के साथ जोड़ें, लेकिन लाभ लोगों तक पहुंचना चाहिए। कुल मिलाकर लोकतंत्र की सफलता इसी में है कि केंद्र और राज्य मिलकर काम करें। राजनीति अगर जनहित पर भारी पड़ेगी, तो उसका नुकसान पूरे देश को उठाना पड़ेगा।

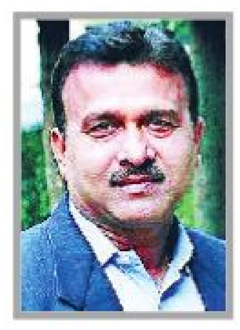

जनसमस्या
सुशील देव

आखिर क्या हैं पेयजल संकट के उपाय

> ग्रामीण भारत से लेकर महानगरों तक, पेयजल की समस्या किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रही। कई गांवों में आज भी हैंडपंप सूख चुके हैं या उनका पानी फ्लोराइड, आर्सेनिक और आयरन जैसे खतरनाक तत्वों से दूषित है। शहरी इलाकों में पाइपलाइन से पानी तो आता है, लेकिन उसकी गुणवत्ता संदिग्ध रहती है। गरीब बस्तियों में लोग मजबूरी में गंदा पानी पीने को विवश हैं, जिसका सीधा असर उनके स्वास्थ्य पर पड़ता है। नीति आयोग की कई रिपोर्ट बताती हैं कि देश की बड़ी आबादी गंभीर जल संकट से जूझ रही है। साफ पानी केवल सुविधा नहीं, बल्कि नागरिकों का मौलिक अधिकार है और इसे सुनिश्चित करना सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है।

देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर की हालिया घटना ने हर किसी को साफ पेयजल के मसले पर सोचने को मजबूर किया है। यह कड़वा सच है कि देश के कई हिस्सों में आज भी जनता को साफ और सुरक्षित पीने का पानी नसीब नहीं है। यह स्थिति उस भारत में है, जो चंद्रयान से लेकर डिजिटल क्रांति तक अपनी उपलब्धियों पर गर्व करता है। साफ पानी जीवन की सबसे बुनियादी जरूरत है, लेकिन दुर्भाग्यवश यह जरूरत करोड़ों लोगों के लिए अब भी एक सपना बनी हुई है। सरकारें बदलती रहीं, योजनाएं आती-जाती रहीं, पर जमीनी हकीकत यह है कि सरकारी उदासीनता और नीतियों के कमजोर क्रियान्वयन ने पेयजल संकट को और गहरा ही किया है।

ग्रामीण भारत से लेकर महानगरों तक, पेयजल की समस्या किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रही। कई गांवों में आज भी हैंडपंप सूख चुके हैं या उनका पानी फ्लोराइड, आर्सेनिक और आयरन जैसे खतरनाक तत्वों से दूषित है। शहरी इलाकों में पाइपलाइन से पानी तो आता है, लेकिन उसकी गुणवत्ता संदिग्ध रहती है। गरीब बस्तियों में लोग मजबूरी में गंदा पानी पीने को विवश हैं, जिसका सीधा असर उनके स्वास्थ्य पर पड़ता है। नीति आयोग की कई रिपोर्ट बताती हैं कि देश की बड़ी आबादी गंभीर जल संकट से जूझ रही है। बावजूद इसके इस संकट को राजनीतिक प्राथमिकता के रूप में नहीं देखा गया। चुनावी भाषणों में बड़े-बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन चुनाव बीतते ही पेयजल जैसे मुद्दे हाशिये पर चले जाते हैं। पेयजल संकट के लिए प्राकृतिक कारणों को जिम्मेदार ठहराना आसान है, लेकिन सच यह है कि सरकारों की उदासीनता ने इस समस्या को और विकराल बनाया है। कई राज्यों में जलापूर्ति से जुड़ी योजनाएं वर्षों से अधूरी पड़ी हैं। कहीं बजट की कमी का रोना है, तो कहीं भ्रष्टाचार और लाल फीताशाही ने योजनाओं की गति रोक रखी है। ग्रामीण जल आपूर्ति योजनाओं का हाल यह है कि नल तो लगा दिए गए, लेकिन उनमें पानी नहीं है। "हर घर नल से जल" जैसे अभियानों की घोषणाएं भले ही प्रभावशाली हों, पर अनेक गांवों में ये योजनाएं केवल सरकारी फाइलों और आंकड़ों तक सीमित हैं। जमीनी स्तर पर न तो नियमित जल आपूर्ति है और न ही गुणवत्ता की प्रभावी जांच।

भारत में जल से जुड़ी नीतियों की कमी नहीं है। समस्या उनके क्रियान्वयन की है। जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन और भूजल प्रबंधन से संबंधित कानून और दिशा-निर्देश मौजूद हैं, लेकिन उनका पालन कराने की इच्छाशक्ति का अभाव है। शहरी क्षेत्रों में वर्षा जल संचयन को अनिवार्य करने के नियम बने, पर अधिकतर भवनों में इनका पालन नहीं होता। औद्योगिक इकाइयां नदियों और जलस्त्रोतों में बेधड़क प्रदूषित पानी छोड़ रही हैं। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या तो मूकदर्शक बने रहते हैं या कार्रवाई के नाम पर औपचारिकताएं निभाई जाती हैं। नतीजा यह है कि जो पानी उपलब्ध है, वह भी पीने योग्य नहीं रह गया। साफ पेयजल की कमी का सबसे बड़ा असर गरीब और वंचित तबकों पर पड़ता है। दूषित पानी से डायरिया, टाइफाइड, पीलिया जैसी बीमारियां आम हैं। हर साल हजारों बच्चे केवल इसलिए अपनी जान गंवा देते हैं क्योंकि उन्हें स्वच्छ पानी उपलब्ध नहीं हो पाता। यह एक गंभीर मानवीय संकट है, जिसे अक्सर आंकड़ों

में छिपा दिया जाता है। सामाजिक दृष्टि से भी जल संकट असमानता को बढ़ाता है। जिनके पास पैसे हैं, वे बोतलबंद पानी या टैंकर खरीद लेते हैं, लेकिन गरीबों के पास कोई विकल्प नहीं होता।

कई जगहों पर पानी को लेकर सामाजिक तनाव और टकराव की स्थिति बन रही है, जो भविष्य के लिए खतरनाक संकेत है। पेयजल आपूर्ति की जिम्मेदारी केंद्र और राज्य सरकार दोनों पर है। केंद्र सरकार योजनाएं बनाती है, बजट आवंटित करती है, लेकिन राज्यों में उनके क्रियान्वयन की स्थिति अक्सर निराशाजनक रहती है। कई बार राजनीतिक खींचतान के कारण भी योजनाएं प्रभावित होती हैं। जल जैसे संवेदनशील विषय पर भी राजनीति हावी हो जाती है, जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है। स्थानीय निकायों और पंचायतों को पर्याप्त अधिकार और संसाधन नहीं दिए जाते, जबकि जल प्रबंधन में उनकी भूमिका सबसे अहम हो सकती है, क्योंकि बिना स्थानीय सहभागिता के कोई भी योजना सफल नहीं हो सकती। सरकार अक्सर संकट के समय तात्कालिक उपायों का सहारा लेती हैं। टैंकर भेज दिए जाते हैं, बोरिंग करवा दी जाती है, लेकिन ये समाधान स्थायी नहीं हैं। दीर्घकालिक योजना और गंभीरता का अभाव साफ झलकता है। जल संरक्षण और स्त्रोतों के पुनर्जीवन पर जितना काम होना चाहिए था, उतना नहीं हुआ। पेयजल संकट से निपटने के लिए सबसे पहले सरकार को इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देनी होगी। नीतियों को कागज से निकालकर जमीन पर उतारना होगा। योजनाओं की नियमित निगरानी, पारदर्शिता और जवाबदेही तय करनी होगी। जल की गुणवत्ता की जांच और उसके सार्वजनिक आंकड़े उपलब्ध कराए जाने चाहिए। साथ ही, जनता की भागीदारी भी जरूरी है। अभी तक हम पानी का उपयोग अनुशासित ढंग से नहीं कर पा रहे हैं।

जरूरत से ज्यादा पानी का नुकसान करना तो जैसे हमारी आदत बन गई हो। ऐसे में हमारी भावी पीढ़ी के लिए भी जल की उपलब्धता सुनिश्चित हो, इसके लिए हमें कई कदम उठाने होंगे; जैसे घरेलू स्तर पर जल का उचित व संयमित उपयोग एवं उद्योगों में पानी के चक्रीय उपयोग जल संरक्षण में सहायक हो सकते हैं। इस्तेमाल किए हुए पानी का फिर से शौचालयों अथवा बगीचों में फिर से इस्तेमाल और रिसाइकिलिंग करके जल का सदुपयोग कैसे करना है, इस दिशा में जन-जागरूकता बढ़ायी जाए। वर्षा-जल का संग्रहण करके हम पानी को बचा सकते हैं। विभिन्न जलाशयों का निर्माण करके उनमें जल संग्रह करना जल संसाधन का सबसे पुराना उपाय है, इसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है। भूमिगत जल संरक्षण के लिए भूमिगत जल का कृत्रिम रूप से पुनर्भरण किया जा सकता है टपकन टैंक/ड्रिप/स्प्रिंकल सिंचाई के उपयोग से सिंचाई जल के संरक्षण को बढ़ावा दिया जा सकता है।वर्षा जल संचयन, जल पुनर्भरण और पानी के विवेकपूर्ण उपयोग को जन आंदोलन का रूप देना होगा। भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में पेयजल केवल एक प्राकृतिक संसाधन नहीं, बल्कि जीवन, विकास और सामाजिक न्याय से जुड़ा बुनियादी प्रश्न है। देश में साफ पेयजल की समस्या केवल संसाधनों की कमी का सवाल नहीं है, बल्कि यह शासन की संवेदनशीलता और नीतिगत ईमानदारी की भी परीक्षा है। सरकार की उदासीनता और क्रियान्वयन में लापरवाही ने इस संकट को बढ़ाया है, इसमें कोई संदेह नहीं। यदि अब भी चेतने का समय नहीं आया, तो आने वाले वर्षों में जल संकट एक भयावह सामाजिक और मानवीय त्रासदी का रूप ले सकता है। साफ पानी केवल सुविधा नहीं, बल्कि नागरिकों का मौलिक अधिकार हैं और इसे सुनिश्चित करना सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है।

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

लेख पर अपनी प्रतिक्रिया **haribhoomi@gmail.com** पर दे सकते हैं।

दिवस विशेष

सुनील कुमार महला

प्राकृतिक आपदाओं के बीच एनडीआरएफ की भूमिका

राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) का स्थापना दिवस 19 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि वर्ष 2006 में इसी दिन एनडीआरएफ का गठन किया गया था। यह बल प्राकृतिक व मानव-निर्मित आपदाओं में राहत और बचाव कार्य के लिए जाना जाता है। एनडीआरएफ का आदर्श वाक्य 'आपदा सेवा सदैव सर्वत्र' है, जिसका अर्थ है-'किसी भी आपदा में, हमेशा और हर जगह सेवा के लिए तत्पर।' प्राकृतिक व मानव-निर्मित आपदाएं वे घटनाएं हैं जो व्यापक स्तर पर जीवन, संपत्ति और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती हैं। भूकंप, बाढ़, सूखा, चक्रवात, तूफान, भूस्खलन, हिमस्खलन, जंगल की आग, सुनामी, बादल फटना, लू और शीत लहर आदि प्राकृतिक आपदाएं तथा औद्योगिक दुर्घटनाएं, रासायनिक/गैस रिसाव, परमाणु दुर्घटनाएं, आग लगना, इमारत या पुल गिरना, तेल रिसाव, खनन हादसे, रेल-सड़क-हवाई दुर्घटनाएं, आतंकवादी हमले और युद्ध मानव-निर्मित आपदाएं हैं। वास्तव में प्राकृतिक आपदाएं प्रकृति की प्रक्रियाओं के कारण होती हैं, जिन पर मानव का सीधा नियंत्रण नहीं होता, वहीं दूसरी ओर मानव-निर्मित आपदाएं मानवीय गतिविधियों, लापरवाही या तकनीकी विफलताओं के कारण उत्पन्न होती हैं।

संक्षेप में कहें तो जहां एक ओर प्राकृतिक आपदाएं प्रकृति से आती हैं, वहीं, दूसरी ओर मानव-निर्मित आपदाएं मानव की गलतियों या क्रियाओं का परिणाम होती हैं। दोनों ही हमारे समाज, देश व अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव डालती हैं। वास्तव में आपदा प्रबंधन राष्ट्रीय प्राथमिकता है और भारत सरकार ने देश में आपदाओं से निपटने की व्यवस्था को आधुनिक और मजबूत बनाने के उद्देश्य से अगस्त 1999 में एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया। बाद में गुजरात भूकंप की विभीषिका को देखते हुए एक राष्ट्रीय समिति भी बनाई। इन समितियों का मुख्य लक्ष्य केवल राहत कार्य तक सीमित न रहकर, भविष्य की आपदाओं के लिए ठोस पूर्व-तैयारी करना और नुकसान को कम करने के लिए एक प्रभावी सरकारी ढांचा तैयार करना था। इन पहलों का उद्देश्य भारत में आपदा प्रबंधन को एक व्यवस्थित और वैज्ञानिक रूप देना था ताकि जान-माल की क्षति को न्यूनतम किया जा सके। दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-07) के दस्तावेज़ में पहली बार, आपदा प्रबंधन पर एक विस्तृत अध्याय जारी किया गया था और अंततः 23 दिसंबर, 2005 को भारत सरकार द्वारा 'आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005' को अधिनियमित किया गया, जिसके तहत 'राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण' (एन.डी.एम.ए.) एवं 'राष्ट्रीय आपदा मोचन बल' (एन.डी.आर.एफ.) का गठन किया गया। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) भारत में आपदा प्रबंधन के लिए गठित एक सर्वोच्च संस्था है, जिसकी स्थापना 'आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005' के अंतर्गत की गई थी। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कार्य करने वाला यह निकाय देश में आपदाओं से निपटने के लिए मुख्य नीतियां, योजनाएं और दिशा-निर्देश तैयार करने हेतु उत्तरदायी है। इसका प्राथमिक उद्देश्य एक ऐसी एकीकृत और रणनीतिक प्रणाली विकसित करना है, जो संकट के समय समय पर और प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित कर जान-माल के नुकसान को न्यूनतम कर सके। वास्तव में इस संस्था का मुख्य लक्ष्य आधुनिक तकनीक और सभी वर्गों की भागीदारी के माध्यम से भारत को आपदाओं के प्रति सुरक्षित और सक्षम बनाना है। यह केवल संकट आने का इंतज़ार करने के बजाय पहले से सतर्क रहने (प्रो-एक्टिव) और विकास कार्यों को आपदा-रोधी बनाने की रणनीति पर ज़ोर देती है। इसका उद्देश्य समाज में एक ऐसी संस्कृति विकसित करना है, जहां आपदाओं को रोकने, उनकी पूर्व-तैयारी करने और उनके प्रभाव को कम करने (शमन) को प्राथमिकता दी जाए, ताकि देश का विकास टिकाऊ बना रहे। बहरहाल, बता दें कि वर्तमान में एनडीआरएफ में कुल 16 बटालियन हैं। प्रत्येक बटालियन में लगभग 1,149 कर्मी होते हैं। दरअसल, एनडीआरएफ एक विशेषज्ञ बल है जिसमें भारत के विभिन्न केंद्रीय अर्धसैनिक बलों (सीएपीएफ) से जवानों को प्रतिनियुक्ति (डेपुटेशन) पर लिया जाता है। एनडीआरएफ स्थापना दिवस हमें यह स्मरण कराता है कि आपदा के समय त्वरित, संगठित और मानवीय प्रतिक्रिया कितनी आवश्यक है। एनडीआरएफ का योगदान सुरक्षित, सक्षम और संवेदनशील भारत के निर्माण में अत्यंत महत्वपूर्ण है और एनडीआरएफ का स्थापना दिवस भारत की उस अदम्य इच्छाशक्ति का उत्सव है, जो यह सुनिश्चित करती है कि देश किसी भी विपदा के सामने घुटने नहीं टेकेगा, बल्कि और अधिक मजबूती से उठ खड़ा होगा।

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

यमदूतों को देख डर जाता है व्यक्ति

संकलित
दर्शन

गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद के रहस्य, आत्मा की यात्रा, पाप-पुण्य, स्वर्ग और नरक के बारे में विस्तार से बताया गया है। संसार का ये नियम अटल है कि जिसने जन्म लिया है, उसकी मृत्यु भी तय है। जन्म और मृत्यु दो वो छोर हैं, जिनकी प्रक्रियाएं एक दूसरे से बहुत अलग हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार, मृत्यु के समय व्यक्ति के शरीर में जो हलचल होती है वो उसके कर्मों और उसकी मानसिक स्थिति पर निर्भर करती है। गरुड़ पुराण में आंखों के पलटने के पीछे कुछ प्रमुख वजहें बताई गई हैं, जिस व्यक्ति को जीवनकाल में सांसारिक सुखों, धन-संपत्ति और परिवार का अधिक मोह रहता है, उसके लिए प्राण त्यागना बहुत कष्टकारी होता है। गरुड़ पुराण कहता है मृत्यु के पास आने पर भी ऐसा व्यक्ति संसार नहीं छोड़ना चाहता। उसमें जीने की इच्छा रहती है। यही इच्छा उसे शरीर से बांधकर रखती है, इसलिए जब शरीर से प्राण खींचे जाते हैं, तो आंखें ऊपर की ओर उलट जाती हैं। वहीं शास्त्रों में बताया गया है कि जब यमदूत आत्मा को लेने आते हैं, तो उनका स्वरूप देखकर मरणासन्न व्यक्ति डर जाता है। वो कुछ कहना चाहता है, लेकिन उसकी आवाज गले में अटक जाती है। डर में उसकी पुतलियां फैल जाती हैं और आंखें उलट जाती है. यमदूत जब बल से आत्मा को शरीर से निकालते हैं, तो भी ऐसी अवस्था हो जाती है, वहीं जब प्राण मस्तक या आखों से निकलते हैं, तो भी आंखें पलट जाती हैं।

अपनी बुराई सुनकर परेशान न हों

संकलित
प्रेरणा

एक लोक कथा के अनुसार पुराने समय में एक संत अपने शिष्य के साथ एक गांव में रुके। कुछ ही दिनों संत की ख्याति आसपास के क्षेत्र में फैल गई। अब उनके प्रवचन सुनने और दर्शन करने के लिए दूर-दूर से लोग आने लगे। ये देखकर उसी गांव का एक अन्य पंडित परेशान हो गया। उसे लगने लगा कि इस संत की वजह से मेरे भक्त कम हो जाएंगे। मेरा जीवन यापन कैसे होगा? पंडित ने संत का दुष्प्रचार करना शुरू कर दिया। वह लोगों के सामने उस संत की बुराई करता था। एक दिन संत के शिष्य को ये सारी बातें मालूम हुईं तो उसे बहुत गुस्सा आया। वह तुरंत ही अपने गुरु के पास पहुंचा और पूरी बात बताई। संत ने शिष्य की बातें सुनी और कहा कि उसे छोड़ो। अगर मैं उस पंडित से वाद-विवाद करूंगा तो इससे ये सब बातें फैलना बंद नहीं होंगी। इसीलिए उसकी बातें पर ध्यान नहीं देना चाहिए। संत ने देखा कि शिष्य का क्रोध शांत नहीं हुआ है। तब उन्होंने कहा कि जब जंगल का हाथी गांव में आता है तो उसे देखकर सभी कुत्ते भौंकने लगते हैं, लेकिन हाथी पर इसका कोई असर नहीं होता है। हाथी अपनी मस्त चाल चलते रहता है। कुत्ते भौंकते हुए थक जाते हैं और वापस अपने इलाके की ओर भाग जाते हैं। हमें भी अपनी बुराई करने वालों के साथ इसी तरह पेश आना चाहिए। हमें सिर्फ अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए और सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। हमारे अच्छे काम ही ऐसे लोगों का मुंह बंद कर सकते हैं।

अंतर्मन

आज की पाती

सड़क पर मवेशी

राजधानी रायपुर में आवारा कुत्तों के साथ ही अब मवेशी लोगों की परेशानी का सबब बने हुए हैं। रायपुर में जिस ओर भी जाएं, सड़क पर मवेशी नजर आते हैं। नगर निगम का अमला कुछ दिन कार्रवाई करता है और शांत हो जाता है। ऐसे में सड़क पर चलने वाले दोपहिया और चार पहिया वाहन चालकों को दिक्कत होती है। आए दिन सड़क हादसे की वजह सड़क पर मवेशी बनते हैं।

-शाहिन बेगम, रायपुर

ट्रेंड

घुसपैठियों पर एक्शन

डबल इंजन सरकार बनते ही पश्चिम बंगाल में घुसपैठियों के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया जाएगा। इसके साथ ही मतुआ और नामशूद्र जैसे शरणार्थियों को पूरी सुरक्षा देकर उनकी बस्तियों में विकास को गति दी जाएगी, ये मोदी की गारंटी है।

- नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

नाकाम व्यवस्था दोषी

माघमेला क्षेत्र में इस साल फिर से साधु-संतों-भक्तों के साथ हुआ दुर्व्यवहार अक्षम्य है। प्रश्न ये है कि ऐसी घटनाएं भाजपा की सरकार में ही क्यों हो रही हैं। इस अवस्था के लिए भाजपा का कुशासन और नाकाम व्यवस्था ही दोषी है।

- अखिलेश यादव, सांसद, सपा

दुर्भाग्यपूर्ण घटना

वाराणसी में अहिल्याबाई होल्कर की मूर्ति को हटाने की ख़बर से समाज के एक बड़े वर्ग में काफी रोष व आक्रोश व्याप्त है। इस अति-दुर्भाग्यपूर्ण घटना को लेकर सरकार को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।

- मायावती, पूर्व सीएम, उप्र

जनता पर विश्वास

हमें पूरा विश्वास है कि तमिलनाडु की जनता आरएसएस-भाजपा की कट्टरता, सांप्रदायिकता और भेदभावपूर्ण राजनीति के बजाय समानता, सामाजिक न्याय, सशक्तिकरण और सुशासन को चुनेगी। कांग्रेस जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

-मल्लिकार्जुन खरगे, अध्यक्ष, कांग्रेस

करंट अफेयर

गैलेक्सीआई 'मिशन दृष्टि' के लिए तैयार

अंतरिक्ष क्षेत्र का स्टार्टअप गैलेक्सीआई अपनी तरह के पहले उपग्रह को प्रक्षेपित करने की तैयारी में है जो 'ऑप्टिकल' और 'रडार सेंसर' से प्राप्त आंकड़ों को एकीकृत कर पृथ्वी की तस्वीरें तैयार करेगा। इन तस्वीरों का उपयोग रक्षा से लेकर कृषि तक कई क्षेत्रों में किया जा सकेगा। स्टार्टअप की इस वर्ष की पहली तिमाही में 'मिशन दृष्टि' नामक बहु-संवेदी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को प्रक्षेपित करने और 2030 तक इसे 10 उपग्रहों के एक समूह में विस्तारित करने की योजना है। गैलेक्सीआई के सह-संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) सुयश सिंह ने कहा, मिशन दृष्टि वैश्विक स्तर पर पहला ऐसा उपग्रह है, जिसमें एक ही प्लेटफॉर्म पर रडार सेंसिंग और ऑप्टिकल इमेजिंग को एकीकृत किया गया है। इसके साथ ही यह भारत का निजी तौर पर विकसित सबसे बड़ा उपग्रह भी है। सिंह ने बताया कि गैलेक्सीआई अगले कुछ वर्षों में दो और उपग्रह तैनात करने की योजना बना रहा है और दशक के अंत तक छह-सात अतिरिक्त उपग्रह जोड़कर कुल संख्या 2030 तक 10 करने का लक्ष्य है। इससे बड़े पैमाने पर लगभग तुरंत डेटा उपलब्ध कराया जा सकेगा। जहां मल्टी-स्पेक्ट्रल ऑप्टिकल कैमरा पृथ्वी की तस्वीरें लेता है।

ऑफ बीट

'काजीरंगा कॉरिडोर' से वन्यजीवों की होगी सुरक्षा

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी रविवार को जिस 'काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर' परियोजना की आधारशिला रखेंगे, उसका उद्देश्य राष्ट्रीय उद्यान में वन्यजीवों का सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करना और 'इकोटूरिज्म' को बढ़ावा देना है। 'इकोटूरिज्म' से तात्पर्य प्राकृतिक क्षेत्रों में ऐसे पर्यटन से है जिससे स्थानीय वन्य जीवन एवं पर्यावरण को संरक्षित रखा जा सके और उन्हें लाभ पहुंचे। मोदी ने कहा कि 6,957 करोड़ रुपये की यह परियोजना राष्ट्रीय राजमार्ग-37 पर दुर्घटनाओं को कम करने में भी मदद करेगी। एक अधिकारी ने बताया कि परियोजना के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग-37 (नया राष्ट्रीय राजमार्ग-715) के कालियाबोर-नुमालीगढ़ खंड को चार लेन का किया जाएगा और लगभग 34.45 किलोमीटर का 'एलिवेटेड कॉरिडोर' बनाया जाएगा। इसके तहत जखलाबांधा और बोकाखाट में बाईपास भी बनाए जाएंगे।उन्होंने कहा कि इस परियोजना को उच्चतम न्यायालय के निर्देशों और भारतीय वन्यजीव संस्थान की सिफारिशों के अनुरूप तैयार किया गया है। एक अन्य अधिकारी ने कहा कि परियोजना का उद्देश्य मध्य एवं अपर असम के बीच संपर्क बेहतर करना और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की समृद्ध जैव विविधता का संरक्षण सुनिश्चित करना है।

अपने विचार
हरिभूमि कार्यालय
टिकरापारा, रायपुर में पत्र के माध्यम से या फैक्स : 0771-4242222, 23 पर या सीधे मेल से **hbcgpati@gmail.com** पर भेज सकते हैं।

कोहरे की मार के बीच सुरक्षित यात्रा मुहैया कराना रेलवे के लिए बना बड़ी चुनौती

भारतीय रेल ने ट्रैक अवसंरचना और सुरक्षा में दर्ज की ऐतिहासिक प्रगति

लगातार निवेश और प्रभावी क्रियान्वयन से सुरक्षित, तेज़ और भरोसेमंद रेल संचालन

हरिभूमि ब्यूरो ▶▶ नई दिल्ली

देश भर में रेलगाड़ियां विलंब से चल रही हैं। उत्तर रेलवे के पॉकेट में धुंध का असर बताया जा रहा है तो कई अन्य सेक्टर में अलग अलग कारण। इन सब से इतर रेलवे बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारियों का मानना है कि रेलमंत्री अश्वनी वैष्णव की पहली प्राथमिकता है सुरक्षित यात्रा। विलंब से ही सही रेल यात्री गंतव्य तक सुरक्षित पहुंचे इसकी कोशिशें अभी तक सफल रही हैं।

बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, पिछले ग्यारह वर्षों में भारतीय रेल ने ट्रैक अवसंरचना को मज़बूत करने और सुरक्षा मानकों को ऊंचा उठाने की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति की है। निरंतर निवेश और योजनाबद्ध क्रियान्वयन के चलते देशभर में रेल परिचालन अब पहले से कहीं अधिक सुरक्षित, तेज़ और विश्वसनीय हुआ है। उक्त अधिकारी ने बताया कि रेल का परिचालन

बेहतर हो, दूर दराज के छूटे हुए इलाके रेलवे से जुड़े इस कोशिश के तहत वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान भारतीय रेल ने 6,851 ट्रैक किलोमीटर में ट्रैक नवीनीकरण का कार्य पूरा किया। चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 में 7,500 ट्रैक किलोमीटर से अधिक ट्रैक नवीनीकरण का कार्य प्रगति पर है। इसके अलावा 2026–27 में 7,900 ट्रैक किलोमीटर ट्रैक नवीनीकरण की योजना बनाई गई है, जो परिसंपत्तियों की विश्वसनीयता और सुरक्षा पर लगातार फोकस को दर्शाती है।

टर्नआउट नवीनीकरण में भी तेज़ी

सुचारू और निर्बाध रेल संचालन के लिए महत्वपूर्ण टर्नआउट नवीनीकरण में भी बड़ी उपलब्धियां हासिल की गई हैं। वर्ष 2024–25 में 7,161 थिक वेब स्विच और 1,704 वेल्डेबल सीएमएस क्रॉसिंग लगाए गए। वहीं 2025–26 में 8,000 से अधिक थिक वेब स्विच और 3,000 से ज्यादा वेल्डेबल सीएमएस क्रॉसिंग उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

बैलास्ट की गहरी स्क्रीनिंग से ट्रैक की मजबूती

ट्रैक की स्थिरता बनाए रखने और यात्रियों को बेहतर यात्रा अनुभव देने के लिए बैलास्ट की यांत्रिक गहरी स्क्रीनिंग पर भी लगातार काम किया गया है। वर्ष 2024–25 में 7,442 ट्रैक किलोमीटर की डीप स्क्रीनिंग पूरी की गई, जबकि 2025–26 में 7,500 ट्रैक किलोमीटर से अधिक डीप स्क्रीनिंग का कार्य जारी है।

ट्रैक मशीनों के बेड़े में बड़ा विस्तार

बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारी ने दावा किया कि यांत्रिक रखरखाव को बढ़ावा देने और उत्पादकता सुधारने के उद्देश्य से भारतीय रेल ने अपने ट्रैक मशीन बेड़े में उल्लेखनीय वृद्धि की है। वर्ष 2014 के बाद से अब तक 1,100 से अधिक ट्रैक मशीनें खरीदी जा चुकी हैं, जिससे रखरखाव कार्य तेज़, सटीक और अधिक प्रभावी हुआ है।

सुरक्षा के लिए रेल पटरियों पर फेंसिंग

रेल पटरियों पर पशुओं के टकराने और अनधिकृत प्रवेश की घटनाओं को रोकने के लिए सुरक्षा फेंसिंग को प्राथमिकता दी गई है। अब तक लगभग 15,000 किलोमीटर रेल लाइनों पर फेंसिंग की जा चुकी है, जिससे उन खंडों में सुरक्षा में उल्लेखनीय सुधार हुआ है जहां ट्रेनों की गति 110 किमी प्रति घंटे से अधिक है।

तेज़ गति वाले ट्रैक में दोगुनी से अधिक वृद्धि

इन सतत प्रयासों के परिणामस्वरूप भारतीय रेल ने ट्रैक उन्नयन के क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। वर्ष 2014 में जहां 110 किमी प्रति घंटे या उससे अधिक गति के लिए सक्षम ट्रैक की लंबाई 31,445 किलोमीटर (कुल नेटवर्क का लगभग 40 प्रतिशत) थी, वहीं वर्तमान में यह बढ़कर 84,244 किलोमीटर (लगभग 80 प्रतिशत नेटवर्क) हो गई है। इससे देशभर में तेज़ और अधिक कुशल रेल संचालन संभव हुआ है। यातायात विशेषज्ञों का मानना है कि भारतीय रेल के इन प्रयासों को देश की परिवहन व्यवस्था को आधुनिक, सुरक्षित और भविष्य के लिए तैयार बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा

खबर संक्षेप

मुझे भारतीय होने पर गर्वः रहमान

मुंबई (महाराष्ट्र)। बॉलीवुड को लेकर अपनी टिप्पणी के बाद विवादों में घिरे प्रख्यात संगीतकार

एआर रहमान ने अपना पक्ष रखा है। एक वीडियो पोस्ट में उन्होंने कहा कि उन्हें भारतीय होने पर गर्व है। वह किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहते, कभी-कभी इरादों को गलत समझा जा सकता है। रहमान ने लोगों से अपील की कि उनकी ईमानदारी को महसूस करें।

लातेहार में बस पलटी 5 लोगों की मौत

लातेहार। झारखंड के लातेहार जिले के महुआडांड़ थाना क्षेत्र अंतर्गत ओरसा घाटी में बड़ा हादसा

हो गया। यहां एक बस पलट गई है, जिसमें अब तक 5 लोगों की जान चली गई है। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी मनोज कुमार घटनास्थल पहुंचकर पूरे मामले की जांच में जुटे। अस्पताल में घायलों को भर्ती कराया। लोग छत्तीसगढ़ के बलरामपुर से लोध फॉल जा रहे थे।

सांसद तिवारी के घर से 5 लाख की रकम चोरी

नई दिल्ली। उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से भाजपा के सांसद और मशहूर लोकगायक

मनोज तिवारी के घर पर चोरी होने की खबर है और चोर घर की अलमारी से करीब 5 लाख से ज्यादा पैसा लेकर गायब हो गया। पुलिस ने चोर को ढूंढ निकाला और गिरफ्तार कर लिया। ये मामला सांसद तिवारी के मुंबई के अंधेरी पश्चिम स्थित आवास का है।

शाहजहांपुर में 3 की मौत, टेंपो चालक घायल

शाहजहांपुर। यहां के रोजा थाना क्षेत्र में सीतापुर-बरेली नेशनल हाईवे पर चकभिटारा मोड़ के समीप

रविवार सुबह करीब नौ बजे ट्रक से बाइक को टक्कर लग गई। बाइक ट्रक के पिछले पहिए में फंसकर घिसटती चली गई। बाइक चालक महावीर निवासी चकभिटारा और उनके साले हेमनाथ निवासी गांव पालीचक लखीमपुर खीरी की मौत हो गई।

20 वाहन टकराए,चालक की मौत, 24 जख्मी

बरेली। यहां के फरीदपुर थाना क्षेत्र में रविवार को सुबह घने कोहरे के कारण हाईवे पर कोहराम मच गया।

दिल्ली-लखनऊ नेशनल हाईवे पर कोहरे के कारण रोडवेज बस और कार समेत 20 वाहन आपस में टकरा गए। हादसे में करीब 24 लोग घायल हुए हैं। रोडवेज बस चालक की मौत हो गई। हादसे के बाद हाईवे पर जाम लग गया। लोग इधर- उधर परेशान दिखाई दिए।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम का हमला

विश्व बैंक की रिपोर्ट पर वायु प्रदूषण को लेकर मोदी सरकार पर 'सच्चाइयों' से मुंह मोड़ने का आरोप

हरिभूमि ब्यूरो ▶▶ नई दिल्ली

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने विश्व बैंक की

ताज़ा रिपोर्ट 'ए ब्रेथ ऑफ चेंज' का हवाला देते हुए देश में वायु प्रदूषण की कथित भयावह स्थिति को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि यह रिपोर्ट पूरी तरह साक्ष्य-आधारित, स्पष्ट और समयानुकूल है, लेकिन इसके बावजूद सरकार सच्चाई से आंखें मूंदे हुए है।

विश्व बैंक की इस रिपोर्ट में भारत के गंगा के मैदानी इलाकों और हिमालयी तलहटी क्षेत्रों में वायु प्रदूषण के गंभीर प्रभावों को रेखांकित किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार, इन क्षेत्रों में हर साल करीब 10 लाख लोगों की समयपूर्व मौत वायु प्रदूषण के कारण हो रही है। इतना ही नहीं, प्रदूषण के चलते क्षेत्रीय जीडीपी का लगभग 10 प्रतिशत आर्थिक नुकसान भी हर वर्ष उठाना पड़ रहा है।

रिपोर्ट में क्या करने की दी साफ सलाह

जयराम रमेश ने कहा कि इस रिपोर्ट की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह सिर्फ समस्या नहीं बताती, बल्कि समाधान भी स्पष्ट रूप से सुझाती है। रिपोर्ट में प्रमुख रूप से निम्न कदम उठाने की सिफारिश की गई हैः

कोयला आधारित बिजली संयंत्रों के लिए उत्सर्जन मानकों का सख्ती से पालन और सबसे पुराने व प्रदूषणकारी संयंत्रों को तेज़ी से बंद करना।

केवल शहरों तक सीमित योजनाओं के बजाय कानूनी रूप से सशक्त एयरशेड-आधारित शासन प्रणाली लागू करना, जो सभी राज्यों में समान रूप से प्रभावी हो।

सार्वजनिक परिवहन का विस्तार और उसका विद्युतीकरण, साथ ही वाहनों के उत्सर्जन और ईंधन मानकों को और अधिक सख्त बनाना।

कांग्रेस की पुरानी मांगें दोहराई

जयराम रमेश ने कहा कि बढ़ते एक्यूआई और उससे जुड़े स्वास्थ्य संकट को देखते हुए कांग्रेस पार्टी लगातार सरकार को चेताती और ठोस सुझाव देती रही है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस की प्रमुख मांगों में शामिल हैं—

वायु प्रदूषण (नियंत्रण और निवारण) अधिनियम, 1981 और राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक, 2009 की व्यापक समीक्षा, विशेष रूप से पीएम 2.5 पर ध्यान केंद्रित करते हुए।

राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम का वित्तीय आवंटन और भौगोलिक दायरा बड़े पैमाने पर बढ़ाना तथा प्रदर्शन के आकलन के लिए पीएम 2.5 को मुख्य मानक बनाना।

वायु प्रदूषण से जुड़े सभी कानूनों और मानकों का बिना किसी ढील या समझौते के सख्ती से पालन सुनिश्चित करना।

मोदी सरकार पर तीखा सवाल

इन तमाम तथ्यों और अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट के बावजूद जयराम रमेश ने सवाल उठाते हुए कहा , मोदी सरकार कब तक सच्चाइयों से इनकार करती रहेगी? उन्होंने कहा कि वायु प्रदूषण अब केवल पर्यावरण का मुद्दा नहीं रहा, बल्कि यह जनस्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था और भविष्य की पीढ़ियों के अस्तित्व से जुड़ा गंभीर संकट बन चुका है, जिस पर तुरंत और ईमानदार कार्रवाई की आवश्यकता है।

पंचायत स्तर से विधानसभा तक चरणबद्ध संघर्ष की रणनीति तय

मनरेगा बचाओ संग्राम को लेकर कांग्रेस की देशव्यापी समीक्षा बैठक, आंदोलन तेज

नई दिल्ली(हरिभूमि ब्यूरो)। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) को उसके मूल स्वरूप में बहाल कराने के उद्देश्य से चल रहे 'मनरेगा बचाओ संग्राम' को लेकर आज, रविवार को कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय में महासचिव संगठन केसी वेणुगोपाल समेत शीर्ष नेताओं ने एक व्यापक ऑनलाइन समीक्षा बैठक आयोजित की। बैठक में देशभर के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष, महासचिव/प्रभारी तथा मनरेगा समन्वय समिति के सदस्य शामिल हुए बैठक में आंदोलन की अब तक की प्रगति की समीक्षा की गई, जिसमें यह बात सामने आई कि कई राज्यों में मनरेगा बचाओ संग्राम का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है और इसे ज़मीनी स्तर पर व्यापक समर्थन मिल रहा है। नेताओं ने आंदोलन की सफलता और दायरे पर संतोष जताया।

पंचायत स्तर पर जनसंपर्क तेज़ करने का निर्णय

समीक्षा बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि आने वाले दिनों में आंदोलन को और अधिक धार देने के लिए पंचायत स्तर पर जनसंपर्क अभियान तेज किया जाएगा। इसके तहत आम जनता, मनरेगा मजदूरों और अन्य हितधारकों से सीधे संवाद किया जाएगा।

चरणबद्ध तरीके से वार्ड स्तर पर शांतिपूर्ण धरने

फिर विधानसभा/लोक भवन घेराव और अंत में जोनल स्तर की रैलियां आयोजित की जाएंगी। यह सभी कार्यक्रम योजनाबद्ध और निरंतर रूप से चलाए जाएंगे।

20 जनवरी को रायबरेली में मनरेगा चौपाल में शामिल होंगे राहुल गांधीः

आंदोलन को और मजबूती देने के लिए 20 जनवरी को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी रायबरेली में आयोजित एक मनरेगा चौपाल में शामिल होंगे। वे ग्रामीण मजदूरों के अधिकारों और सम्मान के प्रति कांग्रेस की प्रतिबद्धता को दोहराएंगे।

जनविरोधी कानून के खिलाफ संघर्ष का प्रतीक

कांग्रेस नेताओं ने कहा कि मनरेगा बचाओ संग्राम जनविरोधी नए कानून के खिलाफ एक मजबूत प्रतिरोध के रूप में उभरा है और मनरेगा को उसके मूल उद्देश्य और भावना के साथ बचाने की निर्णायक लड़ाई है। यह आंदोलन देश के कोने-कोने तक पहुंच रहा है। पंचायतों को भी नई ऊर्जा दे रहा है।

भाजपा के 22 उम्मीदवारों ने पूर्व सांसद नवनीत के खिलाफ खोला मोर्चा

मुख्यमंत्री फडणवीस को लिखा पत्र, कार्रवाई की मांग उठाई

अमरावती नगर निगम चुनाव में भाजपा के उम्मीदवारों के खिलाफत करने का लगाया आरोप

हरिभूमि ब्यूरो ▶▶ नई दिल्ली

हाल ही में अमरावती नगर निगम (एएमसी) चुनाव में उतरे भारतीय जनता पार्टी के 22 उम्मीदवारों ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से पूर्व सांसद नवनीत राणा को पद से हटाने की मांग की है। उम्मीदवारों का आरोप है कि नवनीत राणा ने पार्टी के उम्मीदवारों के खिलाफ प्रचार करके पार्टी को कमजोर किया है। 15 जनवरी को हुए चुनावों में भाजपा की सीटों में भारी गिरावट आई, जिससे टूटे हुए गठबंधन के बीच विश्वासघात के आरोप और भी बढ़ गए हैं।

चुनाव में करारी हार 87 सदस्यीय एएमसी में भाजपा को पिछली बार की 45 सीटों के मुकाबले मात्र 25 सीटें मिलीं, जबकि नवनीत राणा के पति रवि राणा की युवा स्वाभिमान पार्टी (वाईएसपी) को 3 के मुकाबले 15 सीटें मिलीं। अन्य दलों को कांग्रेस (15), एआईएमआईएम (12), एनसीपी (11), शिवसेना (3), बसपा (3), शिवसेना (यूबीटी) (2), वंचित बहुजन अघाड़ी (1) की सीटें मिलीं। चुनाव से पहले, भाजपा और वाईएसपी (विधायक रवि राणा) ने संबंध तोड़ लिए थे, फिर भी भाजपा के एक स्थानीय नेता ने जोर देकर कहा कि नवनीत भगवा उम्मीदवारों का समर्थन करेंगी। इसके विपरीत, उन्होंने कथित तौर पर भाजपा उम्मीदवारों को बेवकूफ करार दिया और वाईएसपी को असली भाजपा के रूप में पेश किया।

22 शिकायतकर्ताओं में से 20 हारे और 2 जीते, लेकिन सभी नवनीत के हस्तक्षेप की ओर इशारा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को लिखे अपने पत्र में उन्होंने कहा, हम समर्पित, मेहनती पार्टी कार्यकर्ता हैं जो समाज से जुड़े हुए हैं। हमारी हार विपक्ष की वजह से नहीं, बल्कि वरिष्ठ भाजपा नेता नवनीत राणा के खुलेआम हमारे खिलाफ प्रचार करने की वजह से हुई है। उन्होंने चेतावनी दी है कि नवनीत राणा को पार्टी में बनाए रखने से अमरावती में भाजपा की पकड़ कमजोर हो सकती है और उन्हें तत्काल निष्कासित करने की मांग की है।

बीएमसी महापौर पर राउत के बयान से बढ़ी 'गरमी'

होटल को बना दिया जेल

शिंदे भी नहीं चाहते भाजपा का मेयर उसके कई पार्षद हमारे संपर्क में

एजेंसी ▶▶ मुंबई

यहां मेयर पद को लेकर सस्पेंस बढ़ा है। चुनाव नतीजों के बाद एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने ढाई-ढाई साल के फार्मूले पर भाजपा से मेयर

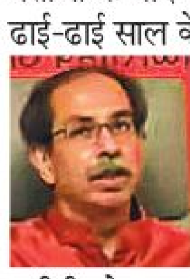

पद की मांग की है और अपने पार्षदों को होटल में ठहरा दिया है। सीएम फडणवीस ने विवाद से इनकार किया है। शिवसेना यूबीटी को उद्धव ठाकरे ने ये कहकर हलचल बढ़ाई कि भगवान ने चाहा तो शिवसेना यूबीटी का ही मेयर बनेगा। संजय राउत ने कह दिया है कि शिवसेना के कई पार्षद भाजपा का मेयर नहीं चाहते और कई लोग उनके संपर्क में हैं।

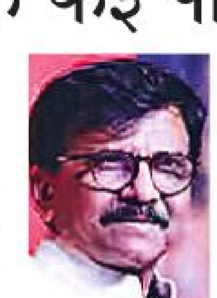

राउत ने कानून- व्यवस्था पर किए सवाल

राउत ने कहा कि शिंदे के पार्षदों को इस तरह से होटल में बंदी बनाकर रखना कानून व्यवस्था का सवाल है। उन पार्षदों को डर है कि उनका अपहरण किया जा सकता है, उन्हें तोड़ा जा सकता है। ऐसे में शिंदे ने उन्हें ताज होटल में बंद कर दिया है। पुलिस का कड़ा पहरा है।

शिंदे के पार्षदों को रिहा करें

राउत ने कहा कि हमें और हमारे दोस्तों को ताज होटल जाना है, लेकिन हम वहां जाएंगे और वहां गड़बड़ हो जाएगी, लेकिन फिर भी हम वहां जाएंगे। राउत ने दावा किया कि एकनाथ शिंदे के गुट के कई पार्षद हमारे संपर्क में हैं। कौन चाहता है कि मुंबई में भाजपा का मेयर बने? शिंदे भी ऐसा नहीं चाहते।

विराट रामायण मंदिर के पास विशाल शिवलिंग स्थापित

पूर्वी चंपारण। बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी में विराट रामायण मंदिर के पास 33 फीट ऊंचे और 210 मीट्रिक टन वजनी शिवलिंग की स्थापना रविवार को की गई। इसे तमिलनाडु के महाबलीपुरम में बनाया गया था और विशेष रूप से निर्मित 96 पहियों वाले ट्रेलर पर कल्याणपुर लाया गया था।

नई दिल्ली के विश्व पुस्तक मेले में पहुंचे केंद्रीय गृहमंत्री शाह

देश की रक्षा व अखंडता का संकल्प और मजबूत होगा

वंदे मातरम और ऑपरेशन सिंदूर पवेलियन का दौरा किया

एजेंसी ▶▶ नई दिल्ली

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज भारत मंडपम में आयोजित नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले का अवलोकन किया। गृह मंत्री ने वंदे मातरम पवेलियन और ऑपरेशन सिंदूर पवेलियन का भी दौरा किया। गृह मंत्री ने सरदार वल्लभभाई पटेल के जीवन और योगदान पर बनी प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। एक्स पर किए गए सिलसिलेवार पोस्ट्स में केन्द्रीय गृह मंत्री शाह ने कहा कि पुस्तकें ज्ञान प्राप्त करने का सर्वोत्तम माध्यम हैं और उम्र चाहे जो भी हो, पढ़ते रहना चाहिए। पढ़ने की आदत तेजी से कम होती जा रही है और मुझे विश्वास है कि डिजिटल हो या प्रिंट, पुस्तकें अभी भी ज्ञान अर्जित करने का सबसे अच्छा तरीका हैं।

स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों को पूरा करें

पुस्तक मेला में गृहमंत्री शाह

बच्चों को 'आनंद मठ' की प्रतियां भी वितरित की

गृहमंत्री शाह ने बच्चों को बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की 'आनंद मठ' की प्रतियां भी वितरित कीं। उन्होंने कहा कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित साहित्यिक कृति 'आनंद मठ' ने लाखों भारतीयों को स्वतंत्रता संग्राम छेड़ने और ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के लिए प्रेरित कर इतिहास रचा।

सरदार पटेल के कृतित्व को अजर-अमर बनाएं

शाह ने कहा कि नेशनल बुक ट्रस्ट के वंदे मातरम पवेलियन का दौरा किया। यह पवेलियन गौरवशाली गाथा को प्रदर्शित कर रहा है, जिसने स्वतंत्रता सेनानियों में औपनिवेशिक शासन को उखाड़ फेंकने की देशभक्ति की भावना जगाई थी। शाह ने पुस्तक मेले में सरदार वल्लभभाई पटेल के जीवन और योगदान पर बनी प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। टुकड़ों में बंटे देश को एकीकृत कर एक भारत बनाने वाले सरदार साहब का 150वां जयंती वर्ष मनाकर मोदी सरकार उनके व्यक्तित्व- कृतित्व को बता रही।

मणिकर्णिका की 'फर्जी' तस्वीरें शेयर की

सांसद संजय, कांग्रेस नेता यादव समेत 8 नेताओं पर एफआईआर

एजेंसी ▶▶ वाराणसी

पुलिस ने मणिकर्णिका घाट पर चल रहे पुनर्विकास कार्यों के बारे में सोशल मीडिया पर एआई से बनाई

गई तस्वीरें, वीडियो और भ्रामक जानकारी प्रसारित करने के आरोप में कार्रवाई की है। वाराणसी पुलिस ने आपके सांसद संजय सिंह, कांग्रेस नेता पप्पू यादव सहित 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) गौरव बंसल ने बताया कि घाट पर चल रहे सौंदर्यीकरण और श्मशान सुविधाओं पर चल रहे सुधार के संबंध में मनगढ़ंत सामग्री फैलाने के आरोप में बीएनएस की संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई हैं। वाराणसी के चौक थाने में शनिवार को एफआईआर दर्ज होने के बाद सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री के लोकसभा क्षेत्र में घाट को तहस-नहस किया गया, मंदिरों को तोड़ा गया, काशी विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कराने वाली माता अहिल्याबाई होल्कर की प्रतिमा भी तोड़ी गई जिसका विरोध काशी के साधुओं ने किया।

संपादकीय जागरण

सोमवार, 19 जनवरी, 2026 : माघ शुक्ल प्रतिपदा वि. 2082

वाणी का संयम मन को एकाग्रचित्त रखने का अचूक साधन है

बीएमसी में खींचतान

एकनाथ शिंदे ने बृहन्मुंबई महानगरपालिका यानी बीएमसी चुनाव में जीते अपने पार्षदों को जिस तरह एक होटल भेज दिया, उसका औचित्य समझना कठिन है। आखिर एकनाथ शिंदे के पार्षदों को किससे खतरा है? क्या उनके पार्षदों के टूटने की आशंका है या फिर वे भाजपा के मेयर को समर्थन देने की कोई कीमत वसूलना चाहते हैं? कारण जो भी हो, यह किसी से छिपा नहीं कि भाजपा और उसकी सहयोगी शिवसेना के बीच खटपट चलती ही रहती है। विधानसभा चुनावों के बाद भी दोनों दलों के बीच खींचतान देखने को मिली थी। इसके बाद विभागों के बंटवारे को लेकर भी दोनों दलों के बीच मतभेद सामने आए थे। शिंदे शिवसेना को मानें तो उनके पार्षदों को पार्षद के रूप में प्रशिक्षित करने के लिए होटल में एकत्रित किया गया है, लेकिन इस तर्क में कोई बहुत दम नहीं दिखता और इसीलिए विपक्षी दल उस पर कटाक्ष करने में लगे हुए हैं। उन्हें कटाक्ष का यह अवसर शिंदे शिवसेना ने स्वयं ही उपलब्ध कराया है। समझना कठिन है कि जब उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना राज्य की सत्ता में साझेदार है और उसने बीएमसी के साथ महाराष्ट्र के अन्य निकाय चुनाव भाजपा के साथ मिलकर लड़े थे, तब फिर अपने पार्षदों को एकत्रित क्यों कर रहे हैं? यह देखना दयनीय है कि जब दोनों दलों के पार्षदों को मुंबई की सूरत संवारने को लेकर अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित करनी चाहिए, तब उनके बीच अविश्वास देखने को मिल रहा है। हैरानी नहीं कि शिंदे शिवसेना के पार्षदों ने इसलिए होटल में डेरा जमाया हो, ताकि वे बीएमसी में मलाईदार पद हासिल कर सकें। जो भी हो, दोनों दलों के बीच का अविश्वास बीएमसी में उनकी शानदार जीत को मलिन ही कर रहा है।

यह निराशाजनक है कि राजनीतिक दल नगर निकाय के चुनाव में जीत हासिल करने के लिए तो हरसंभव जतन करते हैं, लेकिन नगरों की दशा-दिशा बदलने की ईमानदारी से कोई कोशिश करते नहीं दिखते। राजनीतिक दलों के इसी रवैये के कारण देश के छोटे-बड़े शहर दुर्दशा से ग्रस्त हैं। चिंताजनक यह है कि उनकी दुर्दशा बढ़ती चली जा रही है। मुंबई सरीखे जिन महानगरों को नगरीय ढांचे में सुधार करके कोई मिसाल कायम करनी चाहिए, वे इसमें बुरी तरह नाकाम सिद्ध हो रहे हैं। इस नाकामी के चलते ही शहरी जीवन कष्टप्रद बनता चला जा रहा है। हमारे अधिकांश शहर गंदगी-प्रदूषण और ट्रैफिक जाम से तो ग्रस्त रहने ही लगे हैं, उनमें झुग्गी-बस्तियां भी बढ़ती चली जा रही हैं। बीएमसी देश का सबसे धनी नगर निकाय है। उसका बजट कई राज्यों के बजट से भी अधिक है, लेकिन इसके बावजूद मुंबई नागरिक सुविधाओं की दृष्टि से एक बदहाल महानगर है। यदि बीएमसी के मेयर का चयन सुगमता से नहीं होता तो देश की आर्थिक राजधानी को बदहाली से मुक्त होना कठिन ही होगा।

पर्यावरण संरक्षण जरूरी

दिल्ली में बिजवासन रेलवे टर्मिनल के निर्माण में पेड़ काटे जाने की अंतिम अड़चन दूर होना स्वागतयोग्य है। केंद्र सरकार ने परियोजना के आड़े आ रहे 1279 पेड़ों को प्रत्यारोपित करने व काटने की स्वीकृति दे दी है, जिसके बाद अब इस परियोजना पर काम में तेजी आने की संभावना है। इनमें से कुछ पेड़ों को प्रत्यारोपित किया जाएगा, जबकि शेष पेड़ काटे जाएंगे और उनके बदले में किसी अन्य स्थान पर नियमानुसार पौधारोपण किया जाएगा।

> विकास कार्यों की गति नहीं रुकनी चाहिए, लेकिन उनके लिए यदि पेड़ काटे जा रहे हैं तो प्रतिपूर्ति भी सुनिश्चित की जानी चाहिए

यह सही है कि विकास कार्यों के लिए पेड़ काटे जाने को अनुमति दिया जाना सर्वथा उचित है और इसके लिए पेड़ काटने व प्रत्यारोपित करने की अनुमति मिल गई है। लेकिन यह चिंताजनक है कि विभिन्न विकास योजनाओं के लिए अब तक प्रत्यारोपित किए गए पेड़ों में से अधिकतर नष्ट हो गए हैं या नष्ट होने के कगार पर हैं। पेड़ काटने की प्रतिपूर्ति में पौधे लगाने की योजना भी सफल नहीं दिखाई देती, जो पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिकोण से अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। निश्चित तौर पर विकास कार्यों की गति नहीं रुकनी चाहिए, लेकिन उनके लिए यदि पेड़ काटे जा रहे हैं तो प्रतिपूर्ति भी नियमानुसार सुनिश्चित की जानी चाहिए। इस मामले में केंद्र सरकार और रेलवे दोनों को इसकी चिंता करनी होगी, ताकि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना विकास कार्यों की प्रगति जारी रहे।

कह के रहेंगे — माधव जोशी

जागरण जनमत — कल का परिणाम

क्या भारत ने ब्रिक्स देशों के नौसेना अभ्यास में शामिल न होकर सही किया?

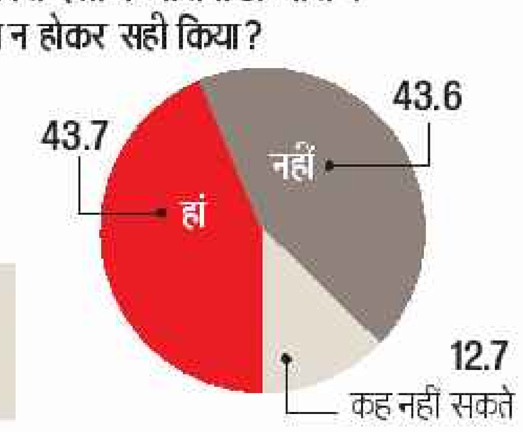

आज का सवाल

क्या ग्रीनलैंड को लेकर यूरोप के अमेरिका के साथ संबंध बिगड़ते दिख रहे हैं?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है। सभी आंकड़े प्रतिशत में।

टकराव की ओर अमेरिका-यूरोप

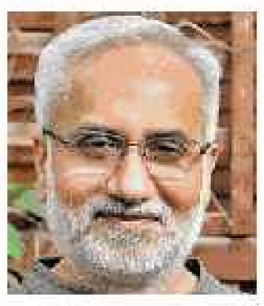

शिवकांत शर्मा

ग्रीनलैंड को लेकर नाटो और यूरोपीय संघ की प्रतिक्रिया नाराजगी भरी तो है, लेकिन यह पता नहीं कि ट्रंप से टक्कर लेने के मामले में वे कितने पानी में हैं

वेनेजुएला पर हमला करके उसके राष्ट्रपति मादुरो को पत्नी समेत अगवा करा लेने के बाद से राष्ट्रपति ट्रंप ने डेनमार्क के स्वायत्त द्वीप ग्रीनलैंड को छीनने की मुहिम तेज कर रखी है। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है जो कनाडा और यूरोप के बीच उत्तरी अटलांटिक महासागर में फैला है। उत्तरी ध्रुव से सटा होने के कारण तटवर्ती पट्टियों को छोड़कर इसका 80 प्रतिशत से अधिक भूभाग बर्फ की एक से तीन किमी मोटी परत से ढका रहता है। दक्षिणी ध्रुव के बाद सबसे अधिक बर्फ ग्रीनलैंड की इस परत में ही जमा है जो जलवायु परिवर्तन के कारण तेजी से पिघल कर किनारों की तरफ खिसक रही है।

ग्रीनलैंड के साथ-साथ उत्तरी ध्रुव सागर की बर्फ भी तेजी से पिघल रही है जिसकी वजह से समुद्री यातायात के नए जलमार्ग खुल रहे हैं जो रूस, चीन और जापान से उत्तरी अमेरिका और यूरोप की दूरी को बहुत कम कर देते हैं। उत्तरी ध्रुव सागर से ग्रीनलैंड सागर होते हुए उत्तरी अटलांटिक महासागर में खुलने वाले इन मार्गों का प्रयोग करने के लिए रूस और चीन अपने विशेष युद्धपोतों और पनडुब्बियों का विकास कर रहे हैं ताकि वहां अपना वर्चस्व कायम कर सकें। इस जलमार्ग पर स्थित होने के कारण ग्रीनलैंड का भूराजनीतिक और सामरिक महत्व हमेशा से रहा है। दूसरे महायुद्ध में उसने हिटलर के युद्धपोतों और पनडुब्बियों को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। युद्ध के बाद राष्ट्रपति ट्रूमैन ने इसे 10 करोड़ डालर के सोने से खरीदने का प्रयास किया, पर बात नहीं बनी। उसके बाद 1951 में डेनमार्क ने अमेरिका को ग्रीनलैंड की रक्षा में विशेष भूमिका देते हुए सैनिक अड्डे बनाने का अधिकार दे दिया था। इसके अलावा ग्रीनलैंड में तेल, गैस और उन दुर्लभ खनिजों के भंडार भी हैं जो इलेक्ट्रानिक और रक्षा उपकरणों और स्वच्छ ऊर्जा की बैटरियों के लिए आवश्यक होते हैं।

राष्ट्रपति ट्रंप का कहना है कि उत्तरी ध्रुव और उत्तरी अटलांटिक महासागर में रूस और चीन के बढ़ते खतरे को देखते हुए ग्रीनलैंड पर अमेरिका का स्वामित्व होना आवश्यक है। इसके बिना न ग्रीनलैंड अपनी रक्षा कर पाएगा और न वे उसकी रक्षा कर सकेंगे। इसलिए सीधे या टेढ़े रास्ते से वे उसे लेकर रहेंगे। उन्होंने भी ग्रीनलैंड को खरीदने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन डेनमार्क और ग्रीनलैंड ने कहा उनका देश बिकाऊ नहीं है। डेनमार्क अमेरिका का दो सौ साल पुराना दोस्त है और स्थापना के समय से ही नाटो का सदस्य रहा है। उसने कोई 300 वर्ष पहले ग्रीनलैंड को अपना उपनिवेश बनाया था, परंतु 1979 के बाद से ग्रीनलैंड पूरी तरह स्वायत्त है। केवल विदेश नीति और रक्षा डेनमार्क संभालता है, क्योंकि ग्रीनलैंड के पास अपनी सेना नहीं है। उसके सभी 56 हजार इन्युइट आदिवासियों को डेनिश नागरिकता प्राप्त है। ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री जेंस-फ्रेडरिक नील्सन का कहना है कि यदि उन्हें अमेरिका और डेनमार्क में से एक को चुनना पड़ा तो वे डेनमार्क में रहना पसंद करेंगे।

अमेरिका-यूरोप के संबंधों को बिगाड़ता ट्रंप का अड़ियल रवैया ● फाइल

संयुक्त राष्ट्र चार्टर या कोई भी अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था किसी भी महाशक्ति को किसी दूसरे देश की संप्रभुता जबरन छीनने का अधिकार नहीं देती, लेकिन हाल के एक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा, 'उन्हें अंतरराष्ट्रीय कानून की जरूरत नहीं है।' सवाल यह है कि यदि ट्रंप सहयोग करने और सुविधाएं देने के लिए तैयार एक संप्रभु मित्र देश को अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जबरन हथियाना आवश्यक और वैध मानते हैं तो उनमें और पुतिन में क्या फर्क है? बल्कि पुतिन तो उनकी तुलना में नेक काम कर रहे हैं, क्योंकि उनके शब्दों में, उनकी सैनिक कार्रवाई तो 'यूक्रेन से नात्सीवादी ताकतों का सफाया कर नाटो की बढ़त को रोकने के लिए है।' ट्रंप की दलील के आधार पर चीन का ताइवान पर कब्जा कर लेना तो और भी जायज माना जाएगा, क्योंकि शी चिनफिंग तो अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए टूट कर अलग हुए देश और समाज के हिस्से को जोड़ने का कार्य करेंगे। दूसरे महायुद्ध के बाद एक नियमबद्ध व्यवस्था की स्थापना करके राष्ट्रीय संप्रभुता, लोकतंत्र और मुक्त व्यापार की हिमायत करते आ रहे देश के राष्ट्रपति का अंतरराष्ट्रीय कानून का इस तरह मखौल उड़ाना विश्व व्यवस्था के लिए गंभीर संकट का संकेत है। इस स्थिति के लिए काफी हद तक यूरोपीय संघ और अमेरिका से इतर नाटो के देश खुद जिम्मेदार हैं। ट्रंप और उनकी सरकार के आपत्तिजनक बयानों का एक सुर में कड़ा विरोध करने और ग्रीनलैंड की रक्षा के लिए नाटो सेनाओं को तैनात करने के बजाय वे उसी तरह की जी हुजूरी में लगे हुए हैं, जैसी ट्रंप के मनमाने टैरिफों के एलान पर की थी। यूक्रेन पर रूसी हमले की कड़ी निंदा से बचने के लिए भारत और चीन जैसी दक्षिणी गोलार्ध की प्रमुख शक्तियों की निंदा करने वाले यूरोपीय देशों ने वेनेजुएला पर ट्रंप के हमले पर जैसी बगलें झांकीं, उससे भी उनकी खासी फजीहत हो रही है।

अब जब ग्रीनलैंड और डेनमार्क की संप्रभुता को लेकर पानी सिर से ऊपर जा चुका है तब भी डेनमार्क के साथ केवल ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस जैसे चंद देशों ने ही अपनी टुकड़ियां ग्रीनलैंड भेजी हैं। इन मुट्ठी भर देशों की हिम्मत तोड़ना ट्रंप के लिए बाएं हाथ का खेल है। उन्होंने दबाव बढ़ाने के लिए यूरोप के आठ देशों पर 10 प्रतिशत टैरिफ लगाने का एलान कर दिया है और उसे 25 प्रतिशत तक बढ़ाने की धमकी दी है। इस पर नाटो और यूरोपीय संघ की प्रतिक्रिया नाराजगी भरी है, लेकिन यह पता नहीं कि ट्रंप से टक्कर लेने के मामले में वे कितने पानी में हैं। नाटो की एक समस्या यह है कि एक पर हमला सभी पर हमले का सिद्धांत नाटो के ही किसी सदस्य पर दूसरे सदस्य के हमले की स्थिति में स्पष्ट नहीं है। मिसाल के तौर पर 1974 में साइप्रस द्वीप पर फैली हिंसा में जब नाटो सदस्य तुर्किये ने दूसरे नाटो सदस्य ग्रीस पर हमला बोल दिया था तब नाटो के समक्ष धर्मसंकट खड़ा हो गया था कि किसका पक्ष ले। अंत में अमेरिका ने बीच-बचाव कर सुलह कराई थी। ट्रंप के ग्रीनलैंड पर कब्जा कर लेने से और भी गंभीर संकट खड़ा हो सकता है, जिसके लिए नाटो अभी तैयार नजर नहीं आता।

(लेखक बीबीसी हिंदी के पूर्व संपादक हैं)

response@jagran.com

आइएनडीआइए की परीक्षा का साल

नए साल के शुरू में ही पश्चिम बंगाल में राजनीतिक रार और उसमें संवैधानिक प्रविधानों-परंपराओं को ताक पर रख देना बता रहा है कि साल 2026 भारतीय राजनीति के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होने जा रहा है। इस साल चार राज्यों-बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल तथा केंद्रशासित प्रदेश पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव होने हैं। इनमें से तीन में आइएनडीआइए के घटक दलों की सरकारें हैं, जबकि दो में भाजपानीत राजग की। इन राज्यों की सत्ता में होने वाला बदलाव राष्ट्रीय राजनीतिक परिदृश्य पर भी असर डालेगा, क्योंकि विधानसभाओं के गणित से संसद के उच्च सदन राज्यसभा में संख्या बल प्रभावित होगा। इसी साल राज्यसभा की 75 सीटों के लिए भी चुनाव होने हैं। साल की शुरुआत देश की सबसे अमीर महानगर पालिका मुंबई यानी बीएमसी समेत महाराष्ट्र के 29 नगर निकाय चुनावों से हुई है। बीएमसी चुनाव में भाजपा को पहली बार जीत मिली है और ठाकरे बंधुओं-उद्धव और राज को साथ आने के बाद भी हार का सामना करना पड़ा है।

राज कुमार सिंह

अगर भाजपा बंगाल में महाराष्ट्र और बिहार की पुनरावृत्ति कर पाई तो उसका राष्ट्रीय राजनीति पर दूरगामी असर होगा

बंगाल में बढ़ती राजनीतिक तकरार ● फाइल

महत्वपूर्ण तो हर राज्य की सत्ता होती है, पर देश की निगाहें फिलहाल पश्चिम बंगाल पर टिकी हैं। ग्यारह साल से केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा और डेढ़ दशक से बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के बीच राजनीतिक कटुता चरम पर है। घुसपैठ, एसआइआर और भ्रष्टाचार पर तो तकरार बरकरार है ही, आइ-पैक के चेयरमैन के दफ्तर पर ईडी के छापे और उसी बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के वहां पहुंच कर कुछ दस्तावेज ले जाने के बाद बंगाल की सत्ता का संघर्ष चुनाव से पहले ही सड़कों पर नजर आ रहा है। ममता इसे केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा के इशारे पर तृणमूल कांग्रेस की चुनावी रणनीति पर ईडी का डाका बता रही हैं तो केंद्र सरकार और भाजपा इसे सरकारी एजेंसी के कामकाज में एक मुख्यमंत्री द्वारा अवरोध डालने का अभूतपूर्व मामला बता रहे हैं। कांग्रेस और वाम मोर्चा अब बंगाल की राजनीति में हाशिये पर हैं। सत्ता की लड़ाई तृणमूल और भाजपा के बीच है। पिछले चुनाव में खुद ममता को हरा कर भाजपा सनसनी फैलाने में तो सफल रही, लेकिन 294 सदस्यीय विधानसभा में 77 सीटों तक ही पहुंच पाई। तृणमूल 215 सीटें जीत गई। तृणमूल को 48 और भाजपा को 38 प्रतिशत मत मिले थे। 2024 के लोकसभा चुनाव में यह फासला बढ़ गया। यही फासला तय करना भाजपा के लिए बड़ी चुनौती है। तीन कार्यकाल के बाद सत्ता विरोधी भावना स्वाभाविक है, पर ममता के 'बांग्ला अस्मिता' के मुद्दे की काट भाजपा नहीं कर पा रही। एसआइआर और घुसपैठिया विवाद के बीच अगर भाजपा बंगाल में महाराष्ट्र और बिहार की पुनरावृत्ति कर पाई तो उसका राष्ट्रीय राजनीति पर भी दूरगामी असर होगा।

दूसरा बड़ा और मुश्किल राज्य तमिलनाडु है। वहां द्रमुक की सरकार है, जो 'इंडिया' का घटक दल है। दशकों से तमिल राजनीति द्रमुक और अन्नाद्रमुक के बीच बंटी रही, लेकिन जयललिता के निधन के बाद परिदृश्य बदला है। अन्नाद्रमुक और अभिनेता विजय के इर्दगिर्द भाजपा चुनावी बिसात बिछाना चाहती है, पर किसी चमत्कार की खुशफहमी उसे भी नहीं है। उत्तर भारत में भाजपा की लहर चलाने वाले मुद्दे दक्षिण में अभी तक तो नहीं चले हैं। एमके स्टालिन सरकार के विरुद्ध सत्ता विरोधी भावना के अलावा वंशवाद, भ्रष्टाचार और हिंदी विरोध सरीखे मुद्दे भी हैं, पर उनका चुनावी लाभ उठाने के लिए विश्वसनीय विकल्प भी चाहिए। भाजपा की रणनीति फिलहाल गठबंधन के जरिये मत प्रतिशत बढ़ाने की ज्यादा लगती है।

पिछले लोकसभा चुनाव में अभिनेता सुरेश गोपी के सांसद बनने और हाल में तिरुवनंतपुरम में अपना मेयर बनाने के करिश्मे के बावजूद भाजपा केरल में हाशिये पर ही है। केरल में सत्ता राजनीति वाम मोर्चा 'एलडीएफ' और कांग्रेसी मोर्चा 'यूडीएफ' के बीच बंटी है। हालांकि हर चुनाव में सरकार बदल जाने का सिलसिला पिछली बार वामपंथी मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने तोड़ दिया। इस बार उनके विरुद्ध ज्यादा सत्ता विरोधी भावना की उम्मीद है, पर उसका चुनावी लाभ कांग्रेस को ही मिल सकता है। अपने अंतिम दुर्ग की सत्ता से विदाई वाम राजनीति के लिए बड़ा झटका साबित होगी। वहीं असम पूर्वोत्तर भारत की राजनीति का प्रवेश द्वार माना जाता है। वहां की सत्ता कब्जाने के बाद ही भाजपा का पूर्वोत्तर में विस्तार हुआ, जिसका श्रेय पूर्व कांग्रेसी हिमंता बिस्वा सरमा को जाता है। बंगाल की तरह असम में भी घुसपैठ बड़ा चुनावी मुद्दा है, जिस पर आक्रामकता के साथ कांग्रेस को भाजपा घेरती रही है। कांग्रेस की सारी उम्मीदें वहां गौरव गोगोई के नेतृत्व तथा क्षेत्रीय दलों से तालमेल पर टिकी हैं। पुदुचेरी की राजनीति अक्सर तमिलनाडु की राह चलती रही है, लेकिन 2021 से वहां भाजपा समर्थित एन रंगासामी सरकार है। 30 सदस्यीय पुदुचेरी विधानसभा में 10 सीटें जीतने वाली आल इंडिया एनआर कांग्रेस ने छह सीटें जीतने वाली भाजपा के साथ मिल कर सरकार बनाई। अगर कांग्रेस और द्रमुक सत्ताविरोधी भावना का लाभ उठाते हुए आगामी चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करते हैं तो भाजपा को दक्षिण भारत में अपना एकमात्र शेष सत्ता दुर्ग भी गंवाना पड़ सकता है। ये विधानसभा चुनाव परिणाम भाजपा की भावी चुनावी तैयारियों पर भी असर डालेंगे, लेकिन आइएनडीआइए का तो भविष्य ही एकता और सफलता पर निर्भर करेगा, क्योंकि चुनाव-दर-चुनाव उसमें दरारें बढ़ती जा रही हैं।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार एवं राजनीतिक विश्लेषक हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

सत्कर्म

अन्याय करने वाला जितना दोषी होता है, उतना ही दोषी उस अन्याय को मूकदर्शक बनकर देखने वाला भी होता है। महाभारत युद्ध के बाद भगवान श्रीकृष्ण जब वापस द्वारका पहुंचे, तो महारानी रुक्मिणी ने उनसे पूछा कि युद्ध में भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य को आपने क्यों मरने दिया। तब भगवान ने उत्तर दिया कि द्रौपदी का चीरहरण करने के लिए जितना दोषी दुशासन था, उतने ही दोषी वे दोनों भी थे, क्योंकि जिस सभा में चीरहरण हो रहा था, उसमें वे दोनों भी उपस्थित थे। यदि वे इस कृत्य को रोकने का प्रयास करते, तो दुशासन कभी चीरहरण नहीं कर पाता, परंतु वे दोनों मूकदर्शक बनकर देखते रहे। इसी प्रकार आज के समाज में चारों ओर अन्याय होता रहता है, परंतु समाज के प्रभावशाली लोग मूकदर्शक बनकर अपनी मौन सहमति देते रहते हैं।

आज बहुत से लोग अपने स्वार्थ के लिए अन्यायपूर्ण कर्म करते हैं, परंतु उन्हें रोकने वाले लोग मूकदर्शक बनकर देखते रहते हैं। इसके कारण समाज में तरह-तरह की बुराइयां पैदा हो रही हैं। अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं और जनता पर अत्याचार कर रहे हैं, जिससे जनता द्रौपदी की तरह स्वयं को असुरक्षित महसूस करने लगी है।

सतयुग में चारों ओर मानवता के कल्याण के कार्य किए जाते थे। इसलिए उस समय समाज का हर व्यक्ति सुरक्षित महसूस करता था और अपने विकास के लिए प्रयासरत रहता था। आज कलियुग में चारों ओर अनैतिक और अन्यायपूर्ण कर्म दिखाई देते हैं। यह केवल इसलिए हुआ है, क्योंकि मनुष्य अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा संसार का अनुभव कर, उसका अपनी इंद्रियों द्वारा अनियंत्रित भोग करना चाहता है। इसके लिए वह अनैतिक और पापकर्म करता है। जिन व्यक्तियों को समाज के लिए प्रेरणादायक होना चाहिए, वही अधिक पाप और अनैतिक कर्म कर रहे हैं। पूरा समाज उनका अनुसरण कर रहा है। यदि हमें दोबारा सतयुग लाना है, तो सत्कर्मों को महत्व देना होगा।

कर्नल शिवदानसिंह

पाठकनामा

pathaknama@nda .jagran.com

सरकार का लचर रवैया

'बिना शिक्षकों के शिक्षा' शीर्षक से प्रकाशित संपादकीय पढ़ा। देश में अनेक उच्च शिक्षा संस्थानों का शिक्षकों की भारी कमी से जूझना अत्यंत चिंताजनक है। एक ओर सरकारें देश को शिक्षित और आत्मनिर्भर बनाने की बात करती हैं, वहीं दूसरी ओर शिक्षकों की भर्ती को लेकर उनका रवैया लचर दिखाई देता है। बिना शिक्षकों के देश कैसे शिक्षित और आत्मनिर्भर बन पाएगा? क्या सरकारें नए शिक्षकों की भर्ती इसलिए नहीं करतीं कि उनके पास शिक्षकों को वेतन देने के लिए पर्याप्त धनराशि नहीं है? यदि ऐसा है, तो यह प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठता है कि फिर सरकारों के पास मुफ्तखोरी को बढ़ावा देने के लिए धन कहां से आता है? देश में उच्च शिक्षा प्राप्त बेरोजगार युवाओं की लंबी कतार है। यदि शिक्षकों की भर्ती की जाए, तो इससे बड़ी संख्या में युवाओं को सम्मानजनक रोजगार मिल सकता है। इससे न केवल शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा, बल्कि सामाजिक संतुलन भी मजबूत होगा। भावी पीढ़ी का उज्ज्वल भविष्य गढ़ने में शिक्षकों की भूमिका महत्वपूर्ण है। इसे देखते हुए शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों की कमी को अविलंब दूर किया जाना चाहिए।

राजेश कुमार चौहान, जालंधर

स्टार्टअप्स की बदलती दुनिया

कहा जाता है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जब जीवन में कोई समस्या गहराई से सामने आती है, जब दर्द व्यक्तिगत हो जाता है, जब असुविधा रोजमर्रा की बाधा बन जाती है, तभी मनुष्य नए रास्ते खोजता है। भारत के उभरते स्टार्टअप्स इस कथन को केवल दोहरा नहीं रहे, बल्कि इसे साकार कर रहे हैं। नेशनल स्टार्टअप अवार्ड के मंच पर सम्मानित किए गए नवाचार इस बात का प्रमाण हैं कि आज का भारतीय उद्यमी केवल मुनाफे के लिए नहीं, बल्कि समाज की वास्तविक जरूरतों को समझकर समाधान गढ़ रहा है। ये नवाचार दिखाते हैं कि तकनीक तब सबसे प्रभावशाली बनती है, जब वह आम आदमी की जिंदगी को सरल, सुरक्षित और सशक्त बनाए। दिल से जुड़ी बीमारी आज भारत में मौत का बड़ा कारण बन चुकी है। बड़े शहरों से लेकर छोटे कस्बों तक हार्ट अटैक की घटनाएं बढ़ रही हैं, लेकिन समय पर जांच और सही जानकारी की कमी के कारण कई जानें असमय चली जाती हैं। ऐसी ही एक व्यक्तिगत त्रासदी ने एक युवा को समाधान खोजने के लिए प्रेरित किया। अपने दोस्त को हार्ट अटैक से खोने के बाद रजत जैन ने यह ठान लिया कि अगर समय रहते संकेत मिल जाएं तो हजारों जानें बच सकती हैं। इसी सोच से जन्म हुआ माचिस जितनी ईसीजी मशीन 'स्पंदन' का। यह उपकरण किसी भी व्यक्ति को यह जानने में सक्षम बनाता है कि उसकी ईसीजी रिपोर्ट सामान्य है या खतरे का संकेत दे रही है। रिपोर्ट तुरंत डाक्टर तक भेजी जा सकती है और समय पर इलाज संभव हो जाता है। आज यह छोटा सा उपकरण हजारों लोगों की जिंदगी में उम्मीद की धड़कन बन चुका है और यह साबित करता है कि व्यक्तिगत पीड़ा से जन्मा विचार समाज के लिए वरदान बन सकता है।

कांतिलाल मांडोत नई दिल्ली

जय हिंद की सेना

जय हिंद की भारतीय सेना अपने शौर्य और वीरता के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। युद्ध का मैदान हो या फिर कोई भी प्राकृतिक आपदा भारतीय सेना देश के लिए हमेशा अपना सर्व समर्पण दिखाया है। आज जय हिंद की सेना सिर्फ भारत देश को अपने परंपरागत दुश्मनों से रक्षा ही नहीं करती है बल्कि जब भी को किसी भी रूप में देश को भारतीय सेना की जरूरत पड़ी तो भारतीय सेना ने हमेशा सेवा भाव के लिए मौजूद रहती है। भारत में जब भी दुश्मनों की नापाक नजर पड़ी भारतीय सेना उन्हें माकूल जवाब दिया। आज भारतीय सेना दुनिया के सबसे बेहतरीन सेनाओं में से एक है। विश्व की चौथी सबसे शक्तिशाली सेना होने के साथ विश्व की तीसरी सबसे बड़ी वायु सेना है। भारतीय सेना सिर्फ अपनी सीमाओं की रक्षा करना नहीं जानती बल्कि जरूरत पड़े, तो दुश्मन देश के अंदर घुस कर उसका अभिमान तोड़ना भी जानती है। आपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने दिखा दिया कि भारतीय सेना दुश्मन देश को अपनी शौर्यता और तकनीक के बलबूते किस हद तक नुकसान पहुंचा सकती है। जय हिंद की सेना विश्व की सबसे शांतिप्रिय और अनुशासित सेनाओं में से एक है। जय हिंद की सेना राजनीति और व्यापार नहीं करती बल्कि जय हिंद की तो सेना भारत माता की सेवा करती है। दुश्मन देश भी इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि भारतीय सेवा अपने मातृ भूमि की रक्षा के लिए किस हद तक जा सकते हैं।

विजय किशोर तिवारी नई दिल्ली

पोस्ट

महाराष्ट्र निकाय चुनावों का सार है एनसीपी के दोनों धड़ों के समक्ष अस्तित्व का संकट है। वहीं, कांग्रेस और ठाकरे परिवार के पास वापसी की गुंजाइश है। कांग्रेस को समझदारी के साथ गठजोड़ करने होंगे। उसके लिए ठाकरे को छोड़ना हिंदुत्ववादी शक्तियों को ही मजबूत करेगा। सुहास पलशिकर@PalshikarSuhas

करियर के उतार पर सीमित काम मिलने के पीछे एआर रहमान को सांप्रदायिकता दिख रही है। जब उन्हें भरपूर काम मिल रहा था तो क्या उन्होंने भारत की उदारता के गीत गाए थे? रहमान, शाहरुख, सलमान और आमिर सबको भारत ने ही सितारा बनाया, किसी मुस्लिम देश ने नहीं। अमिताभ अग्निहोत्री@Aamitabh2

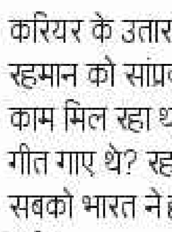

डेनमार्क ग्रीनलैंड में सैन्य मौजूदगी बढ़ा रहा है। स्वीडन, नार्वे, जर्मनी और फ्रांस संयुक्त सैन्य अभ्यास कर रहे हैं। यूरोप ग्रीनलैंड में सैन्य तैनाती कर रहा है, ताकि ट्रंप उसे बलपूर्वक न ले सकें। संदेश साफ है-ग्रीनलैंड लेने के लिए ट्रंप को यूरोपीय खून बहाना पड़ेगा। यही आशावादी प्रतिरोध है, न कि यह विश्वास कि यूरोप वास्तव में द्वीप की रक्षा कर पाएगा। यूसुफ ऊंझावाला@YusufDFI

जनपथ

बेशर्मी से रख लिया दूजे का सम्मान,
रहा अधूरा स्वयं को मिलने का अरमान।
मिलने का अरमान अजब चल रही बकैती,
अब नोबेल पर आप डालने लगे डकैती!
चढ़ी ट्रंप को दीख रही है ऐसी गर्मी,
इज्जत रखकर ताख दिखाते वे बेशर्मी!!

– ओमप्रकाश तिवारी

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान संपादक-स्व. नरेन्द्र मोहन, चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक-महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान संपादक-संजय गुप्त, नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा जागरण प्रकाशन लि. के लिए, डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित एवं 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित, संपादक (दिल्ली एनसीआर) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No 50755/90 समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त। वर्ष 36 अंक 185

हां 92% / नहीं 8%
क्या लंबे समय के संघर्ष में स्वदेशी रक्षा उद्योग की आपूर्ति निर्णायक साबित होगी?

हां 46% / नहीं 54%
क्या केंद्र सरकार रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने के जरूरी संसाधनों का आवंटन कर रही है?

मुद्दा से संबंधित अपनी राय, सुझाव और प्रतिक्रिया mudda@jagran.com पर भेज सकते हैं।

स्वदेशी हथियार, कितने तैयार

वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में वही देश बाहरी हमलों और रक्षा चुनौतियों से प्रभावी तरीके से निपट सकता है, जो हथियारों और रक्षा साजो-सामान के मामले में आत्मनिर्भर हो। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अगुआई में राजग सरकार ने 2014 में सत्ता में आते ही बात को समझ लिया था और सरकार स्वदेशी रक्षा उद्योग का मजबूत ढांचा तैयार करने पर लगातार जोर दे रही है। आज सेना की गोला-बारूद की 90 प्रतिशत जरूरतें घरेलू रक्षा उद्योग पूरी कर रहा है। हाल में थल सेना प्रमुख जनरल उपेन्द्र द्विवेदी ने इस बात को रेखांकित करते हुए कहा कि युद्ध का स्वरूप तेजी से बदल रहा है और स्वदेशी रक्षा आपूर्ति भविष्य के संघर्ष में निर्णायक भूमिका निभाएगी। विशेषज्ञों का मानना है कि रूस-यूक्रेन युद्ध और इजरायल-इरान संघर्ष ने दिखाया है कि लंबे समय तक चलने वाले संघर्ष में वही देश टिक सकते हैं, जिनका घरेलू उद्योग रक्षा आपूर्ति में सक्षम हो। आपरेशन सिंदूर के दौरान हमें घरेलू रक्षा उद्योग की क्षमताओं और कमियों का अंदाजा हो गया है। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत का नारा तभी सार्थक होगा, जब हमारी सेनाएं स्वदेशी ड्रोन से लेकर स्वदेशी लड़ाकू विमान तक से लैस हों। इसके लिए बड़े पैमाने पर संसाधनों और शोध एवं विकास के मजबूत ढांचे की जरूरत है। ऐसे समय में जब बांग्लादेश भी भारत के हितों के खिलाफ चीन और पाकिस्तान की खतरनाक धुरी में शामिल होने की राह पर है, हमारी सुरक्षा चुनौतियां अप्रत्याशित रूप से बढ़ गई हैं। ऐसे में स्वदेशी रक्षा उद्योग के वर्तमान इकोसिस्टम और शोध एवं विकास के लिए जरूरी संसाधनों के आवंटन की पड़ताल अहम मुद्दा है...

रक्षा पीएसयू के उत्पादन की कीमत
(करोड़ रुपये में)

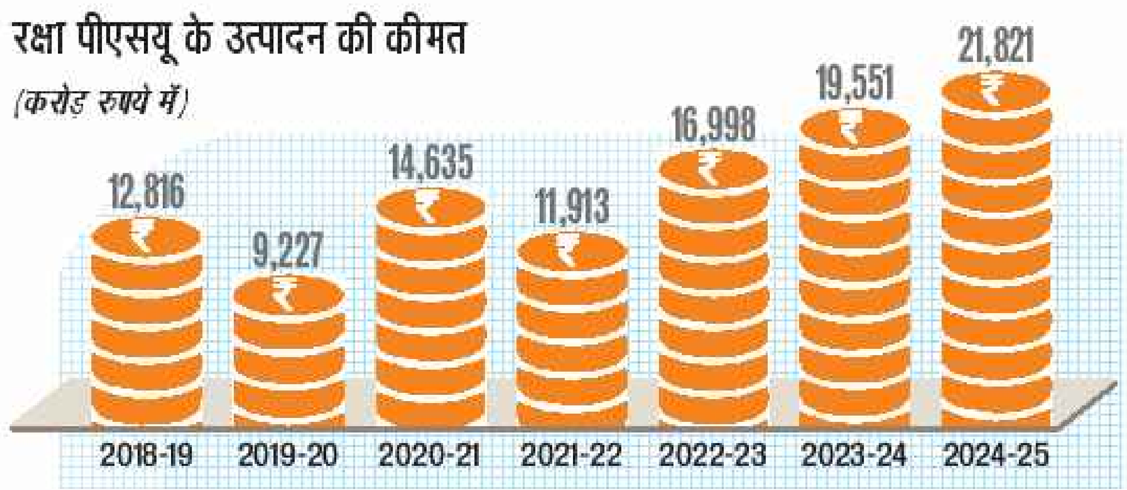

सेक्टर में रक्षा उत्पादन

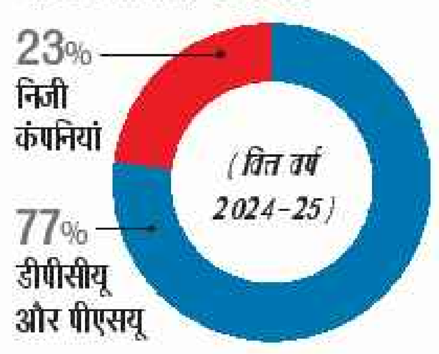

रक्षा क्षेत्र में बजट आवंटन का बंटवारा

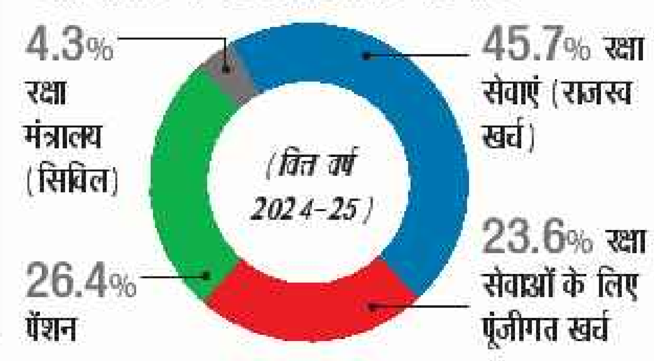

सेनाओं की 70 प्रतिशत तक जरूरतें पूरी कर रहा है घरेलू रक्षा उद्योग

आपरेशन सिंदूर में दुनिया ने भारत के स्वदेशी हथियारों और एयर डिफेंस सिस्टम की ताकत देखी। विज्ञानियों के दशकों के प्रयास से देश ने यह क्षमता हासिल की है। आज देश का घरेलू रक्षा उद्योग सेनाओं की करीब 70 प्रतिशत जरूरतें पूरा कर रहा है। गोला-बारूद से लेकर एयर डिफेंस सिस्टम, ड्रोन और मिसाइल टेक्नालाजी के मोर्चे पर देश तेजी से अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है। लड़ाकू विमान तेजस वायुसेना में शामिल हो चुके हैं। अब इसके उन्नत संस्करण का उत्पादन भी तेज हो गया है और तेजस मार्क-2 की पहली उड़ान भी अगले कुछ वर्षों में प्रस्तावित है। देश स्वदेशी लड़ाकू विमानों और जेट इंजन का मजबूत इकोसिस्टम बनाने के लिए प्रयासरत है। **महेंद्र सिंह** बता रहे हैं घरेलू रक्षा उद्योग की वर्तमान स्थिति और भविष्य की संभावनाओं के मोर्चे पर हम कहां खड़े हैं।

स्वदेशी होगा पांचवीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान

₹10,000 करोड़ पांचवीं पीढ़ी के विमान के विकास के लिए मंजूर किए हैं केंद्र सरकार ने

2035 तक बड़े पैमाने पर वायुसेना के लिए शुरू हो सकता है उत्पादन

- स्टेल्थ क्षमता से लैस पांचवीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान बना रहा है भारत, खत्म होगी आयात पर निर्भरता

बीते सात वर्षों में ऐसे बढ़ी भारत में डिफेंस मैन्यूफैक्चरिंग
(करोड़ रुपये में)

डीआरडीओ बना रहा है भविष्य के हथियार

सिस्टम	टाइप	खासियत	वर्तमान स्थिति
हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल	रणनीतिक हमले के लिए	मैक 5 से अधिक गति	अंडर डेवलपमेंट
ब्रह्मोस एनजी	सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल	हवा से जमीन पर करती है हमला	चल रहे हैं परीक्षण
ब्रह्मोस-2	हाइपरसोनिक	1500 किलोमीटर रेंज	2026-27 में परीक्षण
अस्त्र एमके-2, एमके-3	एयर टू एयर	बियांड विजुअल	ट्रायल जारी
रूदम-2/4	एयर टू ग्राउंड	एंटी रेडिएशन	पाइपलाइन में

भारत को अभेद्य बनाएगा सुदर्शन चक्र

- हवाई हमलों को रोकने और जवाबी हमले के लिए विज्ञानी तैयार कर रहे सुदर्शन चक्र
- एयर डिफेंस सिस्टम और दूसरी प्रणालियों का नेटवर्क तैयार करेगा मल्टी लेयर एयर डिफेंस
- 2035 तक देश को हमलावर लड़ाकू विमान, मिसाइलों और ड्रोन के खिलाफ होगी सुदर्शन चक्र की तैनाती

चुनौतियां

- राष्ट्रीय सुरक्षा की चुनौतियों से निपटने के लिए पर्याप्त संसाधनों का आवंटन न होना
- डीआरडीओ के प्रोजेक्ट को समय से मंजूरी न मिलना, फंड आवंटन में देरी
- सेनाओं और डीआरडीओ के बीच आपसी समन्वय और भरोसे की कमी

उत्पादन क्षमता बढ़ाए रक्षा उद्योग

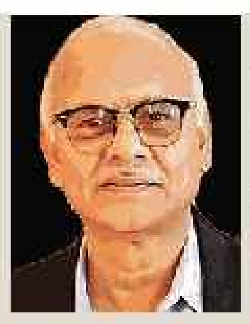

हरि बाबू श्रीवास्तव
पूर्व महानिदेशक और विशिष्ट विज्ञानी डीआरडीओ

आपरेशन सिंदूर के दौरान हमें स्वदेशी हथियारों और आपूर्ति तंत्र का फायदा मिला। हालांकि यह कम अवधि का संघर्ष था। लंबी अवधि के संघर्ष के लिए हमें स्वदेशी रक्षा उद्योग की उत्पादन क्षमता और आपूर्ति तंत्र को मजबूत बनाना होगा। इसमें निजी क्षेत्र की भूमिका का विस्तार करना होगा।

विश्व की रक्षा और सुरक्षा व्यवस्था तनाव के दौर से गुजर रही है और भारत भी इससे अछूता नहीं है। भारत की रक्षा-सुरक्षा के आयाम अब ढाई फ्रंट से बढ़कर साढ़े तीन फ्रंट तक हो गए हैं। बिगड़ती सुरक्षा परिस्थितियों के मद्देनजर अंतरराष्ट्रीय संबंधों में भी उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं। रक्षा निर्यात के अग्रणी देश स्वयं अपनी सुरक्षा से जुड़े मुद्दों से निपटने में व्यस्त हैं। भारत के प्रतिकूल कई हित-समूह बन गए हैं अथवा बन सकते हैं जिससे ये पता लगाना असंभव प्रतीत होता है कि आपातकाल में कौन सा देश भारत के साथ होगा और कौन सा विपक्ष में। मूल सार यह है यदि भारत को अपनी सीमाओं की सुरक्षा करनी है, यदि निर्णय लेने की क्षमता में सार्वभौमिकता सुनिश्चित करनी है तो हमें तकनीकी योग्यता व क्षमता में भी आत्मनिर्भर बनना ही पड़ेगा, साथ ही अपनी तकनीकी व आपूर्ति श्रृंखला की सार्वभौमिकता भी सुनिश्चित करनी ही पड़ेगी।

आत्मनिर्भरता अब कोई नारा अथवा विकल्प नहीं, बल्कि आवश्यकता है। इन्हीं परिस्थितियों के चलते राजग सरकार ने 2014 में स्किल इंडिया व मेक इन इंडिया, 2015 में टीडीएफ (प्रौद्योगिकी विकास फंड), 2016 में स्टार्टअप इंडिया, 2018 में आइडेक्स (आइडीईएक्स), 2020 में आत्मनिर्भर भारत आदि योजनाएं चलाईं और नीतिगत फैसलों के साथ उनका कार्यान्वयन सुनिश्चित किया। इसके साथ ही रक्षा विज्ञान अनुसंधान व रक्षा उत्पादन निजी क्षेत्र के लिए खोला गया, निजी क्षेत्र में अनुसंधान व नवाचार के लिए फंड की व्यवस्था की गई। केंद्र सरकार ने भारत में निर्मित हथियारों की खरीद में प्राथमिकता दी। हथियारों व उनके उपकरणों के स्वदेशीकरण के लिए उनकी लिस्ट सार्वजनिक की गई। विदेशी हथियारों के आयात पर प्रतिबंध लगाए गए। स्वदेशी हथियार-गोला बारूद खरीदने के लिए लक्ष्य निर्धारित किए गए, इत्यादि। साथ ही व्यापार में सुविधा के लिए नीतिगत ढांचा परिवर्तन किया गया। 2014 की तुलना में भारत आज आत्मनिर्भरता की दृष्टि से अत्यंत मजबूत स्थिति में है। आपरेशन सिंदूर ने यह सिद्ध कर दिया कि भारत अब अपने पैरों पर खड़ा हो चुका है। आपरेशन सिंदूर भाग-1 में भारतीय प्रोद्यौगिकी ने अपना लोहा तो मनवाया, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यह संघर्ष अल्पकालीन था। अब समय लंबे, बहुपक्षीय व बहुआयामीय व बहु-मोर्चा संघर्ष का है। भविष्य के संघर्षों में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कई देश सामिल हो सकते हैं (सिंदूर-1 में भी कम से कम चीन व तुर्किये तो शामिल थे ही)। हमें सीमाओं की सुरक्षा के साथ-साथ ऊर्जा, वित्त, खाद्य व स्वास्थ्य, साइबर सुरक्षा आदि भी सुनिश्चित करने होंगे। यह समय संपर्क रहित युद्ध का भी है जिसमें मानवरहित सेंसर, प्लेटफार्म व हथियार जो स्थान-काल-परिस्थिति के अनुसार निर्णय लेने की क्षमता रखते हों, का बोलबाला होगा। ये आयुध व उपकरण न केवल सेनाओं को बल्कि आंतरिक सुरक्षा बलों को भी उपलब्ध कराने होंगे। यह समय अत्यंत तेज गति से क्षति पहुंचाने वाले हथियारों का भी है जिनका विकास व निर्माण सुनिश्चित करना होगा। यह समय गैर परंपरागत हथियारों (जैसा कि अमेरिका ने वेनेजुएला में किया) का भी है, जिनके विकास पर भी बल देना होगा। अब युद्ध मात्र सीमा पर ही नहीं लड़े जाएंगे इसलिए सेना व आंतरिक रक्षा बलों के संसूचकों व हथियारों में भी सामंजस्य लाना होगा। आवश्यकता है कि पूरे देश में संसूचकों का नेटवर्क बिछाया जाए, इस नेटवर्क का बाह्य सूचना तंत्र के साथ एकीकरण किया जाए व कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा खतरों के निष्कर्ष तक पहुंचा जाए। भारत की रक्षा अनुसंधान व उत्पादन इकाइयों को सेना व आंतरिक सुरक्षा बलों की एकीकृत आवश्यकताओं की जानकारी उपलब्ध करानी होगी। उनके लिए धन, समय सीमा में खरीद व कंपनियों के भुगतान सुनिश्चित करने होंगे। प्रधानमंत्री द्वारा 'सुदर्शन चक्र' योजना की घोषणा इसी कड़ी में पहला कदम है।

आपकी आवाज

वर्तमान समय में हम रक्षा जरूरतों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रह सकते हैं। इसका कारण यह है कि संकट के समय दूसरे देश रक्षा आपूर्ति के लिए हम पर शर्ते थोप सकते हैं। कारगिल युद्ध के अनुभव बताते हैं मित्र देश हों या दूसरे देश आपात खरीद में वह मनमानी कीमत वसूलते हैं और हथियार की गुणवत्ता की गारंटी भी नहीं होती है। ऐसे में हर कीमत पर रक्षा साजो- सामान के लिए स्वदेशी आपूर्ति को मजबूत करना होगा। देश इस मामले में सही दिशा में आगे बढ़ रहा है लेकिन रफ्तार बढ़ाने की जरूरत है। **श्रवण गुप्ता**

संसाधनों की कमी और सरकार के स्तर पर प्रोजेक्ट मंजूर करने में देरी की वजह से हम रक्षा के क्षेत्र में शोध एवं विकास को उस रफ्तार से आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं, जिसकी जरूरत है। अब भी सरकारी तंत्र स्वदेशी प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने में टाल मटोल की नीति अपनाता है। करीब तीन दशकों के प्रयास के बावजूद हम आज तक स्वदेशी जेट इंजन नहीं बना पाए हैं। आपरेशन सिंदूर ने यह दिखाया है कि स्वदेशी तकनीक के क्या फायदे हो सकते हैं। ऐसे में सरकार के स्तर पर यह जरूरी हो गया है कि वह स्वदेशी हथियारों के विकास में तेजी लाने के लिए जरूरी संसाधन उपलब्ध कराए। **मुकेश पासवान**

चीन और पाकिस्तान का रणनीतिक गठजोड़ हमारी सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। ऐसे में हमारी रक्षा तैयारियां उच्चतम स्तर पर होनी चाहिए। इसमें स्वदेशी हथियार और रक्षा उपकरणों की अहम भूमिका है। ऐसे में देश को इस लक्ष्य के साथ काम करना चाहिए कि अगले 10 वर्ष में हमें रक्षा उपकरण विदेशों से आयात करने की जरूरत न पड़े। **उज्जवल त्रिपाठी**

आत्मनिर्भरता की मजबूत नींव तैयार

नीरज गुप्ता
प्रबंध निदेशक, एमकेयू लिमिटेड

रक्षा आत्मनिर्भरता का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सैनिक, इंजीनियर और कमांडर यह भरोसा महसूस करें कि राष्ट्र संकट के पहले दिन से अंतिम दिन तक उनके साथ खड़ा है। भारत ने इस दिशा में मजबूत नींव रख दी है। अब समय है इसे निर्णायक राष्ट्रीय शक्ति में बदलने का।

सीमा पर तैनात सैनिक के लिए रक्षा आत्मनिर्भरता कोई नारा नहीं है। यह इस बात का निर्धारक है कि संकट के समय हथियार, गोला-बारूद और सुरक्षा उपकरण समय पर मिलेंगे या नहीं, काम करेंगे या नहीं, और क्षति की स्थिति में कितनी जल्दी दोबारा उपलब्ध हो पाएंगे। पिछले एक दशक में भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता की दिशा में हुई प्रगति देश की राष्ट्रीय सुरक्षा नीति में सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक बदलावों में से एक है। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसी पहलों के माध्यम से भारत ने रक्षा क्षेत्र में आयात-आश्रित सोच से बाहर निकलकर एक विविध, सशक्त और लचीले स्वदेशी रक्षा औद्योगिक ढांचे के निर्माण की दिशा में ठोस कदम बढ़ाए हैं। यह परिवर्तन केवल नीतिगत घोषणाओं तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसके ठोस परिणाम सामने आए हैं। स्वदेशी रक्षा उत्पादन 1.27 लाख करोड़ के स्तर को पार कर चुका है, जिसमें निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी लगभग 25 प्रतिशत तक पहुंच चुकी है। रक्षा निर्यात वित्त वर्ष 2024–25 में 23,622 करोड़ तक पहुंच गया है, जो एक दशक पहले की तुलना में लगभग 30 गुना वृद्धि को दर्शाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज भारतीय थल सेना की लगभग 90 प्रतिशत गोला-बारूद आवश्यकताएं देश के भीतर ही पूरी हो रही है। यह तथ्य युद्धकालीन तैयारियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

हाल के वैश्विक संघर्ष- चाहे रूस-यूक्रेन युद्ध हो या पश्चिम एशिया में लंबे समय से चल रहे सैन्य टकराव, एक सख्त सच्चाई उजागर करते हैं। आधुनिक युद्ध पहले महीने में नहीं, बल्कि दूसरे और तीसरे वर्ष में किसी देश की वास्तविक क्षमता की परीक्षा लेते हैं। ऐसे संघर्षों में जीत केवल उन्नत हथियारों से नहीं, बल्कि औद्योगिक निरंतरता, तेज मरम्मत और युद्ध के अनुभव के आधार पर त्वरित अनुकूलन से सुनिश्चित होती है। भारत ने आज तोपखाने, बख्तरबंद वाहन, मिसाइल प्रणालियां, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, ड्रोन, सेंसर, एयरोस्पेस और नौसैनिक प्लेटफार्म जैसे कई क्षेत्रों में स्वदेशी क्षमता विकसित की है। स्वदेशी लड़ाकू विमान, हेलिकाप्टर और युद्धपोत इस प्रगति के स्पष्ट उदाहरण हैं। फिर भी, जेट इंजन, लंबी दूरी के रडार, इलेक्ट्रानिक वारफेयर सिस्टम, उन्नत सामग्री और रक्षा इलेक्ट्रानिक्स जैसे उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में अभी भी निर्भरता बनी हुई है। इन क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता केवल औद्योगिक लक्ष्य नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा की आवश्यकता है। सरकार ने नीति स्तर पर सही दिशा तय की है। नकारात्मक आयात सूचियां, निजी क्षेत्र को अवसर, आइडीइएक्स जैसे मंच और रक्षा पूंजीगत व्यय में निरंतर वृद्धि ने रक्षा उद्योग को नया आत्मविश्वास दिया है। आज सैकड़ों स्टार्ट-अप और हजारों एमएसएमइ इस आपूर्ति श्रृंखला का हिस्सा हैं। अब चुनौती इन पहलों को कागज से जमीन तक पूरी गहराई से लागू करने की है।

रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (डीपीएसयू) इस पूरे तंत्र के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। आज डीपीएसयू नेतृत्व पर दोहरी जिम्मेदारी है। एक ओर जटिल सैन्य क्षमताओं की समयबद्ध डिलीवरी, और दूसरी ओर कठोर प्रशासनिक प्रक्रियाओं के भीतर काम करना। डीपीएसयू के पेशेवरीकरण पर चर्चा को आलोचना नहीं, बल्कि उन्हें अधिक सक्षम और प्रभावी बनाने के प्रयास के रूप में देखा जाना चाहिए। पेशेवर बोर्ड, प्रदर्शन-आधारित नेतृत्व कार्यकाल, अधिक परिचालन स्वायत्तता और स्पष्ट जवाबदेही ढांचे डीपीएसयू नेतृत्व को अपने दायित्व बेहतर ढंग से निभाने में मदद करेंगे। आगे का रास्ता स्पष्ट है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास में दीर्घकालिक निवेश, लागत के साथ रणनीतिक मूल्य को प्राथमिकता देने वाली खरीद नीति, 5–7 वर्ष के रोलिंग फ्रेमवर्क कान्ट्रैक्ट, रक्षा-विशिष्ट पीएलआइ योजनाएं, आधुनिक परीक्षण एवं प्रमाणन अवसंरचना, और रक्षा निर्यात को विदेश नीति के प्रभावी उपकरण के रूप में विकसित करना।

गैर-हिंदी भाषाओं के लिए तमिलनाडु का साहित्यिक पुरस्कार घोषित

चेन्नई, प्रेट्र : राजभाषा हिंदी के प्रति अपनी नफरत को एक बार फिर दर्शाते हुए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने सात गैर-हिंदी भारतीय भाषाओं के वार्षिक साहित्यिक पुरस्कारों की घोषणा की और साहित्य अकादमी पुरस्कारों में कथित राजनीतिक हस्तक्षेप के लिए केंद्र पर हमला किया। तमिलनाडु सरकार के तत्वावधान में यह पुरस्कार तमिल समेत सात क्षेत्रीय भाषाओं में पांच लाख रुपये की नकद राशि के साथ दिया जाएगा। इसे ''सेमोजी इल्लाकिया विरुधु (क्लासिकल लैंग्वेज लिटरेरी अवार्ड)'' नाम दिया गया है। पहले चरण में पुरस्कार तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ओड़िया, बांग्ला व मराठी भाषाओं में सर्वश्रेष्ठ कृतियों के लिए दिए जाएंगे।

रविवार को चेन्नई अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेले के समापन समारोह में अपने संबोधन में मुख्यमंत्री स्टालिन ने कहा कि हर साल तमिलनाडु सरकार की ओर से ''राष्ट्रीय स्तर'' के पुरस्कार दिए जाएंगे।

प्रेमिका की हत्या कर 10 दिन रखे रहा शव, टुकड़े-टुकड़े कर चूल्हे में जलाया

झांसी में सेवानिवृत्त 62 वर्षीय रेलकर्मी ने की लिव इन में रह रही महिला से हैवानियत, दो शादियां कर चुका आरोपित

जागरण संवाददाता, झांसी : सेवानिवृत्त रेलकर्मी ने हैवानियत की हद पार करते हुए साथ लिव-इन में रह रही उम्र में 25 वर्ष छोटी प्रेमिका की हत्या कर दी। इसके बाद 10 दिन तक कमरे में शव को रखे रहा और टुकड़े-टुकड़े कर चूल्हे में जलाता रहा। दो शादियां कर चुका आरोपित शनिवार रात प्रेमिका के शव के जले टुकड़े, हड्डियां आदि को नीले बक्से में रखकर अपने बेटे के सहयोग से ठिकाने लगाने निकला। जिस आटो में बक्से को रखा, उसके चालक ने सैंयर गेट तक पहुंचाने के बाद पुलिस को फोन कर दिया। बक्से से निकलते पानी और बदबू के कारण उसे मामला संदिग्ध लगा था। पुलिस ने रविवार शाम आरोपित को सैंयर गेट के पास से गिरफ्तार कर लिया। जांच में सामने आ रहा है कि प्रेमिका लगातार ब्लैकमेल कर रुपयों की मांग कर रही थी।

पुलिस के अनुसार रेलवे से सेवानिवृत्त 62 वर्षीय राम सिंह परिहार सैंयर गेट का रहने वाला है। उसकी पहले से दो शादियां हो चुकी हैं। पहली पत्नी निशा नन्दनपुरा में रहती है। मिनर्वा के पास दूसरी पत्नी गीता, अपने पुत्र नितिन, बहू और अन्य बच्चों के साथ रहती है। राम सिंह अपने से 25 वर्ष छोटी प्रीति रैकवार के साथ लिव इन में लहर गांव में किराये के मकान में रहता था। सीपरी बाजार थानाप्रभारी विनोद कुमार मिश्रा के अनुसार दूसरी पत्नी गीता ने बताया कि आइटीआइ के पास रहने वाली प्रीति रैकवार का राम सिंह परिहार के यहां आना-जाना था। दोनों के बीच संबंध हो गए। मिनर्वा के पास रहने वाले आटो चालक जय सिंह पाल ने पुलिस को बताया कि मुहल्ले का रहने वाला नितिन उसके पास शनिवार की रात आया और कहा, उसके पिता कुछ सामान, बक्सा आदि लेकर यहां रहने आ रहे हैं। 400 रुपये किराया तय करके जय सिंह साथ में लहर गांव चला गया। वहां राम सिंह परिहार ने नितिन व उसके दोस्तों के साथ एक नीले रंग के बाक्स को आटो में रखवाया। चालक ने बताया कि बाक्स में से पानी निकल रहा था। बदबू भी आ रही थी। आटो के पीछे बाइक से स्वयं राम सिंह चलने लगा, लेकिन रास्ते में कब गायब हो गया, पता ही नहीं चला। नितिन और उसके दो-तीन दोस्त आटो के साथ पीछे-पीछे चल रहे थे। मिनर्वा चौराहा के पास दाऊ समोसे वाली गली के अंदर फूटा चौपड़ा में उन लोगों ने बक्सा उतार लिया। चालक ने किराये के पैसे लिए, पर मामला संदिग्ध देखते हुए डायल 112 को फोन कर दिया।

छत्तीसगढ़ से लातेहार जा रही बस पलटी, छह की मौत

संवाद सूत्र, जागरण • महुआडांड़ (लातेहार) : छत्तीसगढ़ से झारखंड के लोध फाल जा रही यात्रियों से भरी एक बस रविवार को लातेहार के महुआडांड़ स्थित ओरसा घाटी में भीषण हादसे का शिकार हो गई। दुर्घटना में चार महिलाओं समेत छह लोगों की मौत हो गई, जबकि 70 से अधिक लोग घायल हो गए।

छग व झारखंड की सीमा पर हुए इस हादसे के कारण घटनास्थल पर काफी देर तक चीख-पुकार मची रही। पुलिस के अधिकारी, जवान और स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए राहत अभियान चलाया और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। प्रथमदृष्टया बस का ब्रेक फेल होने से दुर्घटना होने की बात सामने आ रही है। वहीं, बस में क्षमता से अधिक यात्रियों का सवार होना भी हादसे का कारण माना जा रहा है। बस में 80 से अधिक लोग सवार थे। घायलों को छग और झारखंड के अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती किया गया है।

अब छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य को परखेंगे उच्च शिक्षण संस्थान, उपचार भी मिलेगा

अरविंद पांडेय • जागरण

नई दिल्ली: उच्च शिक्षण संस्थान अब छात्रों की पढ़ाई के साथ ही उनके मानसिक स्वास्थ्य को भी परखेंगे। यदि किसी छात्र की मानसिक स्थिति ठीक नहीं दिखी तो तुरंत इसे संस्थान में स्थापित मानसिक स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र में भेजेंगे, जहां पेशेवर मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ उसकी जांच करेंगे। जरूरत पड़ने पर उसे समुचित उपचार भी मुहैया कराएंगे।

उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्रों के आत्महत्या की बढ़ती घटनाओं व तेजी से सामने आ रहे मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े मामलों को देखते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर इससे निपटने के लिए एक एकीकृत नीति तैयार की है। इसे पिछले दिनों यूजीसी बोर्ड ने भी मंजूरी दे दी है। इस नीति के तहत प्रत्येक उच्च शिक्षण संस्थान में मानसिक स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र बनाने के साथ इनमें प्रशिक्षित मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों को तैनात करने के निर्देश दिए हैं। छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य पर नजर रखने के लिए प्रत्येक पांच सौ छात्रों पर एक वरिष्ठ शिक्षक को बतौर मेंटर एवं छात्रों के बीच से प्रत्येक सौ छात्रों पर एक सहायक छात्र की तैनाती करने को कहा है।

- **यूजीसी ने बनाई नीति, हर संस्थान में होगा मानसिक स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र**
- **इन मानसिक स्वास्थ्य केंद्रों में तैनात होंगे पेशेवर मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ**

इन कारणों से यह कदम उठाने की पड़ी जरूरत

- देश की कुल जनसंख्या में करीब 10.6 प्रतिशत लोग मानसिक स्वास्थ्य समस्या से पीड़ित
- इनमें 18 से 29 आयुवर्ग के 7.3 प्रतिशत युवा गंभीर मानसिक स्वास्थ्य की समस्या से घिरे
- एनसीआरबी की रिपोर्ट, देश में कुल आत्महत्याओं में करीब 7.6 प्रतिशत छात्रों के मामले

हेल्पलाइन नंबर भी होगा स्थापित: यूजीसी ने इसके साथ ही प्रत्येक उच्च शिक्षण संस्थान से छात्रों की मदद के लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी स्थापित करने को कहा है। जहां छात्रों को चौबीस घंटे मदद मिल सके। इस नीति में यूजीसी ने आत्महत्या की घटनाओं को रोकने के लिए प्रत्येक संस्थान से एक कार्ययोजना भी बनाने को कहा है।

अविमुक्तेश्वरानंद की शोभायात्रा रोकने पर गुस्साए शिष्यों की पुलिस से झड़प

जागरण संवाददाता, प्रयागराज: मौनी अमावस्या पर पालकी से शोभायात्रा निकालने पर जगद्गुरु स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को पुलिस ने रोका तो विवाद हो गया। उनके शिष्यों और पुलिस के बीच झड़प हो गई। गुस्साए शिष्यों ने बैरिकेडिंग तोड़ दी। पुलिस ने उनके शिष्य प्रतक्षचैतन्य मुकुंदानंद गिरि सहित कई लोगों को हिरासत में ले लिया। अविमुक्तेश्वरानंद को भी वहां से हटा दिया गया। इसके बाद वह अपने त्रिवेणी मार्ग स्थित शिविर के बाहर बिना कुछ खाए धरने पर बैठ गए। शिष्यों ने पुलिस पर दुर्व्यवहार और पिटाई करने का आरोप लगाया है। घटना के कुछ वीडियो भी इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुआ है जिसमें पुलिसकर्मी बटुकों को पीटने के साथ उनकी चोटी खींचता दिखाई दे रहा है। संतों से पुलिस वाले अभद्रता से बातचीत भी कर रहे हैं।

मौनी अमावस्या पर शोभायात्रा के साथ स्नान करने को लेकर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को संगम नोज क्षेत्र से बाहर ले जाते पुलिस कर्मी ● मुकेश कनौजिया

पुलिस आयुक्त जोगेंद्र कुमार ने कहा कि रथ, पालकी की परंपरा नहीं थी। कई बार निवेदन करने के बाद भी नहीं माने।

त्रिवेणी तट पर मौन कोलाहल, लौकिक-अलौकिक ऊर्जा की अनुभूति

शरद द्विवेदी ● जागरण

प्रयागराज : मौनी अमावस्या के मुहूर्त ने अमृतधारा में जैसे प्रवेश किया, श्रद्धालुओं का तपोबल उर्जित हो उठा। साधकों के लिए आत्मिक उत्कर्ष और शांति का महायोग बना। चरम पर चढ़ी श्रद्धा और आस्था के आवेग में शनिवार रात 11.53 बजे अमावस्या लगते ही त्रिवेणी में स्नान आरंभ हो गया। मकर राशि में मंगल, बुध, शुक्र और सूर्य का संचरण होने से चतुर्ग्रहीय योग बनने और अमावस्या का प्रभाव दिनभर रहने से उत्साह अधिक रहा। मेला प्रशासन का दावा है कि शाम छह बजे तक 4.52 करोड़ लोगों ने स्नान किया।

मेला प्रशासन के दावे के अनुसार शनिवार को 1.5 करोड़ लोग स्नान कर चुके थे। मौनी अमावस्या पर आकाश पथ से झर-झर बरसती पुष्पों की पंखुड़ियों ने सबका हृदय प्रफुल्लित कर दिया। आह्वान अखाड़ा के संत गीतानंद गिरि के नेतृत्व में नागा संन्यासियों ने अस्त्र-शस्त्र का प्रदर्शन करते हुए संगम में स्नान किया। वैष्णव संप्रदाय के अखाड़े दिगंबर अनी, निर्मोही अनी व निर्वाणी अनी के संतों ने खाकचौक व्यवस्था समिति के महामंत्री जगद्गुरु संतोषाचार्य सतुआ बाबा के नेतृत्व में स्नान करने गए। छत्र-चंवर और अखाड़े के ध्वज के साथ स्नान किया। श्रीपंचायती अखाड़ा निर्मल के महंत ज्ञान दास के नेतृत्व में संतों ने डुबकी लगाई।

प्रयागराज में रविवार को मौनी अमावस्या के अवसर पर आस्था का जन समुद्र उमड़ा। त्रिवेणी संगम पर पवित्र स्नान करने के लिए श्रद्धालुओं ने शनिवार रात में ही यहां पहुंचना शुरू कर दिया था ● एएनआइ

भीड़ उमड़ने पर इमरजेंसी प्लान लागू, ऐरावत घाट पर स्नान: रविवार सुबह छह बजे से 10 बजे तक तीन बार संगम के सभी स्नान घाटों पर क्षमता से अधिक भीड़ हो गई। संगम का सर्कुलेटिंग एरिया चोक हो जाने की वजह से प्रशासन को इमरजेंसी प्लान लागू करना पड़ा। स्नान घाटों को खाली कराया गया।

सीएम योगी ने किया अभिनंदन: मौनी अमावस्या स्नान पर्व पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर पोस्ट कर श्रद्धालुओं का अभिनंदन किया। लिखा- ''आस्था के महापर्व मौनी अमावस्या के पावन अवसर पर पवित्र संगम स्नान के लिए पधारे सभी पूज्य अखाड़ों, धर्माचार्यों, संतगणों, साधकों, कल्पवासियों और श्रद्धालुओं का आत्मीय अभिनंदन।

एक नजर में

एसआइआर के खिलाफ लोगों ने टायर जलाकर किया विरोध प्रदर्शन

कोलकाता: बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के बादुड़िया में मतदाता सूची के विशेष गहन परीक्षण (एसआइआर) के माध्यम से आम जनता के उत्पीड़न के आरोपों को लेकर रविवार को स्थानीय लोगों ने उग्र विरोध प्रदर्शन किया तथा टायर जलाकर सड़क जाम कर दी। बादुड़िया के शिमुलतला इलाके के बूथ नंबर 69 पर मतदाताओं ने आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग एसआइआर के नाम पर आम जनता को परेशान कर रहा है। (जासं)

विचाराधीन कैदी को एसआइआर सुनवाई केंद्र में ले गई बंगाल पुलिस

कोलकाता: बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के बनगांव इलाके में एक विचाराधीन कैदी को पुलिस मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) के लिए सुनवाई केंद्र में ले गई। कैदी का नाम शकील शेख है। वह यौन उत्पीड़न के मामले में पिछले 17 महीनों से कृष्णानगर जेल में न्यायिक हिरासत में है। (राब्यू)

खुले समुद्र में मछली पालन परियोजना का शुभारंभ

श्रीविजयपुरम : केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में देश की पहली खुली समुद्री मछली पालन परियोजना का शुभारंभ किया। राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान के अधिकारी ने बताया कि खुले समुद्र में सीबास और कोबिया मछलियों का पालन-पोषण किया जा रहा है, प्रायोगिक तौर पर समुद्री शैवाल की खेती भी हो रही है। (प्रेट्र)

बंगाल में भाजपा के सुशासन का आना जरूरी : प्रधानमंत्री

सिंगुर की रैली से बंगाल में असली परिवर्तन का आह्वान

राज्य ब्यूरो, जागरण ● कोलकाता: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रविवार को उद्योग, रोजगार व घुसपैठ के मुद्दे को केंद्र में रखते हुए ममता सरकार पर तीखा हमला बोला। कहा कि बंगाल से टीएमसी के महाजंगलराज को समाप्त करना और भाजपा के सुशासन का आना बहुत जरूरी है। विधानसभा चुनाव से पहले बंगाल दौरे के दूसरे दिन हुगली जिले के सिंगुर में भाजपा की परिवर्तन संकल्प रैली को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि बंगाल की जनता अब टीएमसी की निर्मम सरकार को सबक सिखाने की ठान चुकी है, ताकि यहां भी भाजपा की सरकार बने और विकास व सुशासन का मार्ग प्रशस्त हो।

पीएम मोदी ने असली परिवर्तन लाने का आह्वान करते हुए कहा कि देश में जो भी सरकारें विकास और गरीब कल्याण के कार्यों में रुकावट डालती हैं, उन्हें लगातार सजा मिलती रही है। दिल्ली में भी ऐसी ही सरकार थी जो केंद्र की योजनाओं को लागू नहीं होने देती थी। इसलिए दिल्ली की जनता ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब बंगाल में हर कोई टीएमसी के 15 वर्ष के महाजंगलराज को बदलना चाहता है। कभी बंगाल की राजनीतिक दिशा और दशा बदल देने वाले सिंगुर की धरती से पीएम ने सत्ता परिवर्तन की हुंकार भरते हुए कहा कि बंगाल में भाजपा की डबल इंजन वाली सरकार होनी चाहिए, क्योंकि इससे विकास को गति मिलेगी। मोदी ने पलटानो दोरकार, चाई बीजेपी सरकार (पलटने की दरकार, चाहिए भाजपा सरकार) का नारा भी दिया। जनसभा से पहले पीएम ने लगभग 830 करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया। तीन नई अमृत भारत ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाई।

माफिया व सिंडिकेट राज खत्म करेंगे: पीएम मोदी ने बंगाल में कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर घेरते हुए आरोप लगाया कि राज्य में टीएमसी का सिंडिकेट राज बेखौफ चल रहा है। दंगाइयों, माफियाओं को यहां खुली छूट है। यहां हर चीज पर सिंडिकेट टैक्स लगाया जाता है। भाजपा सरकार इसे खत्म करेगी, यह मोदी की गारंटी है।

उद्योग और निवेश बंगाल में तभी आएंगे जब कानून-व्यवस्था की स्थिति सुधरेगी। बंगाल का सामर्थ्य बहुत बड़ा है, यहां बहुत बड़ी-बड़ी नदियां हैं, बहुत बड़े समुद्र तट हैं, उपजाऊ ज़मीन है। बंगाल के हर जिले में कुछ न कुछ खास है। भाजपा योजना बनाकर हर जिले की इस ताकत को बढ़ाएगी।

राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ करने का आरोप: पीएम ने टीएमसी सरकार पर वोट बैंक की राजनीति के लिए घुसपैठियों की मदद व राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ करने का भी आरोप दोहराया। कहा कि केंद्र सरकार सीमा पर बाड़ लगाने के लिए जमीन की मांग कर टीएमसी सरकार को बार-बार पत्र लिख रही है लेकिन राज्य सरकार ने कुछ नहीं किया।

सिंगुर में रविवार को आयोजित परिवर्तन संकल्प रैली को संबोधित करते प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ● एएनआइ

- बंगाल की जनता अब टीएमसी की निर्मम सरकार को सबक सिखाने की ठान चुकी है
- पीएम ने 830 करोड़ की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया

सिंगुर में पीएम ने उद्योग को लेकर नहीं दिया कोई बड़ा संदेश

पीएम मोदी ने सिंगुर की रैली में उद्योग को लेकर बड़ा संदेश नहीं दिया, इससे राजनीतिक विश्लेषक हैरान हैं। दो दशक पहले पूर्ववर्ती वाममोर्चा सरकार के खिलाफ ममता बनर्जी के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस द्वारा चलाए गए भूमि अधिग्रहण विरोधी आंदोलन के कारण टाटा की बहुचर्चित नैनो कार परियोजना सिंगुर से गुजरात स्थानांतरित हो गई थी। आंदोलनों की बदौलत 2011 के चुनाव में वाममोर्चा शासन समाप्त कर दिया था।

सरकार मुझे डराने की निरर्थक कोशिश कर रही : संजय सिंह

जागरण संवाददाता, वाराणसी: आप के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने रविवार को वीडियो जारी कर मणिकर्णिका घाट पर कुछ मंदिरों, मूर्तियों को नुकसान पहुंचने की बात दोहराई। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म की आस्था पर चोट पहुंचाने वालों के बजाय मेरे खिलाफ केस दर्ज किया गया। मूर्तियों के खंडित होने को लेकर माता अहिल्याबाई के परिवार ने ऐतराज जताया, भाजपा नेता सुमित्रा महाजन ने विरोध जताया। सरकार केस के जरिए मुझे डराने की निरर्थक कोशिश कर रही है। सरकार को मूर्तियां खंडित करने का गुनाह करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। वहीं, पप्पू यादव ने एक्स पर लिखा कि चाहे जितने भी एफआइआर कर लें, सच्चाई को एआइ बताकर कब तक झुठलाएंगे। प्राचीन मंदिरों और मूर्तियों को ध्वस्त करने वाला निश्चय ही महमूद गजनवी का अनुयायी होगा। क्या सरकार भाजपा की वरिष्ठ नेता सुमित्रा महाजन के खिलाफ भी एफआइआर दर्ज करेगी। काशी में सीएम योगी ने कहा था कि मणिकर्णिका घाट पर कोई मूर्ति नहीं तोड़ी गई। एआइ से बने वीडियो और तस्वीरें प्रसारित कर कांग्रेस लोगों को गुमराह कर रही है। मामले में कांग्रेस व आप नेता समेत आठ को आरोपित बनाया गया है।

लगाई गई बीएनएस की ये धाराएं

धारा 196 : धर्म, जाति, भाषा, समुदाय के आधार पर लोगों के बीच घृणा, दुश्मनी, वैमनस्य फैलाना

धारा 298 : धार्मिक या पूजा स्थल का अपमान

धारा 299 : बोलकर, लिखकर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना

धारा 353-1C : झूठी जानकारी, अफवाह फैलना।

एकनाथ शिंदे ने अपने पार्षदों को प्रलोभन या दबाव में नहीं आने के दिए निर्देश

राज्य ब्यूरो, जागरण ● मुंबई: उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मुंबई महानगरपालिका चुनाव का परिणाम आने के बाद एक पांचसितारा होटल में ठहराए गए अपने 29 पार्षदों से मुलाकात कर उन्हें भाजपा के साथ सत्ता बंटवारे का अंतिम समझौता होने तक किसी भी बाहरी दबाव या प्रलोभन में न आने को कहा है।

शिंदे के पार्टी सूत्रों का कहना है कि उन्होंने यह कदम नवनिर्वाचित पार्षदों को एक साथ प्रशिक्षित करने के लिए उठाया है, लेकिन इसका एक अर्थ यह भी लगाया जा रहा है कि शिंदे भाजपा के साथ नई महानगरपालिका में मेयर के पद एवं स्थायी समितियों की सौदेबाजी के लिए पार्षदों को अपनी निगरानी में रख रहे हैं। स्वयं शिंदे की ओर से ऐसा कोई बयान नहीं आया है, लेकिन उनकी पार्टी के कुछ नेता यह कहते सुनाई दिए हैं कि बीएमसी का मेयर ढाई-ढाई साल के लिए भाजपा और शिवसेना में बांटा जाना चाहिए। इसके पीछे उनकी पार्टी का एक तर्क यह भी है कि लगभग 25 साल तक बीएमसी में शिवसेना (अविभाजित) का मेयर रहा है। इसलिए उद्धव ठाकरे को कमजोर करने के लिए मुंबई में शिंदे की पार्टी का मेयर होना चाहिए।

एकनाथ शिंदे ● फाइल फोटो

वैसे शिवसेना (यूबीटी) के नेता उद्धव ठाकरे द्वारा मेयर पद की उम्मीद न छोड़ने व उनके नेताओं द्वारा शिंदे गुट के कई पार्षदों के संपर्क में होने से यह अनुमान है कि उद्धव उनके पार्षदों में सेंध लगा सकते हैं। वहीं प्रेट्र के अनुसार, वरिष्ठ भाजपा नेता नारायण राणे ने कहा कि शिवसेना (यूबीटी) के प्रमुख उद्धव और पार्टी सांसद संजय राउत आवश्यक संख्या की कमी के बावजूद बृहन्मुंबई महानगरपालिका में मेयर बनाने का सपना संजोए हैं। एएनआइ के अनुसार, एकनाथ शिंदे ने पार्षदों से कहा कि बीएमसी का मेयर महायुति से ही होगा।

पवार परिवार के एक होने के बाद अब दोनों की पार्टियों के विलय पर लग रहे कयास

ओमप्रकाश तिवारी ● जागरण

मुंबई: पुणे और पिंपरी-चिंचवड़ महानगरपालिकाओं के चुनाव शरद पवार और अजीत पवार के साथ आकर लड़ने के बावजूद चुनाव में सफलता भले न मिली हो, लेकिन दोनों परिवारों में कटुता दूर हो चुकी है। अब जिला परिषद के चुनाव भी एक साथ लड़ने का निर्णय करने के साथ ही दोनों पार्टियों के विलय के भी कयास लगाए जाने लगे हैं। लेकिन अजीत पवार ने इन चर्चाओं पर यह कहकर विराम लगाने की कोशिश की है कि दोनों पार्टियों के एक होने पर फिलहाल कोई बातचीत नहीं हुई है। जबकि अजीत पवार और सुप्रिया सुले दोनों सार्वजनिक रूप से स्वीकार कर चुके हैं कि दोनों परिवारों में अब कोई कटुता नहीं रही है।

- शहरों में पार्टी का घटता प्रभाव शरद और अजीत पवार को फिर साथ आने को कर रहा मजबूर
- दोनों जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव को भी साथ मिलकर लड़ेंगे

हाल ही में संपन्न हुए पुणे और पिंपरी-चिंचवड़ नगर निगम चुनावों में राकांपा के दोनों गुटों ने गठबंधन कर चुनाव लड़ा था, लेकिन नतीजे भाजपा के पक्ष में रहे। जानकारों का मानना है कि शहरी क्षेत्रों में पार्टी का घटता प्रभाव शरद पवार और अजीत पवार को एक बार फिर साथ आने के लिए कर रहा मजबूर कर रहा है। शनिवार को बारामती में उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने शरद पवार से मुलाकात की। इस बैठक में सुप्रिया सुले और रोहित पवार भी मौजूद थे। सुले ने कहा कि बातचीत का विवरण सार्वजनिक नहीं किया जा सकता, लेकिन पार्टी के भविष्य को लेकर चर्चा जारी है। चुनावी हार के बावजूद दोनों गुटों ने पांच फरवरी को होने वाले जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव भी साथ मिलकर लड़ने का निर्णय लिया है।

नितिन का निर्विरोध भाजपा अध्यक्ष बनना तय

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : बिहार के युवा नेता और पूर्व मंत्री नितिन नवीन भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे, यह तो पहले ही लगभग तय हो चुका था, लेकिन सोमवार को इसकी औपचारिकता भी पूरी हो जाएगी। नामांकन दाखिल करने से लेकर नामांकन पत्रों की जांच और नाम वापसी की प्रक्रिया इसी दिन पूरी होगी। चूंकि इस पद के लिए वर्तमान कार्यकारी अध्यक्ष ही अकेले प्रत्याशी मैदान में होंगे और ऐसे में वोटिंग की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी और नवीन को भाजपा अध्यक्ष घोषित कर दिया जाएगा। भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर मंगलवार को नितिन नवीन निवर्तमान अध्यक्ष जेपी नड्डा का स्थान ले लेंगे।

भाजपा के नए अध्यक्ष के लिए महीनों से चल रही अटकलों को भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के विराम देते हुए ऐसा कदम उठाया कि सभी हैरत में पड़े रह गए। पार्टी ने बिहार सरकार में पथ निर्माण मंत्री का दायित्व संभाल रहे मात्र पांच बार के विधायक 45 वर्षीय नितिन नवीन को अचानक 14 दिसंबर, 2025 को कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित कर दिया। इसके साथ ही यह माना जाने लगा कि पार्टी इन्हें ही स्थायी अध्यक्ष बनाते हुए भविष्य के लिए पार्टी संगठन को युवा ऊर्जा से लैस करना चाहता है। नितिन नवीन को यह दायित्व ऐसे समय में मिलने जा रहा है, जब उनके सामने बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी के विधानसभा चुनाव हैं। इनमें बंगाल, असम और तमिलनाडु का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण भी है। निस्संदेह अपने दायित्व और चुनौतियों को समझते हुए नितिन नवीन ने कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में ही इन राज्यों में दौरा करते हुए संगठनात्मक गतिविधियों में सक्रियता बढ़ा दी।

नितिन नवीन ● फाइल फोटो

- नामांकन, जांच और नाम वापसी की प्रक्रिया के बाद आज पूरी हो जाएगी औपचारिकता
- बतौर कार्यकारी अध्यक्ष काम जारी, पांच राज्यों में चुनाव से पहले लेंगे नड्डा का स्थान

सोमवार दोपहर दो से शाम चार बजे तक नामांकन, चार से पांच बजे तक जांच और शाम पांच से छह बजे के बीच नामांकन वापस लेने का समय निर्धारित है। शाम 6.30 बजे चुनाव अधिकारी द्वारा नामांकन के संबंध में प्रेस वक्तव्य जारी किया जाएगा। यदि मतदान आवश्यक हो तो उसके लिए मंगलवार को प्रातः 11.30 से दोपहर 1.30 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। हालांकि, इसकी संभावना न के बराबर है।

मथुरा में सपा महानगर अध्यक्ष ने सड़क पर तलवार से काटा केक

रविवार को होलीगेट चौराहे पर सपा की महानगर अध्यक्ष रितु गोयल की जन्मतिथि पर केक काटने के दौरान मौजूद कार्यकर्ता, इस दौरान जाम के बने रहे हालात ● जागरण

जागरण संवाददाता, मथुरा : सपा की महानगर अध्यक्ष रितु गोयल ने अपनी जन्मतिथि पर संजय मार्केट से होली गेट होते हुए जुलूस की अनुमति ली थी। उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ होली गेट पर जुलूस रोककर तलवार से केक काटा। केक पाने को होड़ मच गई। महिला कार्यकर्ताओं के साथ आए बच्चे भीड़ के दबाव में चीख उठे। जाम के हालात बन गए। वहीं अहिल्याबाई होल्कर पार्क में मंच बनाकर महिलाओं को गिफ्ट दिए। महिलाएं पार्क में लगी रेलिंग से होकर बाहर निकलीं। इससे हादसे की भी आशंका रही। अपर नगर आयुक्त सौरभ सिंह ने बताया, पार्क में निजी कार्यक्रम की नगर निगम से अनुमति नहीं ली गई है।

कोहरा बना काल, यूपी और पंजाब में हादसों में गई सात लोगों की जान

जागरण टीम, नई दिल्ली: उत्तर भारत के कई राज्यों में कोहरे का सितम कम होता नहीं दिख रहा। यूपी, और पंजाब में रविवार को कोहरा काल बनकर आया। यहां घने कोहरे के कारण दृश्ता बेहद कम होने की वजह से सात लोगों की मौत हो गई।

रामपुर में गलत दिशा से आ रहे आटो ने एक बाइक पर सवार तीन लोगों को टक्कर मार दी। हादसे में पिता-पुत्र समेत तीनों की मौत हो गई। मुरादाबाद में दिल्ली-लखनऊ हाईवे पर शनिवार रात लोधीपुर राजपूत गांव के पास एक कैंटर में कंटेनर पीछे से टकरा गया, जिसमें कंटेनर चालक की मौत हो गई। अमरोहा के आदमपुर में मैक्स गाड़ी एक गहरी खंदक पर पलट गई, जिसमें चालक की जान चली गई।

वहीं पंजाब में रविवार की सुबह घनी धुंध के कारण चार जिलों में हुए हादसों में दो लोगों की मौत हो गई।

'नए आयामों के कारण युद्ध जटिल, लड़ाई सीमाओं तक सीमित नहीं'

नागपुर, प्रेट्र : रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को कहा कि नए आयामों के कारण युद्ध बहुत जटिल हो गए हैं। लड़ाई अब केवल सीमाओं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ऊर्जा, व्यापार, शुल्क, आपूर्ति श्रृंखला, प्रौद्योगिकी और सूचना भी इसके नए आयामों का हिस्सा है।

सोलर इंडस्ट्रीज में गोला-बारूद संयंत्र के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए राजनाथ ने कहा कि एक समय ऐसा था, जब रक्षा उत्पादन केवल सार्वजनिक क्षेत्र तक सीमित था और निजी क्षेत्र की भागीदारी के बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। लेकिन, मौजूदा सरकार ने नीतियों में बदलाव और प्रक्रियाओं को सरल बनाकर इस क्षेत्र को खोल दिया है, क्योंकि उसे निजी क्षेत्र की क्षमता पर पूरा भरोसा है।

रक्षा मंत्री ने कहा कि इससे बेहतर गुणवत्ता, समयबद्धता में सुधार और उत्पादकता एवं वितरण में भी वृद्धि हो रही है। उन्होंने आपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल किए गए पिनाक मिसाइल और नागास्त्र ड्रोन जैसे रक्षा उत्पादन के लिए सोलर समूह की सराहना की। एएनआइ के अनुसार, रक्षा मंत्री ने कहा कि आपरेशन सिंदूर के दौरान हमने आपकी प्रतिभा और कुशलता देखी। राजनाथ ने कहा कि घरेलू रक्षा उत्पादन 2014 में 46 हजार करोड़ रुपये से बढ़कर अब 15 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया है, जिसमें निजी क्षेत्र का योगदान 30 हजार करोड़ रुपये है।

नागपुर में 30 एमएम के गोला-बारूद निर्माण संयंत्र के उद्घाटन समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ● एएनआइ

भोपाल में रामभद्राचार्य और अन्य धर्मगुरुओं को कहे अपशब्द

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल: मध्य प्रदेश में एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के विभिन्न संगठनों के कई नेताओं ने रविवार को भोपाल में अभद्र भाषा का प्रयोग किया। ब्राह्मण बेटियों को लेकर असभ्य बयान देने वाले आइएएस अधिकारी संतोष वर्मा पर कोई कार्रवाई नहीं किए जाने की मुख्य मांग समेत अन्य कई मांगों के बहाने भेल दशहरा मैदान में आयोजित एससी-एसटी-ओबीसी संगठनों के संयुक्त मोर्चा के सम्मेलन में जुटे नेताओं ने प्रसिद्ध कथावाचक धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री, जगद्गुरु स्वामी रामभद्राचार्य तक को लेकर अपशब्द कहे।

एसटी-एससी-ओबीसी संगठनों के नेताओं ने संतोष वर्मा पर कार्रवाई नहीं करने सहित अन्य मांगों को लेकर किया सम्मेलन

छतरपुर के चांदला से भाजपा के पूर्व विधायक आरडी प्रजापति ने स्वामी रामभद्राचार्य के वीडियो का हवाला देकर उनके लिए कहा, 'तुम वाइफ को एंज्वाय की वस्तु बताते हो, इसलिए तुम्हारी आंख खराब है।' मैं कहता हूं, मुझे फांसी दे दी जाए, संतोष वर्मा को आइएएस अधिकारी के पद से हटा दिया जाए, पर पहले ऐसे बाबाओं पर कार्रवाई होनी चाहिए। दलित पिछड़ा समाज संगठन के संस्थापक दामोदर यादव ने पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री को अपशब्द कहे। कहा, 'छतरपुर में पाखंड की दुकान खोले हैं। कहते हैं दुनिया का इलाज पर्ची से कर देंगे।

देवभूमि के देवत्व की रक्षा करेंगे, छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं : धामी

- जागरण फोरम में मुख्यमंत्री धामी के तेवर कड़े, बोले- हम दावे नहीं, काम करके दिखाते हैं
- जनसांख्यिकीय परिवर्तन और लैंड-लव जिहाद के लिए कांग्रेस पर किया प्रहार

राज्य ब्यूरो, जागरण ● देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के तेवर अब कड़े और आक्रामक हैं। उनके सीधे निशाने पर अब विपक्षी मुख्य रूप से कांग्रेस है। उत्तराखंड में जनसांख्यिकीय परिवर्तन, धार्मिक प्रतिकृतियों और संरचनाओं का जाल बुनकर सरकारी भूमि पर अतिक्रमण, लैंड जिहाद और बहला-फुसलाकर मतांतरण के प्रकरणों के लिए उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा कि देवभूमि के देवत्व और उसके सांस्कृतिक व आध्यात्मिक स्वरूप से छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

मसूरी रोड स्थित होटल फेयरफील्ड बाय मैरियट में गत दिवस जागरण फोरम में माटी के संदेश के रूप में सजा देवभूमि सत्र मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आक्रामक तेवरों के बूते चुनावी मंच में तब्दील हो गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम वादे और दावे ही नहीं करते, बल्कि काम कर दिखाते हैं। अब हमारा काम बोल रहा है। पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार के सहयोग से राज्य में विकास की महत्वाकांक्षी परियोजनाएं मूर्त रूप ले रही हैं। प्रदेश की ऐसी दो महत्वाकांक्षी बहुद्देश्यीय पेयजल योजनाओं सौंग और जमरानी बांध पर काम शुरू हुआ, जिन्हें लेकर विपक्ष ने केवल राजनीति ही की है। चारधाम आलवेदर रोड समेत ऐसी कई बड़ी परियोजनाएं हैं, जिनका शिलान्यास व लोकार्पण किया गया। दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे शीघ्र खुलने जा रहा है। इससे दिल्ली से देहरादून का सफर ढाई घंटे में पूरा होगा।

लैंड जिहाद के संदर्भ में धामी ने कहा कि राज्य सरकार ने अब तक 10,000 एकड़ से अधिक भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया है। कड़े धर्मांतरण रोधी कानून की आवश्यकता पर बल देते हुए मुख्यमंत्री बोले, जबरन, प्रलोभन या षड्यंत्र के माध्यम से धर्मांतरण को किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। मदरसा बोर्ड भंग किया गया है। प्रदेश में अब तक अवैध 250 मदरसे बंद कराए जा चुके हैं। अब वही मदरसे संचालित होंगे, जिनमें उत्तराखंड बोर्ड का पाठ्यक्रम लागू होगा। अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण में अब जैन, ईसाई व सिख को भी सम्मिलित किया गया है।

उद्घाटन सत्र में उत्तराखंड-संभावनाओं का नया द्वार में उपराष्ट्रपति ने बतौर मुख्य अतिथि विचार रखे। हरित विकास विषय पर मंथन सत्र में पद्मभूषण पर्यावरणविद् डा अनिल प्रकाश जोशी, आइआइटी रुड़की के प्रो रजत अग्रवाल ने हिस्सा लिया। संभावना सत्र में नई शिक्षा नीति पर दून विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो सुरेखा डंगवाल ने विचार रखे। धर्म सत्र में जेन-जी का धर्म विषय पर जूना अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी ने संबोधित किया। देवभूमि सत्रः माटी के संदेश में धामी परिचर्चा में भागीदार बने। मनोरंजन सत्र के अंतर्गत उत्तराखंड बना बालीवुड का नया ठिकाना विषय पर अभिनेता सुनील शेट्टी ने संवाद किया।

देहरादून में मसूरी रोड स्थित होटल फेयरफील्ड वाय मैरियट में शनिवार को दैनिक जागरण की ओर से आयोजित जागरण फोरम के उद्घाटन सत्र में राष्ट्रगान के दौरान मंच पर उपस्थित उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन। साथ में हैं राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (सेनि) एवं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ● जागरण

6 | संपादकीय
जनसत्ता | 19 जनवरी, 2026

कल्पमेधा

जो व्यक्ति उच्च विचारों की सुखद संगति में रहते हैं, वे कभी भी एकाकी नहीं हो सकते।

– फिलिप सिडनी

जीत का परचम

बृहन्मुंबई महानगर पालिका (बीएमसी) चुनाव में भाजपा नीत गठबंधन 'महायुति' ने जीत का परचम लहरा दिया है। साथ ही अविभाजित शिवसेना की लगातार ढाई दशक से चली आ रही सत्ता की विरासत को भी छीन लिया है। भाजपा इस चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, जो उसके बढ़ते जनाधार का संकेत है। वहीं, उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना भले हार गई, मगर वह अपनी कुछ साख बचाने में कामयाब रही है। अब सवाल यह है कि बीएमसी का नया महापौर कौन होगा और महायुति में शामिल किस दल का होगा? इसको लेकर जीत हासिल करने वाले गठबंधन के बीच जोर-आजमाइश भी शुरू हो गई है। हालांकि, एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना को भाजपा से काफी कम सीटों पर जीत हासिल हुई है, मगर वह महापौर की दावेदारी में बनी हुई है। सवालों और सियासत के इस क्रम में यह उम्मीद ज्यादा महत्त्वपूर्ण है कि बीएमसी की नई सत्ता मुंबई के संपूर्ण विकास के नए द्वार खोलेगी।

बीएमसी को देश का सबसे अमीर निगम माना जाता है। इसकी सबसे बड़ी वजह है इसका बजट, जो देश के कई छोटे राज्यों के बजट से कहीं ज्यादा होता है। यही कारण है कि बीएमसी चुनाव की सिर्फ मुंबई में ही नहीं, बल्कि देश भर में चर्चा होती है। पिछले 25 वर्षों से बीएमसी में अविभाजित शिवसेना की सत्ता रही है। मगर, इस बार के चुनाव में भाजपा नीत महायुति ने शिवसेना के इस किले में ऐसी सेंध लगाई कि उसे सत्ता से बेदखल कर दिया। अब सवाल यह है कि बीएमसी का महापौर भाजपा का होगा या फिर एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना का। देखा जाए तो बीएमसी चुनाव में भाजपा ने सबसे ज्यादा सीटें जीती हैं और इस लिहाज से महापौर के लिए उसकी दावेदारी सबसे ऊपर है। मगर शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे ने इस पर अभी तक अपनी पार्टी का रुख स्पष्ट नहीं किया है। अब ऐसी भी खबरें आई हैं कि शिवसेना महापौर का पद पाने के लिए भाजपा पर दबाव बना सकती है।

दरअसल, भाजपा ने भले ही बीएमसी चुनाव में सबसे ज्यादा सीटें जीती हैं, लेकिन आंकड़ों की लिहाज से शिवसेना (शिंदे) के बिना उसका सत्ता में आना मुश्किल है। इस सियासी गणित के जरिए एकनाथ शिंदे दबाव की रणनीति अपना सकते हैं। ये कयास इसलिए भी लगाए जा रहे हैं, क्योंकि शिवसेना (शिंदे) की ओर से पहले भी इस तरह के संकेत दिए जा चुके हैं कि बीएमसी में महापौर उनकी पार्टी से होना चाहिए। हालांकि, सियासी गलियारों में ये अटकलें भी लगाई जा रही हैं कि भाजपा व शिवसेना बीच का रास्ता निकाल सकती हैं। मसलन, दोनों दलों को ढाई-ढाई साल तक महापौर के पद पर काबिज होने का मौका मिले। बहरहाल, उम्मीद यही की जानी चाहिए कि बीएमसी की बागडोर संभालने वाले मुंबई के विकास को रफ्तार देंगे, लोगों के हित उनकी प्राथमिकता में होंगे और बुनियादी समस्याओं को केंद्र में रखकर नई योजनाएं बनाई जाएंगी। क्योंकि, चुनाव में जनता विकास की उम्मीद एवं विश्वास के साथ प्रतिनिधि चुनती है और इस भरोसे को कायम रखने की जिम्मेदारी भी संबंधित दल और प्रतिनिधि की ही होती है।

संकुचित सोच

यह विचित्र विडंबना है कि एक ओर बड़ी संख्या में दंपति बच्चों को गोद लेने के लिए बरसों इंतजार करते हैं, तो दूसरी ओर ऐसे अनाथ बच्चे भी हैं, जो उम्र बढ़ने के साथ गोद लिए जाने से वंचित रह जाते हैं। केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण के आंकड़े बताते हैं कि गोद लेने के मामले में समाज का नजरिया किस कदर संकुचित है। इस समय प्राधिकरण के पास ऐसे कई बच्चे हैं, जिनकी उम्र छह वर्ष या इससे अधिक हो गई है। यह दुखद है कि कई दंपति बच्चा तो गोद लेना चाहते हैं, लेकिन साथ ही उम्र सीमा भी तय कर देते हैं। आज भी लोग नवजात शिशु अथवा पांच साल तक के बच्चों को ही गोद लेना पसंद करते हैं। सवाल है कि संतान सुख पाने के लिए क्या यह नजरिया सही है? उम्र और रंग-रूप के आधार पर बच्चों में भेदभाव करने की प्रवृत्ति को स्वस्थ सोच कहा जा सकता है?

गौरतलब है कि गोद लेने की प्रक्रिया के साथ प्रतीक्षा सूची लंबी होने का खमियाजा बच्चों को ही भुगतना पड़ता है। कई बार दंपति की जटिल शर्तों से उनकी उपेक्षा ही होती है। इस जद्दोजहद के बीच कई बच्चे पांच-छह साल की उम्र पार कर जाते हैं और उनके गोद लिए जाने की उम्मीद धुंधली होती जाती है। अगर निसंतान दंपति अपनी सामाजिक सोच बदलें, तो बड़ी उम्र के बच्चों को भी परिवार मिल सकता है और उनका भविष्य संवर सकता है। वैसे भी बड़े बच्चे समझदार होते हैं और धीरे-धीरे माता-पिता से जुड़ाव के साथ नए परिवार में भी घुल-मिल जाते हैं। अगर दंपति धैर्य रखें और ऐसे बच्चों को प्यार एवं प्रोत्साहन दें, तो यह उनके लिए भी सुखद होगा। निस्संदेह हर बच्चे का अपना घर-परिवार होना चाहिए। इसलिए सामाजिक सोच में बदलाव जरूरी है, ताकि अनाथ बच्चों को भी सामान्य बच्चों की तरह खुशहाल जिंदगी मिल सके और वे अपने सपनों को पूरा कर सकें। परिवार में शामिल होने पर अनाथ बच्चे खुद को मूल्यवान महसूस करते हैं व इससे न केवल उनका आत्मविश्वास बढ़ता है, बल्कि वे समाज में सम्मान के भी हकदार होते हैं।

बढ़ता प्रदूषण, घटता वित्त पोषण

दुनिया के तमाम देश और विकास एजंसियां स्वच्छ वायु को लेकर बड़े-बड़े वादे तो जरूर करती हैं, लेकिन उनका धन उन्हीं परियोजनाओं में जा रहा है, जो हवा को और जहरीला बना रही हैं। यह स्थिति नीतिगत विफलता का परिणाम है।

कुमार सिद्धार्थ

स्वच्छ हवा आज दुनिया की सबसे बुनियादी जरूरतों में शामिल है, लेकिन वैश्विक वित्तीय व्यवस्था इसे अब भी प्राथमिकता नहीं मानती। 'क्लीन एअर फंड' की ताजा वैश्विक रपट ने एक बार फिर इस कड़वी सच्चाई को सामने रखा है कि दुनिया के तमाम देश और विकास एजंसियां स्वच्छ हवा के लिए बड़े-बड़े वादे तो जरूर करती हैं, लेकिन उनका धन उन्हीं परियोजनाओं में जा रहा है, जो हवा को और जहरीला बना रही है। यह स्थिति केवल नीतिगत विफलता नहीं है, बल्कि एक ऐसे वैश्विक अन्याय का उदाहरण है, जिसका सबसे भारी बोझ भारत जैसे विकासशील देशों को उठाना पड़ रहा है। यह बेहद चिंताजनक स्थिति है और इस पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है।

क्लीन एअर फंड' की रपट के मुताबिक वर्ष 2023-24 के दौरान कई देशों की सरकारों और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं ने जीवाश्म ईंधन को लंबे समय तक बनाए रखने वाली परियोजनाओं में वित्तीय राशि अस्सी फीसद बढ़ा कर 9.5 अरब डालर कर दी है। इसके उलट, स्वच्छ हवा और वायु गुणवत्ता सुधार के लिए दी जाने वाली सहायता घट कर 3.7 अरब डालर रह गई, जो कुल वैश्विक विकास सहायता का महज एक फीसद ही है। यह आंकड़ा बताता है कि विकास वित्त और मानव स्वास्थ्य के बीच की खाई कितनी गहरी होती जा रही है। प्रदूषण से निपटने के लिए वित्त पोषण घट रहा है। हर वर्ष होने वाले अंतरराष्ट्रीय शिखर सम्मेलन चाहे वे जलवायु पर हों या स्वास्थ्य पर, ये स्वच्छ हवा को मानव अधिकार के रूप में स्वीकार करते हैं। मगर जब बजट आबंटन की बात आती है, तो वही सरकारें और संस्थाएं पीछे हट जाती हैं।

ऐसा लगता है कि वैश्विक निर्णय लेने वाली संस्थाएं प्रदूषण से होने वाली मौतों और बीमारियों की वास्तविक कीमत को समझने के बजाय आर्थिक और कारोबारी हितों को अधिक महत्त्व दे रही हैं। इससे कई देशों के सामने जोखिम लगातार बढ़ रहा है। स्थिति तब और गंभीर हो जाती है जब दुनिया की सबसे बड़ी विकास एजंसी 'यूएसएड' के बंद होने और विश्व बैंक पर जीवाश्म ईंधन ऋण बढ़ाने के दबाव जैसी चर्चा सामने आती हैं। इन फैसलों ने स्वच्छ हवा के लिए चल रहे वैश्विक प्रयासों की रीढ़ कमजोर कर दी है। 'क्लीन एअर फंड' की मुख्य कार्यकारी जेन बर्स्टन की चेतावनी इस संदर्भ में बेहद अहम है अगर दिशा नहीं बदली गई, तो आने वाले वर्षों में करोड़ों और लोग जहरीली हवा के कारण जान गंवाएंगे।

गौरतलब है कि आज वायु प्रदूषण दुनिया भर में हर साल लगभग 57 लाख लोगों की जान ले रहा है। यह संख्या वर्ष 2040 तक 62 लाख तक पहुंच सकती है। यह कोई संभावित खतरा नहीं, बल्कि चलती-फिरती महामारी है, जो चुपचाप समाज के सबसे कमजोर तबकों को निगल रही है। यह संकट सिर्फ स्वास्थ्य से जुड़ा नहीं है। यह बताता है कि वैश्विक राजनीति में किसकी जिंदगी की कीमत क्या है। लिहाजा अब इसे समझने और सचेत होने की जरूरत है। वैश्विक रपट यह भी दिखाती है कि स्वच्छ हवा के लिए उपलब्ध सीमित वित्तीय अनुदान का वितरण बेहद असमान है। वर्ष 2023 में फिलीपींस, बांग्लादेश और चीन को वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए 65 फीसद बाहर से सहायता राशि मिली, जबकि उप-सहारा अफ्रीका के लिए सहायता

राशि 91 फीसद घट कर केवल 1.18 करोड़ डालर रह गई। यानी जिन इलाकों में स्वास्थ्य ढांचा सबसे कमजोर है, वहीं मदद सबसे कम पहुंच रही है। इस मामले में बड़े देश किस तरह लापरवाही बरत रहे हैं, इसे समझा जा सकता है। प्रदूषण से लड़ने में गरीब देश अकेले पड़ते जा रहे हैं। भारत इस

> **भारत जैसे देश के लिए वायु प्रदूषण केवल पर्यावरणीय समस्या नहीं है। यह गरीबी, असमानता और सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट से सीधा जुड़ा हुआ मुद्दा है। गरीब बस्तियां, असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर, सड़क किनारे रहने वाले लोग, ये सभी सबसे अधिक प्रदूषण झेलते हैं। अगर वैश्विक वित्तीय सहायता जीवाश्म ईंधन आधारित परियोजनाओं पर ही केंद्रित रही, तो भारत का स्वच्छ ऊर्जा अभियान और धीमा पड़ेगा। कोयला आधारित बिजली संयंत्र, उद्योग और डीजल आधारित परिवहन न केवल जलवायु संकट को गहराएंगे, बल्कि भारत को एक स्थायी स्वास्थ्य आपदा की ओर भी धकेल देंगे।**

वैश्विक असमानता का सबसे बड़ा उदाहरण है। दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में भारत के शहर लगातार ऊपर बने हुए हैं। दिल्ली, पटना, लखनऊ, कानपुर, धनबाद और गाजियाबाद ये नाम अब केवल शहर नहीं, बल्कि वैश्विक प्रदूषण की चेतावनी बन चुके हैं। सर्दियों के महीनों में उत्तर भारत का बड़ा हिस्सा गैस चैंबर में बदल जाता है। बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों के लिए सांस लेना तक मुश्किल हो जाता है। भारत को स्वच्छ हवा के लिए अंतरराष्ट्रीय सहायता में प्राथमिकता नहीं मिलती। न तो वायु प्रदूषण पर शोध के लिए पर्याप्त सहयोग मिलता है, न ही स्थानीय समाधान विकसित करने के लिए दीर्घकालिक निवेश। जबकि भारत की स्थिति यह है कि यहां वायु प्रदूषण से हर साल करीब 95 अरब डालर की आर्थिक क्षति होती है।

यह नुकसान केवल अस्पतालों के बढ़ते खर्च में नहीं दिखता, बल्कि काम के दिनों की हानि, बच्चों के स्कूल न जा पाने, घटती उत्पादकता और जीवन की गिरती गुणवत्ता के रूप में सामने आता है। यह समस्या इतनी बड़ी है कि आने वाले समय में इसके दुष्परिणाम गंभीर हो सकते हैं। भारत जैसे देश के लिए वायु प्रदूषण केवल पर्यावरणीय समस्या नहीं है। यह गरीबी, असमानता और सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट से सीधा जुड़ा हुआ मुद्दा है। गरीब बस्तियां, असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर, सड़क किनारे रहने वाले लोग, ये सभी सबसे ज्यादा प्रदूषण झेलते हैं। मगर दुखद यह कि निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में उनकी आवाज सबसे कम सुनी जाती है। अगर वैश्विक वित्तीय सहायता जीवाश्म ईंधन आधारित परियोजनाओं पर ही केंद्रित रही, तो भारत का स्वच्छ ऊर्जा अभियान धीमा पड़ेगा। कोयला आधारित बिजली संयंत्र, डीजल आधारित परिवहन और प्रदूषण फैलाते उद्योग न केवल जलवायु संकट को गहराएंगे, बल्कि भारत को एक स्थायी स्वास्थ्य आपदा की ओर भी धकेल देंगे। यह भी समझना जरूरी है कि वायु प्रदूषण किसी एक देश तक सीमित नहीं रहता। यह सीमाओं के पार फैलता है।

दक्षिण एशिया में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल साझा वायु क्षेत्र में सांस लेते हैं। इसलिए वैश्विक वित्त की दिशाहीनता का असर पूरे क्षेत्र पर पड़ता है। यह निराशाजनक है कि स्वच्छ पर्यावरण के पैरोकार देशों को ही चिंता नहीं है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वर्ष 2040 तक मानव जनित वायु प्रदूषण से होने वाली मौतों को आधा करने का लक्ष्य रखा है। गौरतलब है कि जी20 ने भी वायु गुणवत्ता को अपनी प्राथमिकताओं में शामिल किया है। मगर सच्चाई यह है कि वैश्विक राजनीति घोषणाओं में तो तेजी देखी जाती है, लेकिन संसाधन मुहैया कराने की प्रक्रिया बेहद धीमी है। जब तक नीतियों और बजट के बीच यह खाई बनी रहेगी, तब तक कोई भी लक्ष्य कागज से बाहर नहीं आ पाएगा।

'क्लीन एअर फंड' की रपट समाधान का रास्ता भी सुझाती है कि वित्त पोषण को जीवाश्म ईंधन के विस्तार से हटा कर स्वच्छ हवा, सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छ ऊर्जा की ओर मोड़ा जाए। यह केवल तकनीकी बदलाव नहीं, बल्कि मूल्यों का बदलाव है। यह पूरी दुनिया के लिए जरूरी भी है। वायु प्रदूषण कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है। यह राजनीतिक फैसलों, आर्थिक प्राथमिकताओं का अभाव, इच्छाशक्ति की कमी और वैश्विक असमानता का परिणाम है। अगर विकास बैंक और वैश्विक संस्थाएं अब भी अपनी दिशा नहीं बदलतीं, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन और जी20 के लक्ष्य केवल खोखले घोषणापत्र बन कर रह जाएंगे, लेकिन अगर समय रहते दिशा बदली जाए, तो यह लड़ाई सिर्फ प्रदूषण की नहीं रहेगी, बल्कि न्याय, समानता और हर इंसान को स्वच्छ वातावरण में सांस लेने के अधिकार की लड़ाई बन सकती है।

चिंता और चिंतन

दुनिया मेरे आगे

मुनीष भाटिया

मनुष्य का स्वभाव है कि वह भविष्य की अनिश्चितता, बीती हुई गलतियों और वर्तमान की कठिनाइयों को लेकर बार-बार चिंता में डूब जाता है। चिंता एक ऐसी मानसिक अवस्था है, जो न तो समस्या का समाधान करती है और न ही हमें आगे बढ़ने की शक्ति देती है। उलटे, यह हमारे आत्मविश्वास को कमजोर करती है, निर्णय क्षमता को कुंद करती है और मन को भ्रमित कर देती है। व्यर्थ की चिंता में डूबा व्यक्ति अक्सर समस्या को उससे भी बड़ा बना लेता है, जितनी वह वास्तव में होती है। इसके विपरीत चिंतन एक सकारात्मक, रचनात्मक और उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है।

चिंतन का अर्थ है- शांत मन से स्थिति को समझना, तथ्यों का विश्लेषण करना और संभावित समाधानों पर विचार करना। जहां चिंता 'क्या होगा?' के भय से शुरू होती है, वहीं चिंतन 'अब क्या किया जाए?' के उत्तर की खोज करता है। चिंता हमें अतीत और भविष्य में उलझाए रखती है, जबकि चिंतन हमें वर्तमान में टिक कर सही कदम उठाने की दिशा देता है। जब हम चिंतन करते हैं, तो हम समस्या के मूल कारण तक पहुंचते हैं। हम अपनी गलतियों से सीखते हैं, उपलब्ध संसाधनों का सही आकलन करते हैं और एक ठोस योजना बनाते हैं। यह प्रक्रिया हमें निष्कर्ष तक पहुंचाती है। एक ऐसा निष्कर्ष जो केवल विचार नहीं, बल्कि कार्य की स्पष्ट दिशा देता है और जब दिशा स्पष्ट होती है, तो प्रयास भी सटीक होते हैं, जिससे सफलता की संभावना बढ़ जाती है।

सफल व्यक्तियों का जीवन देखें, तो स्पष्ट होता है कि उन्होंने कठिन परिस्थितियों में चिंता नहीं की, बल्कि गहन चिंतन किया। उन्होंने डर के बजाय समझ को चुना, घबराहट के बजाय धैर्य को अपनाया। इसलिए आवश्यक है कि हम भी व्यर्थ की चिंता छोड़ कर सार्थक चिंतन को अपनाएं। क्योंकि चिंता समस्या को जटिल बनाती है, जबकि चिंतन समाधान को सरल करता है और हमें लक्ष्य तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त करता है। जब-जब जीवन में किसी परेशानी की आहट सुनाई दे, तब सबसे पहले हिम्मत और विवेकशीलता के साथ काम लेना चाहिए। परेशानी का आना कोई असामान्य बात नहीं है, यह जीवन की स्वाभाविक प्रक्रिया है। हर व्यक्ति के जीवन में कभी न कभी कठिन परिस्थितियां आती ही हैं। फर्क केवल इतना होता है कि हम उन परिस्थितियों का सामना कैसे करते हैं। यदि पहली प्रतिक्रिया घबराहट या हताशा की हो, तो समस्या स्वतः ही और बड़ी लगने लगती है।

चिंता मन को अस्थिर कर देती है। जब मन डगमगाता है, तब सोचने-समझने की शक्ति कमजोर पड़ जाती है। हताशा हमें यह विश्वास दिलाने लगती है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, जबकि वास्तव में रास्ते हमेशा होते हैं, बस उन्हें देखने के लिए शांत और संतुलित मन चाहिए। घबराहट में लिया गया निर्णय अक्सर गलत दिशा में ले जाता है और परेशानी को सुलझाने के बजाय और उलझा देता है। इसके विपरीत, हिम्मत हमें भीतर से मजबूत बनाती है। हमें यह विश्वास देती है कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, उसका सामना किया जा सकता है। वहीं विवेकशीलता हमें सही और गलत में अंतर करना सिखाती है।

हिम्मत और विवेक का संतुलन ही किसी भी संकट से निकलने का सबसे प्रभावी उपाय है। परेशानी के समय शांत रह कर स्थिति का मूल्यांकन करना, समस्या के कारणों को समझना और एक-एक कदम करके समाधान की ओर बढ़ना ही समझदारी है। जीवन के अनुभव भी यही सिखाते हैं कि कठिनाइयां हमें तोड़ने नहीं, बल्कि मजबूत बनाने आती हैं। इसलिए जब भी किसी परेशानी की आहट सुनाई दे, चिंतित या हताश होने के बजाय धैर्य, साहस और विवेक के साथ उसका सामना करें।

अतीत को इतना मत याद कीजिए कि वह आपको दुखी करने लगे, क्योंकि बीते हुए कल की परछाइयां वर्तमान के उजाले को भी धुंधला कर देती हैं। मनुष्य का स्वभाव है कि वह अपने अतीत की गलतियों, असफलताओं और कड़वे अनुभवों को बार-बार याद करता है। यह स्मृतियां जब सीख देने के बजाय बोझ बन जाती हैं, तब वे चिंता, हताशा और चिंतन के बीच के संतुलन को बिगाड़ देती हैं। अतीत में उलझा मन वर्तमान क्षण को पूरी तरह जी ही नहीं पाता। मन बार-बार यही सोचता है कि जो पहले गलत हुआ, वह फिर न हो जाए। यही भय भविष्य की कल्पनाओं में बदल जाता है और व्यक्ति अनावश्यक रूप से चिंतित रहने लगता है। यह चिंता आत्मविश्वास को कम करती है।

> **जब वर्तमान के हर कदम पर अतीत की असफलताओं का बोझ लदा हो, तो आगे बढ़ना कठिन हो जाता है। इसी चिंता से हताशा जन्म लेती है। व्यक्ति स्वयं को दोषी मानने लगता है, अपने प्रयासों को व्यर्थ समझने लगता है और उसे महसूस होता है कि अब कुछ भी बदलना संभव नहीं है।**

जब वर्तमान के हर कदम पर अतीत की असफलताओं का बोझ लदा हो, तो आगे बढ़ना कठिन हो जाता है। इसी चिंता से हताशा जन्म लेती है। व्यक्ति स्वयं को दोषी मानने लगता है, अपने प्रयासों को व्यर्थ समझने लगता है और उसे लगता है कि अब कुछ भी बदलना संभव नहीं। हताश मन न तो अवसर देख पाता है और न ही समाधान। वह वर्तमान को भी अतीत की तरह निरर्थक मानने लगता है, जबकि सच्चाई यह है कि हर नया दिन एक नई संभावना लेकर आता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि अतीत को पूरी तरह भुला दें। अतीत का सही उपयोग सकारात्मक चिंतन में है। अतीत से सीख लेकर, अनुभवों को मार्गदर्शक बना कर, वर्तमान में बेहतर निर्णय लेना ही विवेकपूर्ण चिंतन है। चिंता और हताशा जहां हमें पीछे खींचती हैं, वहीं संतुलित चिंतन आगे बढ़ने की दिशा देता है।

इसलिए अतीत को सिर्फ स्मृति के रूप में रखें, बोझ के रूप में नहीं। वर्तमान पल अनमोल हैं; यदि इन्हें चिंता और हताशा में गंवा दिया, तो भविष्य भी अतीत बन जाएगा। सीखें, समझें और आगे बढ़ें। यही जीवन का सार है।

हमें लिखें, हमारा पता : edit.jansatta@expressindia.com | chaupal.jansatta@expressindia.com

चौपाल

प्रतिस्पर्धा के जोखिम

वाणिज्यिक कंपनियों को दस मिनट में सामान पहुंचाने का दावा खत्म करने का निर्देश समयोचित कदम है। यह फैसला केवल विज्ञापन नीति में बदलाव भर नहीं, बल्कि उन कर्मियों की कार्यदशा से जुड़े एक बड़े सवाल को सामने लाता है, जो लगातार जोखिम में रहते हैं। एक अनुमान के मुताबिक, भारत में ऐसे कामगारों की संख्या वर्ष 2030 तक 2.3 करोड़ तक पहुंच सकती है। कम समय में सामान पहुंचाने की होड़ ने इस क्षेत्र में अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा को जन्म दिया है। जल्द सामान पहुंचाने के कारण यातायात नियमों की अनदेखी होती है। मानसिक तनाव का सामना भी करना पड़ता है। कई अध्ययनों में सामने आया है कि एक खास समय के भीतर सामान पहुंचाने का दबाव सड़क दुर्घटनाओं की आशंका को कई गुना बढ़ा देता है। आंकड़े बताते हैं कि सड़क हादसों में मारे जाने वालों में बड़ी संख्या दोपहिया चालकों की है, जिनमें सामान पहुंचाने वाले कर्मी भी शामिल हैं। यातायात जाम, पार्किंग की समस्या, आवास परिसरों की सुरक्षा प्रक्रियाएं और ग्राहक की उपलब्धता जैसे कारक तय समयसीमा को अव्यावहारिक बना देते हैं।

– विभूति बुपक्या, दिल्ली

सुरक्षा का सवाल

साइबर अपराधियों का बेलगाम होना चिंता का विषय बन चुका है। कभी लोगों को लालच देकर ठगी का शिकार बनाया जाता था, लेकिन आज भय फैला कर लूटा जा रहा है। 'डिजिटल अरेस्ट' जैसे नए-नए हथकंडों ने आम नागरिकों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। हाल ही में एक बुजुर्ग महिला कारोबारी को 'डिजिटल अरेस्ट' का भय दिखा कर सात करोड़ रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। साइबर अपराधी स्वयं को पुलिस, कस्टम, सीबीआइ या नारकोटिक्स अधिकारी बता कर लोगों को गुमराह कर उनसे मोटी रकम वसूल रहे हैं। चिंता की बात यह है कि अब ये अपराधी फर्जी अदालतें लगा कर लोगों को ठगने लगे हैं। तकनीक के दुरुपयोग ने अपराध को और खतरनाक बना दिया है। भय और भ्रम की इस स्थिति में लोग जल्दबाजी में अपने जीवनभर की कमाई गंवा बैठते हैं। ऐसे में लोगों का जागरूक होना भी जरूरी है।

– हिमांशु शेखर, गयाजी

प्रशासनिक लापरवाही

इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित जल आपूर्ति से हो रही बीमारियां और लोगों की मौत की घटनाएं चिंताजनक हैं। यह स्थिति किसी दुर्घटना का परिणाम नहीं, बल्कि प्रशासनिक लापरवाही और आपराधिक उदासीनता का स्पष्ट उदाहरण है। पीड़ितों की संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन समस्या के स्थायी समाधान की दिशा में अपेक्षित गंभीरता दिखाई नहीं दे रही है। यह आशंका और भी भयावह है कि भागीरथपुरा जैसी घटना शहर के किसी भी क्षेत्र में दोहराई जा सकती है। पेयजल और गंदे पानी की लाइनों को बिना उचित दूरी और तकनीकी मानकों के बिछाया गया है। कई स्थानों पर पुरानी और जर्जर पाइपलाइनें हैं, जिनसे रिसाव होकर गंदगी पेयजल में मिल सकती है। नियमित जल परीक्षण की कोई प्रभावी व्यवस्था नहीं है। गंभीर परिणाम सामने आने के बाद ही प्रशासन जागता है। ऐसे में जरूरी है कि पानी टंकियों और आपूर्ति लाइनों की नियमित निगरानी की जाए।

– अरविंद जैन 'बीमा', उज्जैन

संकल्प से सिद्धि

'संकल्प की महत्ता' (दुनिया मेरे आगे, 16 जनवरी) पढ़ा। जीवन में हम सभी बदलाव चाहते हैं। चाहे वह हमारी आदतों में हो, करिअर में हो या हमारे व्यक्तित्व में। मगर अक्सर हम केवल इच्छा और क्रिया के बीच के अंतर को समझ नहीं पाते। सिर्फ यह चाहना कि काश मेरा जीवन बेहतर होता, काफी नहीं है। बदलाव की पहली सीढ़ी है- दृढ़ निश्चय। जब आपकी इच्छा एक संकल्प में बदल जाती है, तब आपके भीतर की ऊर्जा उस लक्ष्य की ओर प्रवाहित होने लगती है। किसी भी बड़े बदलाव के पीछे कोई चमत्कार नहीं, बल्कि निरंतर प्रयास होता है। छोटे-छोटे कदम, जो हर रोज बिना रुके उठाए जाएं, अंततः एक बड़े परिणाम में बदल जाते हैं। जैसे पत्थर पर गिरती पानी की बूंदें अपनी निरंतरता से पत्थर को भी तराश देती हैं।

– प्रसिद्ध यादव फुलवारी, पटना

व्रत त्योहार

23 जनवरी 2026 शुक्रवार बसंत पंचमी
25 जनवरी 2026 रविवार रथ सप्तमी
26 जनवरी 2026 सोमवार भीष्म अष्टमी
29 जनवरी 2026 गुरुवार जया एकादशी

ऋतुराज वसंत में ज्ञान की देवी सरस्वती की साधना

शास्त्री कोसलेन्द्रदास

भारत में वर्ष का आरंभ चैत्र या कार्तिक मास से होता है। वैदिक वचनों से प्रकट होता है कि वर्ष की गणना पूर्णिमा से होती थी और नया वर्ष फाल्गुनी पूर्णिमा के उपरांत चैत्र में आरंभ होता था। वर्ष की प्रथम ऋतु होती थी वसंत। महाभारत के वनपर्व (130/14-16) में वसंत ऋतु में हुए वर्ष के आरंभ का उल्लेख है। अयोध्या में भगवान श्रीराम माता कौशल्या की गोद में वसंत ऋतु में ही चैत्र शुक्ल नवमी को उतरे थे। गीता में परमात्मा श्रीकृष्ण ने वसंत को अपना ऋतु अवतार कहा है। श्रीकृष्ण ने वसंत के लिए एक सुंदर शब्द कहा है – ऋतूनां कुसुमाकरः यानी कुसुमाकर यानी फूलों की खान। माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को वसंत पंचमी या श्रीपंचमी बताकर उस दिन शारदा पूजन का विधान किया है।

छह ऋतुओं में पहली है वसंत

ऋग्वेद के पुरुष-सूक्त (10/90) के 16 श्लोक प्रसिद्ध हैं। इसमें हिरण्यगर्भ को देवों ने एक प्रतीकात्मक यज्ञ के रूप में हवि (आहुति) दी है। इसमें तीन ऋतुएं ही आहुति रूप में हैं। वसंत घृत, ग्रीष्म ईंधन एवं शरद हवि हैं। स्पष्ट है कि वसंत ही छह ऋतुओं में पहली है, जो संवत्सरारंभ के समय रहती है। भविष्योत्तर पुराण में आया है कि फाल्गुन पूर्णिमा यानी होली पर जब पतझड़ समाप्त होता है और वसंत ऋतु का आगमन होता है, तब जो व्यक्ति चंदन-लेप के साथ आम्र-मंजरी खाता है, वह वर्ष भर आनंद से रहता है। ईसा से आठ शती पूर्व के ग्रीक विद्वान हेसिओड का कथन है कि जाड़े के 60 दिनों के उपरांत वसंत का आगमन होता है।

वसंत में रति और कामदेव का पूजन

वसंत प्रेम की ऋतु है। इससे ही शास्त्रों ने दाम्पत्य जीवन में पारस्परिक अनुराग को बनाए रखने और बढ़ाने के लिए वसंत पंचमी पर प्रेम के देवता काम और उनकी प्रिया रति के पूजन करने का शास्त्रीय विधान किया है। मदनरत्न का कथन है कि इस दिन अशोक के वृक्ष में कामदेव और माता रति की पूजा करने से सुखद दाम्पत्य प्राप्त होता है। गीता में श्रीकृष्ण ने स्वयं को धर्म से अवरुद्ध काम कहा है। रत्नाकर भट्ट ने जयसिंह-कल्पद्रुम में वसंत पंचमी तिथि को मांगलिक कार्य, विवाह और यात्रा में शुभ दिन कहा है।

ऋग्वेद में प्रमुख नदी है सरस्वती

सरस्वती देवी और नदी, दोनों हैं। विद्वानों ने सिद्ध करने का प्रयास किया है कि सरस्वती वास्तव में सिंधु नदी ही है। पर यह कथन स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऋग्वेद (10/64/9) में सरस्वती, सरयु और सिंधु नदियों का वर्णन प्रमुख नदियों के रूप में है। प्रो क्षेत्रेशचंद्र चट्टोपाध्याय ने आधुनिक सरस्वती की स्थिति को आरंभिक वैदिक काल में भी ज्यों का त्यों माना है। वामनपुराण (32/1-4) में सरस्वती को एक प्लक्ष (पाकड़) वृक्ष से निकली हुई माना गया है और कुरुक्षेत्र से गुजरती हुई कहा गया है। इसमें सरस्वती नदी को सहस्रों पहाड़ियों को तोड़ती-फोड़ती द्वैत वन में प्रवेश करती हुई दर्शाया गया है। तीर्थराज प्रयाग में तीन नदियां मिलती हैं – गंगा, यमुना एवं सरस्वती। सरस्वती दोनों के बीच अंतर्भूमि में है, जिससे इसको त्रिवेणी की संज्ञा मिली है।

शास्त्रों में सरस्वती की साधना

वेदों से पुराणों तक माता सरस्वती की अद्भुत महिमा है। उन्हें शास्त्रों में वाणी की अधिष्ठात्री, शक्ति तथा संगीत, साहित्य और काव्य की मूल प्रेरणा कहा गया है। वे परमात्मा के मुख से प्रकट होकर मानव को विवेक, विद्या और सौम्यता प्रदान करती हैं। उनका श्वेत, शांत और सत्त्वमय स्वरूप ज्ञान की निर्मलता और कल्याणकारी शक्ति का प्रतीक है। देवीपुराण (अध्याय 45) ने सरस्वती शब्द की व्युत्पत्ति पर कहा है-जो निरंतर प्रवाहित होकर गतिशील रहती है, उसे इस सरणशीलता के कारण सरा कहा गया है। गेय (संगीतात्मक) रूप में उसकी सात धाराएं प्रसिद्ध हैं, जिससे वह सरस्वती कही जाती है।बौद्धों ने भगवान गणेश एवं माता सरस्वती जैसे देव-देवियों को ले लिया है और उनकी स्तुति की है। जैनों ने माता सरस्वती की प्रतिमाओं का निर्माण किया, जिनमें वे हाथ में पुस्तक धारण करती हैं।

तंत्रशास्त्र में महानिर्वाणतंत्र का चतुर्थ अध्याय यह कहकर आरंभ होता है कि देवी दुर्गा परमात्मा की परम प्रकृति हैं। उनके अनेक नाम हैं – काली, भुवनेश्वरी, बगला, भैरवी और छिन्नमस्तका। वे सरस्वती, लक्ष्मी एवं शक्ति हैं। वे भक्तों की कामनापूर्ति तथा राक्षसों के नाश के लिए विभिन्न रूप धारण करती हैं। दुर्गासप्तशती ने चंड-मुंड, रक्तबीज और शुंभ-निशुंभ राक्षसों की वधकर्त्री के रूप में माता सरस्वती को प्रतिष्ठित किया है।

प्रथम ऋतु

जड़ता दूर करने वाली शक्ति

12वीं शती में कुमारदास द्वारा संकलित सदुक्तिकर्णामृत में कवि अपिदेव लिखते हैं-माता सरस्वती सूर्य की भांति जड़ता को दूर करने वाली शक्ति है, तो कहीं असंख्य तारों की आभा के समान चमत्कार रचती हैं। कहीं वे चंद्रमा की ज्योत्स्ना की तरह मृदुल और शीतलता धारण करती हैं, तो कहीं अग्नि की लपट-सी तिरछी और प्रखर लहराती हैं। वे दीये की उजली लौ के समान प्रकाश फैलाती हैं। देवी सरस्वती की ज्योति विजय का प्रतीक है। ऐसी माता शारदा की हम श्रद्धापूर्वक उपासना करते हैं।

अनोखा है सरस्वती का ज्ञान भंडार

उद्भटसागर में बंगाली कवि पूर्णचंद्र ने माता सरस्वती के ज्ञान भंडार की प्रशंसा में लिखा है कि सरस्वती का ज्ञान-भंडार अनुपम है। यह ऐसा है, जो व्यय करने पर वृद्धि को प्राप्त होता जाता है और संग्रह करने पर घटता है। तात्पर्य है, ज्ञान जितना अधिक वितरित किए जाए, उतना ही बढ़ता है।

क्या परिस्थितियों की गुलाम है जिंदगी

रोहित कौशिक

जीवन की परिस्थितियां भविष्य की दिशा तय करती हैं। इसलिए जीवन में परिस्थितियों का महत्त्वपूर्ण योगदान होता है। जीवन इस बात पर निर्भर करता है कि परिस्थिति क्या रही है। स्थिति और परिस्थिति में एक महीन अंतर होता है। स्थिति किसी व्यक्ति या वस्तु की तत्काल दशा होती है, लेकिन परिस्थिति में वह बाहरी परिवेश भी शामिल हो जाता है जो किसी स्थिति को जन्म देता है। कई बार हम कुछ परिस्थितियों के कारण अपनी जिंदगी में उतना बेहतर नहीं कर पाते, जितना वास्तव में करना चाहिए था। जिंदगी में ऐसे अनेक उदाहरण दिखाई देते हैं कि कई व्यक्तियों को बेहतर परिस्थितियां मिलीं, जिसके कारण वे अपने जीवन में निरंतर सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ते चले गए।

दूसरी तरफ अनेक व्यक्तियों को बेहतर परिस्थितियां नहीं मिल पाईं जिसकी वजह से वे अपनी जिंदगी में उतनी सफलता प्राप्त नहीं कर पाए। बेहतर परिस्थितियां न मिलने के कारण अनेक लोग तो बेहद निराश हो जाते हैं और वे अवसाद की स्थिति तक पहुंच जाते हैं। सच्चाई तो यह है कि बेहतर परिस्थितियां मिलना हमारे हाथ में नहीं है। बहुत-कुछ घर-परिवार की स्थिति पर भी निर्भर करता है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि घर-परिवार की स्थिति ही सफलता का मुख्य कारण होती है। अनेक लोगों ने अपने जीवन में विपरीत परिस्थितियों के बावजूद सफलता पाई है।

दूसरी तरफ कई लोग अनुकूल या अच्छी परिस्थितियों के बावजूद सफलता प्राप्त नहीं कर पाए। इसलिए अच्छी परिस्थितियां हमारी सफलता में सहायक तो सिद्ध हो सकती हैं, लेकिन सफलता की गांरटी नहीं दे सकतीं। सफलता किसी भी इंसान की व्यक्तिगत क्षमताओं और इच्छा शक्ति पर भी निर्भर करती है। अगर सफलता परिस्थितियों की गुलाम होती तो ऐसे सभी लोग सफलता की नई-नई कहानियां लिखते, जिनके घर-परिवार की स्थिति हमेशा बहुत अच्छी रही।

सच्चाई तो यह है कि अनेक लोग घर-परिवार की स्थिति ठीक होने के बावजूद प्रगति नहीं कर पाते हैं। कभी-कभी तो हमारे घर-परिवार की अच्छी स्थिति संघर्ष करने का जज्बा खत्म कर देती हैं। जब अच्छी परिस्थितियां हमारी जिंदगी को आरामदेह बना देती हैं तो हम परिश्रम करने से बचने लगते हैं। इस तरह देखा जाए तो कभी-कभी बहुत अच्छी परिस्थितियां हमें आगे नहीं बढ़ने देती और हमारी प्रगति में बाधक सिद्ध होती हैं। हालांकि हर बार ऐसा नहीं होता। अगर हमारे अंदर काम करने का जज्बा और आगे बढ़ने की इच्छा है तो हम अपने घर-परिवार की अच्छी स्थिति का उपयोग अपनी स्थिति को और बेहतर बनाने में कर सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि कितने लोग ऐसा कर पाते हैं? हमारे घर-परिवार की बेहतर स्थिति हमें एक सुरक्षा कवच प्रदान करती है। यह हम पर निर्भर करता है कि हम इस सुरक्षा कवच का इस्तेमाल किस तरह करते हैं। यह सुरक्षा कवच हमें जिंदगी में पीछे भी ले जा सकता है और आगे भी।

बेहतर तो यह है कि हम इस सुरक्षा कवच का इस्तेमाल अपनी प्रगति के लिए करें। जब किसी भी तरह का सुरक्षा कवच प्राप्त हो जाता है तो मानसिक रूप से शांत रहकर आगे बढ़ने के लिए किए गए प्रयासों की तीव्रता बढ़ा सकते हैं। यानी यदि घर-परिवार की स्थिति अच्छी है तो हम अनेक चिंताओं से मुक्त होकर अपने उद्देश्य पर बेहतर तरीके से ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। इसके विपरीत यदि हमारे घर-परिवार की स्थिति ठीक नहीं है तो अनेक तरह की चिंताओं से घिरे रहेंगे।

जीवन जगत

मौनी अमावस्या

वाराणसी में मौनी अमावस्या के अवसर पर रविवार को दशाश्वमेध घाट पर श्रद्धालु पवित्र स्नान करने के लिए एकत्रित हुए।

जीवन का आधार स्वयं का आत्मसम्मान

अम्बिका कुशवाहा 'अम्बी'

दुनिया डिजिटल हो गई और साथ में रिश्ते भी ऐसे ही होते जा रहे हैं। आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में हर कोई सफलता की सीढ़ियां चढ़ने, पैसा कमाने, अच्छे रिश्ते बनाने और खुशी की तलाश में लगा रहता है। सकून की तलाश हर किसी को है,लेकिन बहुत कम लोग आत्मसम्मान से जी रहे हैं। आत्मसम्मान वह मजबूत नींव है जिस पर हमारी पूरी जिंदगी की इमारत खड़ी होती है।

अगर यह नींव मजबूत है, तो जीवन के किसी भी तूफान का सामना हंसते हुए किया जा सकता है। लेकिन अगर यह कमजोर पड़ जाए, तो छोटी-छोटी आलोचनाएं, विफलताएं या अपमान अंदर से तोड़ देते हैं। लोग खुद पर भरोसा खो बैठते हैं और जिंदगी एक बोझ लगने लगती है।

आज बहुत सी ऐसी घटनाएं हो रही है, लोग रिश्तों के नाम पर आत्मसम्मान गिरवी रख देते हैं। जब किसी पर अटूट विश्वास करते है, तो उसकी गलतियां जानते हुए भी नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन समय बीतता जाता है और सम्मान धीरे-धीरे खत्म होता जाता है। वह व्यक्ति सिर्फ रिश्तों को आजमाता है।

समाज में ऐसा भी है कि जब कोई आत्मसम्मान के लिए खड़ा होता है, तो लोग उसे अहंकारी या घमंडी के शब्दों से संबोधित करते हैं। जबकि आत्मसम्मान का मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है। यह तो बस खुद की कीमत जानना है। यह जानना है कि किसी भी इंसान की भावनाएं होती हैं, सपने होते हैं, सीमाएं होती हैं, और उसे सम्मान का हक होता है। जब लोग "ना" कहना सीखते हैं, ना गलत व्यवहार के खिलाफ, ना अनुचित मांगों के सामने, तब उनका आत्मसम्मान मजबूत होता है। इसके लिए आवाज उठाना भी आसान नहीं होता है।

अब बच्चों को भी आत्मसम्मान की यह शिक्षा बचपन से ही देनी जरूरी है। आजकल स्कूलों में खिंचाई करना बहुत आम है। अगर बच्चा चुप रहता है, तो यह बढ़ जाता है और डर से उसका आत्मविश्वास खत्म होने लगता है। उन्हें सिखाएं कि अपनी बात निडरता से रखें, जरूरत पड़े तो जवाब दो, लेकिन हिंसा का रास्ता मत अपनाओ। घर में भी माता-पिता को ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे की हर बात को गलत ठहराना, हमेशा डांटना-फटकारना उसका आत्मसम्मान कम करता है। उल्टा, उसकी छोटी-छोटी सफलताओं की तारीफ करनी चाहिए, उसकी भावनाओं को समझना और सम्मान देना चाहिए। यही उसे बड़ा होकर मजबूत इंसान बनाएगा, जो गलत के खिलाफ खड़ा हो सकेगा।

पेशेवर दुनिया में भी आत्मसम्मान बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। जब कर्मी अपनी कीमत जानते हैं, अपनी मेहनत और योग्यता की कद्र मांगते हैं, तब सफलता खुद पास आती है। कई बार इसके लिए नया रास्ता चुनना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन वह संघर्ष ऊंचाइयों तक ले जाता है। कभी-कभी खुद ही अपना सम्मान गिराते हैं।

आत्मसम्मान को मजबूत बनाने के लिए अच्छाइयों को याद करना चाहिए और कमियों को नजरअंदाज। कोई नया कौशल सीखें, किताबें पढ़ें, योग-ध्यान करें। जब कोई गलत कहे, तो शांतिपूर्वक बात रखें। सीमाएं बनाएं कि क्या सहन करेंगे, क्या नहीं।

और सबसे जरूरी, माफ करना भी सीखें, क्योंकि गलतियां इंसान से ही होती हैं। आत्मसम्मान व्यक्ति का अस्तित्व होता है। इसे वह स्वयं बनाता है, इसे कोई छीन नहीं सकता, जब तक कि उसमें स्वाभिमान है। इसलिए इसे स्वयं की आत्मा में जिंदा रखना होता है।

जीवन है जीने का नाम

समाज में ऐसा भी है कि जब कोई आत्मसम्मान के लिए खड़ा होता है, तो लोग उसे अहंकारी या घमंडी के शब्दों से संबोधित करते हैं। जबकि आत्मसम्मान का मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है। यह तो बस खुद की कीमत जानना है। यह जानना है कि किसी भी इंसान की भावनाएं होती हैं, सपने होते हैं, सीमाएं होती हैं, और उसे सम्मान का हक होता है।

निष्काम कर्म से लक्ष्य की प्राप्ति के संदेश

जनसत्ता धर्मदीक्षा

महर्षि वेदव्यास रचित महाभारत महाकाव्य का हिस्सा रहे श्रीमद्भगवद् गीता के जीवन को लेकर सारगर्भित संदेश उसकी रचना के समय से ही लोगों को उद्वेलित करते रहे हैं। युद्धभूमि कुरुक्षेत्र में भगवान श्रीकृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया 'निष्काम कर्मज्ञान' गीता के रूप में संकलित है। गीता का सार है कि 'कर्म करो, फल की चिंता मत करो', अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करो, मन को शांत रखो, स्वयं में विश्वास रखो, और सभी परिस्थितियों में समभाव (राग-द्वेष से रहित) रखो, क्योंकि यही जीवन का सच्चा मार्ग व परम आनंद की प्राप्ति का साधन है।

निष्काम कर्म का आशय यह है कि व्यक्ति को अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा से निभाना चाहिए, परिणामों की चिंता नहीं करनी चाहिए। आसक्ति के साथ किया गया कर्म दुख का कारण बनता है। गीता में स्पष्ट संदेश है कि हर व्यक्ति को अपने धर्म और कर्तव्य (स्वधर्म) का पालन करना चाहिए, भले ही वह कठिन लगे, क्योंकि यही समाज और व्यक्ति के उत्थान का मार्ग है। मन चंचल होता है, उसका वेग बहुत तेज है, इसलिए मन को निष्काम कर्म की दिशा में लगाए रखना साधना की तरह है, जो अभ्यास से संभव है। गीता का एक और प्रमुख संदेश है समभाव। इसका तात्पर्य है कि सुख-दुख, लाभ-हानि, यश-अपयश, सभी स्थितियों में समान रहना। राग (पसंद) और द्वेष (नापसंद) से बचना ही सच्चा ज्ञान है। यह स्थितप्रज्ञ की अवस्था है। गीता में आध्यात्मिक ज्ञान का संदेश है, जिसमें मानव की चेतना के स्तर का जागृत कर परम आनंद का मार्ग प्रशस्त करता है।

असल में, गीता एक उद्देश्यपूर्ण, कर्तव्यनिष्ठ और आनंदमय जीवन जीने की कला सिखाती है , जो अंततः व्यक्ति को आत्म-साक्षात्कार की ओर ले जाता है। गीता में जीवन के पुरुषार्थ को अपनाने का संदेश है। आधुनिक समय में भी गीता के सार संदेश सभी मानव के लिए जीवनोपयोगी और समीचीन है। जब हम गीता का अध्ययन करते हैं, तो वह हमें खुद को जानने, समझने और पहचानने का मार्ग दिखाती है।

जीवन की जटिलताओं के बीच अपने लिए लक्ष्य निश्चित करने और उसकी प्राप्ति के लिए निष्काम कर्म करने का संदेश गीता देती है। चूंकि यह संसार और शरीर परिवर्तनशील हैं। हमें नश्वर वस्तुओं से आसक्ति छोड़कर शाश्वत आनंद की ओर बढ़ना चाहिए। श्रीकृष्ण को कर्मयोगी कहा गया है। योग भाव से कर्म करना चाहिए, जिसमें आसक्ति नहीं हो। श्रील प्रभुपाद ने भी गीता की व्याख्या करते हुए उसमें उद्धृत ज्ञान के यथारूप पर जोर दिया है। यथारूप व्याख्या में भगवान कृष्ण के मूल शब्दों और इरादों को बिना किसी मिलावट या मनमानी व्याख्या के प्रस्तुत करने पर जोर था, जैसा कि वे सीधे अर्जुन को बता रहे थे।

आनंद जीव का मूल स्वभाव है, इसलिए जब हम आनंदमय होकर कर्म करते हैं, इसमें शाश्वत आ''ाद की अनुभूति होती है। जब हम आसक्त होकर या किसी निहित फल की इच्छा लेकर या मन के विरुद्ध मजबूरी में कर्म करते हैं, उसमें हम आनंद का अनुभव नहीं करते हैं। प्रत्येक विवेकी मनुष्य में दिव्य भगवदीय सामर्थ्य विद्यमान है। आनंद का अनुभव करते हुए कर्म करने में सुख की अनुभूति होती है। आज के समाज में करोड़ों लोग अंधी होड़ में बिना स्पष्ट लक्ष्य के कर्म किए जा रहे हैं, इसके कारण न उन्हें आत्मानंद मिलता है और न सुख मिलता है। हमें यह समझना होगा कि प्रसन्नता पदार्थ सापेक्ष नहीं, अपितु चिंतन एवं विचार सापेक्ष है। श्रीमद्भगवद्गीता में योगेश्वर श्रीकृष्ण कहते हैं, 'देहिनोऽस्मिन्यथा देहे कौमारं यौवनं जरा' अर्थात इस देह की भी तीन अवस्थाएं हैं-बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था। इसका आशय यह है कि शरीर में भी नित्य परिवर्तन हो रहा है। हमारा मन और बुद्धि भी कहां स्थिर हैं। मन कभी प्रसन्न रहता है और कभी खिन्न। ठीक यही दशा बुद्धि की भी है। जानकारी में वृद्धि होने के साथ बुद्धि का भी विस्तार होता जाता है। गीता का मुख्य संदेश कर्मयोग है, अर्थात कर्तव्यपथ पर चलते हुए निष्काम भाव से कार्य करना। भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि कर्म ही जीवन का धर्म है और उससे कभी भी भागना नहीं चाहिए। गीता जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझने में मदद करती है और विपरीत परिस्थितियों में धैर्य और संतुलन बनाए रखने की सीख देती है।

गीता में अध्यात्म को स्वभाव की यात्रा कहा गया है अर्थात स्वरूप सिद्धि के लिए अथवा जो हम हैं, उसके ज्ञान व आत्मबोध के लिए हमें आध्यात्मिक जीवन शैली का अनुगमन और अनुशीलन करना चाहिए। सुख के मूल स्रोत हमारे भीतर ही विद्यमान हैं। गीता का प्रभाव न केवल हिंदू धर्म मानने वालों पर बल्कि विश्व के अन्य धर्मों और दर्शनों पर भी पड़ा है। महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद और अन्य महान व्यक्तियों ने गीता के सिद्धांतों से प्रेरणा लेकर अपने जीवन को सफल बनाया। आज के युग में भी गीता का संदेश अत्यंत प्रासंगिक है। हमें अपने कर्तव्य का पालन करते हुए निष्काम भाव से कार्य करना चाहिए। हमें लालच, मोह और क्रोध से दूर रहना चाहिए और सत्य, अहिंसा और धर्म का पालन करना चाहिए।

गीता सार

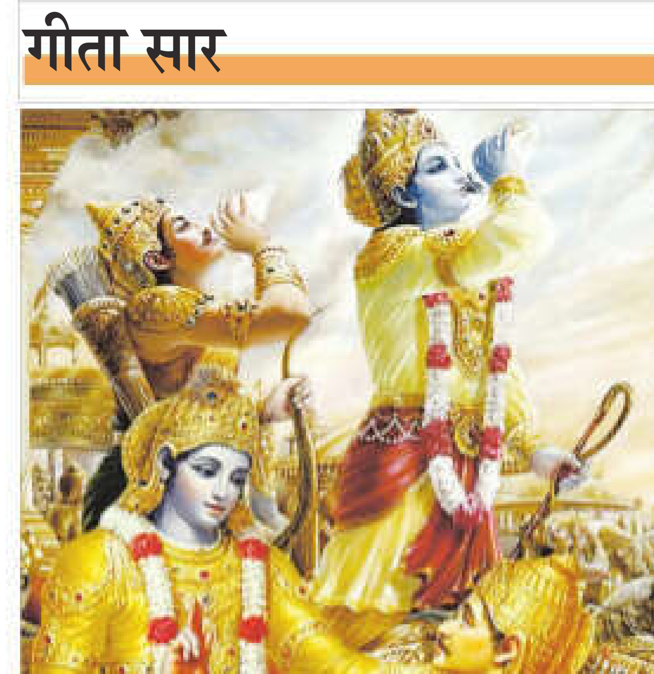

खबर कोना

यूपी के लाभार्थियों के खाते में 2000 करोड़ रुपए का हस्तांतरण

नई दिल्ली, 18 जनवरी (ब्यूरो)।

प्रधानमंत्री आवास योजना-(शहरी 2.0) के तहत उत्तर प्रदेश के दो लाख से अधिक लाभार्थियों के बैंक खातों में रविवार को 2,000 करोड़ रुपए से अधिक की अनुदान राशि का सीधे हस्तांतरण किया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की मौजूदगी में लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम को केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आभासी माध्यम से संबोधित किया। खट्टर ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हर ऐसे बेघर परिवार को एक घर मिलेगा, जिसके सिर पर छत नहीं है। जब तक लक्ष्य पूरा नहीं हो जाता है रुकेंगे नहीं। उन्होंने आश्वस्त किया, यह जरूरत नहीं है कि मकानों की संख्या कितनी होगी।

अगरतला में रविवार को धान की कटाई के बाद उसे फटकते किसान।

भारत से वाहन निर्यात 24 फीसद बढ़ा : सियाम

नई दिल्ली, 18 जनवरी (भाषा) ।

वाहन विनिर्माताओं के संगठन सियाम के ताजा आंकड़ों के अनुसार विदेशी बाजारों में कारों, दुपहिया वाहनों और वाणिज्यिक वाहनों की मजबूत मांग के कारण 2025 में भारत से वाहन निर्यात 24 फीसद बढ़ा। पिछले साल भारत से कुल निर्यात 24.1 फीसद बढ़कर 63,25,211 इकाई हो गया, जबकि 2024 में यह 50,98,474 इकाई था।

बम की धमकी मिलने के बाद लखनऊ में सुरक्षित उतारा गया विमान

नई दिल्ली, 18 जनवरी (ब्यूरो)।

इंडिगो एअरलाइन के दिल्ली-बागडोगरा उड़ान (6 इ-6650) में बम की धमकी मिलने के बाद आपात स्थिति में इसे लखनऊ हवाई अड्डे पर उतारा गया। सुरक्षा के लिहाज से सभी यात्रियों को उतारने के बाद विमान की सघन जांच की गई। करीब साढ़े चार घंटे की जांच के बाद वैकल्पिक उड़ान से यात्रियों को बागडोगरा के लिए रवाना किया गया। पुलिस अधिकारी ने बताया, उड़ान के शौचालय में एक टिशू पेपर पर धमकी दी गई थी। इस पर लिखा था विमान में बम है। इस सूचना के बाद विमान को आपात स्थिति में लखनऊ में उतारने के बाद सघन जांच की गई।

स्वदेशी जागरण मंच ने सिगरेट की तस्करी बढ़ने पर चेतावनी दी

नई दिल्ली, 18 जनवरी (भाषा)।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संबद्ध स्वदेशी जागरण मंच (एसजेएम) ने चेतावनी दी कि विदेशी सिगरेटों की बढ़ती तस्करी सरकारी राजस्व और सार्वजनिक स्वास्थ्य, दोनों को गंभीर रूप से प्रभावित कर रही है। एसजेएम के राष्ट्रीय सह-संयोजक अश्वनी महाजन ने समाचार एजंसी को बताया कि हानिकारक वस्तुओं पर उच्च करों का ऐतिहासिक नतीजा कालाबाजारी बढ़ने के रूप में सामने आया है। उन्होंने कहा कि वैध उत्पादों की कीमतें बहुत अधिक बढ़ जाने के कारण पैदा हुए अंतर को तस्करी के उत्पादों से भरा जा रहा है।

विश्व आर्थिक मंच की बैठक आज से

भारत वैश्विक दिग्गजों के सामने दमदार उपस्थिति के लिए तैयार

दावोस, 18 जनवरी (भाषा)

विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) की वार्षिक बैठक में भारत एक दमदार प्रतिनिधित्व के लिए तैयार है। सोमवार से शुरू होने वाले पांच दिवसीय इस आयोजन में दुनिया भर के दिग्गज एक चुनौतीपूर्ण दुनिया में 'संवाद की भावना' विषय पर चर्चा करेंगे।

सरकार, व्यापार, शिक्षा, बहुपक्षीय निकायों, नागरिक समाज और श्रम संघों के 3,000 से अधिक वैश्विक नेताओं के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सबसे बड़े आकर्षण होंगे। ट्रंप अपने मंत्रिमंडल के पांच सदस्यों के साथ आ रहे हैं। भारत से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के अलावा कम से कम चार केंद्रीय मंत्रियों अश्विनी वैष्णव, शिवराज सिंह चौहान, प्रल्हाद जोशी और के राम मोहन नायडू के साथ ही छह मुख्यमंत्रियों और देश के 100 से अधिक शीर्ष मुख्य कार्यपालक अधिकारियों (सीईओ) के शामिल होने की उम्मीद है।

उधर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस रविवार को ज्यूरिख पहुंचे, जहां वह दावोस में होने वाली विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक में भाग लेंगे। बैठक में शामिल होने वाले अन्य मुख्यमंत्रियों में आंध्र प्रदेश के एन चंद्रबाबू नायडू, असम के हिमंत बिस्व सरमा, मध्य प्रदेश के मोहन यादव, तेलंगाना के ए रेवंत रेड्डी और झारखंड के हेमंत सोरेन शामिल हैं। जहां रेड्डी कांग्रेस पार्टी से हैं, सोरेन कांग्रेस की सहयोगी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा से और नायडू भाजपा की सहयोगी तेलुगु देशम पार्टी से हैं, वहीं अन्य तीन मुख्यमंत्री भाजपा से हैं। कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार (कांग्रेस) के भी वहां रहने की उम्मीद है। केंद्रीय मंत्रियों में नायडू तेदेपा से हैं, जबकि अन्य चार भाजपा से हैं। इसके अलावा, गुजरात के उपमुख्यमंत्री हर्ष रमेशभाई संघवी (भाजपा) और उत्तर प्रदेश का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी दुनिया भर के अमीर और शक्तिशाली लोगों के इस वार्षिक जमावड़े के लिए दावोस की यात्रा करेंगे। वैश्विक नेताओं में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने वरिष्ठ सहयोगियों वित्त मंत्री स्काट बेसेन्ट, वाणिज्य मंत्री हावर्ड लुटनिक और ऊर्जा मंत्री क्रिस राइट के साथ वहां पहुंच सकते हैं। इस वैश्विक शिखर सम्मेलन में लगभग 130 देशों के करीब 400 से अधिक नेता शामिल होंगे, जिनमें 64 राष्ट्राध्यक्ष भी होंगे।

भारतीय नेताओं के शिखर सम्मेलन के दौरान कई समूह चर्चाओं में भाग लेने की उम्मीद है, जिसमें 'क्या भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है' विषय पर एक चर्चा भी शामिल है। इसके अलावा वे द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति जुबिन इरानी भी 'अलायंस फार ग्लोबल गुडः जेंडर इक्विटी एंड इक्वालिटी' की संस्थापक और चेयरपर्सन के रूप में वहां मौजूद रहेंगी, जिसकी स्थापना कुछ साल पहले दावोस में ही हुई थी। इसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी, टाटा समूह के एन चंद्रशेखरन शामिल होंगे।

भारत के साथ साझेदारी करें और भविष्य से जुड़ें

दावोस में जिस जगह कभी प्रतिष्ठित 'पियानो बार' हुआ करता था, वहां से अब 'टीम इंडिया' का एक स्पष्ट संदेश इस बर्फीले रिसार्ट शहर की गलियों में गूंज रहा है कि 'भारत के साथ साझेदारी करें और भविष्य से जुड़ें'। शीर्ष उद्योग मंडल सीआइआइ ने भी अपने पवेलियन में कुछ ऐसा ही संदेश दिया है: 'भारतीय उद्योग जगत के भागीदार बनें और एक भरोसेमंद भविष्य का हिस्सा बनें'।

ट्रंप से लेकर जेलेंस्की तक दिग्गजों के लिए दावोस की किलेबंदी

दावोस, 18 जनवरी (भाषा) ।

विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) की सोमवार से शुरू हो रही वार्षिक बैठक के पांच दिवसीय आयोजन के लिए दुनिया भर के दिग्गज यहां जुटना शुरू हो रहे हैं।

इसके साथ ही 5,000 से अधिक सशस्त्र बल के जवान, रणनीतिक स्थानों पर तैनात स्नाइपर, एआइ संचालित ड्रोन और विशेष उपकरण इस शहर की सुरक्षा के लिए तैनात हैं। कार्यक्रम में शामिल होने वाले अति विशिष्ट लोगों को देखते हुए सभी प्रवेश द्वारों पर और अचानक जांच आम है। सुरक्षा एजंसियों की चिंताओं को बढ़ाते हुए कुछ विरोध प्रदर्शनों की पहले से ही योजना बनाई गई है, जिनमें पूंजीवाद विरोधी और पर्यावरण कार्यकर्ता शामिल हैं।

अप्रैल से यूपीआइ से निकाल सकेंगे पीएफ का पैसा

नई दिल्ली, 18 जनवरी (एजंसी)।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) अप्रैल 2026 तक अपने आठ करोड़ सदस्यों को यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआइ) के माध्यम से पीएफ निकालने की सुविधा देगा।

सदस्य यूपीआइ पिन का उपयोग करके पात्र राशि सीधे बैंक खाते में हस्तांतरण कर सकेंगे, जबकि न्यूनतम 25 फीसद हिस्सा ब्याज के लिए सुरक्षित रहेगा। ताकि सदस्यों को वर्तमान 8.25 फीसद ब्याज दर और चक्रवृद्धि ब्याज का लाभ मिलता रहे। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने यह जानकारी दी। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बताया कि आंतरिक चर्चाओं के बाद प्रारंभिक निकासी की अधिकतम सीमा 25,000 रुपए प्रति लेनदेन तय करने की दिशा में निर्णय लिया जा रहा है।

अधिकारी ने बताया कि पूरी प्रणाली के विकास पर काम चल रहा है। इस प्रणाली के विकास में तीन प्रणाली शामिल हैं। ईपीएफओ, सी-डीएसी (उन्नत कंप्यूटिंग विकास केंद्र) और एनपीसीआई (भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम) और भुगतान समन्वय के लिए भारतीय स्टेट बैंक भी इसमें शामिल है। शुरुआत में निकासी की सुविधा भीम ऐप के माध्यम से दी जाएगी, जो सीधे यूपीआइ से जुड़े बैंक खाते में राशि जमा कर देगी। अधिकारी ने बताया कि ईपीएफओ के सभी सदस्य भीम ऐप के माध्यम से यूपीआइ सुविधा का लाभ उठा सकेंगे और यूपीआइ लेनदेन के लिए मौजूदा सुरक्षा उपाय यथावत लागू रहेंगे। यह सुविधा विशेष रूप से ईपीएफओ के अंतर्गत आने वाले उन श्रमिक-श्रमिकों के लिए सहायक होगी जो अन्यथा आनलाइन पोर्टल के माध्यम से निकासी प्रक्रिया का लाभ नहीं उठा पाते। अधिकारी ने बताया कि शुरुआत में प्रति लेनदेन 25,000 रुपए की सीमा प्रस्तावित की गई है।

एफपीआइ ने जनवरी में शेयरों से 22,530 करोड़ निकाले

नई दिल्ली, 18 जनवरी (भाषा)।

अमेरिकी बांड प्रतिफल में बढ़ोतरी और डालर की मजबूती के बीच विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआइ) ने इस महीने अब तक भारतीय शेयरों से 22,530 करोड़ रुपए से अधिक निकाले हैं। यह निकासी 2025 में दर्ज की गई 1.66 लाख करोड़ रुपए की बिकवाली के बाद हुई। ऐसा मुद्रा की अस्थिरता, वैश्विक व्यापार तनाव और अमेरिकी शुल्क में बढ़ोतरी की आशंका तथा बाजार के ऊंचे मूल्यांकन के कारण हुआ।

एफपीआइ के लगातार बिकवाली के दबाव ने 2025 के दौरान डालर के मुकाबले रुपए के मूल्य में लगभग पांच प्रतिशत की गिरावट लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एनएसडीएल के आंकड़ों के अनुसार एफपीआइ ने एक से 16 जनवरी के बीच भारतीय इक्विटी से 22,530 करोड़ रुपए निकाले। बाजार विशेषज्ञों ने इस निकासी के लिए वैश्विक और घरेलू कारकों को जिम्मेदार ठहराया है। सेंट्रिसिटी वेल्थटेक के इक्विटी प्रमुख और संस्थापक पार्टनर सचिन जसुजा ने कहा कि बढ़ते अमेरिकी बांड प्रतिफल और मजबूत डालर ने विकसित बाजारों में जोखिम समायोजित प्रतिफल में सुधार किया है। ऐसे में उभरते बाजारों से पूंजी निकलकर दूसरे बाजारों की ओर जा रही है।

इसी तरह के विचार व्यक्त करते हुए मार्निंगस्टार इन्वेस्टमेंट रिसर्च इंडिया के प्रधान प्रबंधक शोध हिमांशु श्रीवास्तव ने कहा कि बढ़े हुए अमेरिकी बांड प्रतिफल और डालर की मजबूती ने अमेरिकी संपत्तियों को तुलनात्मक रूप से अधिक आकर्षक बना दिया है।

सोने में मजबूती बने रहने की संभावना, चांदी में स्थिरता संभव

नई दिल्ली, 18 जनवरी (भाषा)।

सुरक्षित निवेश की मांग और अमेरिकी फेडरल रिजर्व की तरफ से नीतिगत दर में कटौती की उम्मीदों के चलते आने वाले सप्ताह में सोने की कीमतों में तेजी का रुख बने रहने की संभावना है, जबकि तेज उछाल के बाद चांदी में कारोबार कुछ हद तक स्थिर या सीमित दायरे में रह सकता है। विश्लेषकों ने यह राय जताई है।

विश्लेषकों ने कहा कि निवेशकों की नजर अगले सप्ताह वैश्विक स्तर पर जारी होने वाले प्रमुख आर्थिक आंकड़ों पर रहेगी। इनमें प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रास्फीति के आंकड़े, निजी उपभोग व्यय सूचकांक, सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि और बेरोजगारी भत्ते से जुड़े दावे शामिल हैं।

जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज के उपाध्यक्ष (जिंस एवं मुद्रा शोध) प्रणव मेर ने कहा कि चीन से आने वाले आर्थिक आंकड़े औद्योगिक धातुओं के लिहाज से अहम होंगे। इसके अलावा, विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का संबोधन और व्यापार शुल्कों से जुड़े अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी बाजार की दिशा तय करने वाले कारक होंगे।

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर बीते सप्ताह सोने का वायदा भाव 3,698 रुपए यानी 2.7 प्रतिशत बढ़ा। इस दौरान सोने ने बुधवार को 1,43,590 रुपए प्रति 10 ग्राम का रिकार्ड स्तर भी हासिल किया। मेर ने कहा कि कमजोर रुपए और सुरक्षित निवेश की मांग से घरेलू बाजार में सोने को समर्थन मिला। हालांकि शुक्रवार को ऊंचे स्तर पर मुनाफावसूली होने से सोने की कीमतों में कुछ नरमी आई।

अभियान

अहमदाबाद को साफ-सुथरा बनाने के लिए रविवार को मांझा इकट्ठा करते नगर निगम के कर्मचारी।

तेज रफ्तार ट्रेन के संबंध में केंद्र सरकार का दावा

दोगुनी से अधिक हुई पटरियों की लंबाई

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 18 जनवरी।

भारतीय रेलवे ने पिछले 11 वर्षों के दौरान किए गए निवेश से तेजी से पटरी बिछाने के साथ ही सुरक्षा मानकों को भी और पुख्ता किया है। रेलगाड़ियों के सुरक्षित, त्वरित और अधिक विश्वसनीय के लिए विस्तार का सिलसिला लगातार जारी है। इस दौरान तेज रफ्तार ट्रेनों के लिए रेल नेटवर्क (पटरी) में दोगुना से अधिक की बढ़ोतरी के बाद यह 84,244 किलोमीटर हो गई है। इन पटरियों पर 110 किमी प्रति घंटे से अधिक तेज रफ्तार से ट्रेनों का परिचालन भी हो रहा है। यह बयान रेल मंत्रालय की ओर से रविवार को दिया गया।

मंत्रालय के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, भारतीय रेलवे ने 6,851 किलोमीटर पर पटरी का नवीनीकरण किया। चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में 7,500 किलोमीटर में पटरियों का नवीनीकरण किया जा रहा है। 2026-27 के लिए 7,900 किलोमीटर में नवीनीकरण की योजना है। रेल मंत्रालय ने कहा कि पटरियों के नवीनीकरण का कार्य तेजी से जारी है जो ट्रेनों की सुचारू आवाजाही के लिए अहम है। पिछले दो वर्षों के दौरान रेलवे क्रासिंग भी तैयार किए जा रहे हैं ताकि ट्रेनों की आवाजाही और सुलभ व सुरक्षित हो। रेल पटरियों की स्थिरता बनाए रखने और गुणवत्ता में सुधार के लिए मशीनीकृत डीप स्क्रीनिंग भी लगातार की गई है। 2024-25 के दौरान 7,442 किलोमीटर जबकि 2025-26 में 7,500 से अधिक किलोमीटर के दायरे में डीप स्क्रीनिंग का काम जारी है। मशीनीकृत रखरखाव और उत्पादकता में सुधार के लिए रेलवे ने अपने मशीन बेड़े का काफी विस्तार किया है। वर्ष 2014 से अब तक 1,100 से अधिक ट्रैक मशीनें खरीदी गईं, जिससे रेलवे नेटवर्क पर सेवाओं की गुणवत्ता में लगातार सुधार हो रहा है। रेल पटरियों के किनारे सुरक्षा बाड़ लगाने का काम प्राथमिकता के आधार पर किया गया है ताकि मवेशियों की ट्रेन से टक्कर या अनाधिकृत प्रवेश की घटनाएं कम हो सकें।

मौनी अमावस्या पर साढ़े चार करोड़ लोगों ने लगाई डुबकी

प्रयागराज, 18 जनवरी (भाषा)।

प्रयागराज में जारी माघ मेले में रविवार को मौनी अमावस्या पर शाम छह बजे तक 4.52 करोड़ श्रद्धालुओं ने गंगा और संगम में डुबकी लगाई।

इस बीच, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर स्नान कर रहे श्रद्धालुओं और साधु संतों पर हेलिकाप्टर से पुष्प वर्षा की गई। मेला प्रशासन के एक अधिकारी ने बताया कि कल रात 12 बजे से ही स्नान करने के लिए लोगों का गंगा और संगम क्षेत्र में आना जारी रहा। इस दौरान, सुबह स्नान के दौरान संगम नोज पर उस समय विवाद खड़ा हो गया, जब ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को भारी संख्या में समर्थकों के साथ संगम में जाने से पुलिस ने रोक दिया। पुलिस अधीक्षक (माघ मेला) नीरज पांडेय ने बताया कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने बिना किसी अनुमति के 200-250 समर्थकों के साथ पुल नंबर दो का बैरियर तोड़कर स्नान घाट की तरफ प्रवेश किया। पांडेय के मुताबिक, उन्हें बताया गया था कि श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है, इसके बावजूद वह नहीं माने और रोकने पर वह स्नान किए बगैर वापस चले गए। उन्होंने बताया कि पुलिस प्रशासन सभी साधु संतों का सम्मान करती है, लेकिन श्रद्धालुओं की सुरक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है। वहीं, शंकराचार्य के मीडिया प्रभारी शैलेंद्र योगीराज ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि जगद्गुरु शंकराचार्य ज्योतिषपीठाधीश्वर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज को प्रशासन ने आज जानबूझकर स्नान करने से रोका।

उन्होंने कहा, 'यह घटना पूरी तरह से सुनियोजित थी और प्रशासन ने जानबूझकर उन्हें स्नान करने से रोका जो निंदनीय कार्य है।'

जलवायु कार्यकर्ता वांगचुक की पत्नी गीतांजलि अंगमो ने कहा | बयान | 26 सितंबर को हिरासत में लिया गया था

सोनम के खिलाफ रासुका के मामले में कोई दम नहीं

नई दिल्ली, 18 जनवरी (भाषा)।

जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि अंगमो ने कहा है कि उनके पति की गिरफ्तारी देश में लोकतंत्र की स्थिति को दर्शाती है, जहां सत्ता का इस्तेमाल लोगों को 'अवैध रूप से हिरासत में लेने' के लिए किया जाता है। उन्होंने दावा किया कि वांगचुक के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) के मामले में कोई दम नहीं है इसलिए सरकार अदालत से बार-बार नई तारीख मांग रही है।

अंगमो ने समाचार एजंसी के साथ साक्षात्कार में आरोप लगाया कि अधिकारियों द्वारा की गई 'प्रक्रियात्मक चूक' के मद्देनजर वांगचुक को पहले ही जेल से बाहर आ जाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि यह 'बिल्कुल स्पष्ट मामला' है।

अंगमो ने स्वीकार किया कि उन्हें इस बात से थोड़ी निराशा हुई है कि वांगचुक की गिरफ्तारी का कड़ा विरोध नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि हम चुप नहीं रह सकते और वांगचुक की गिरफ्तारी के खिलाफ सामूहिक और मुखर विरोध की अपील की।

गीतांजलि अंगमो ने आरोप लगाया कि अधिकारियों द्वारा की गई 'प्रक्रियात्मक चूक' के मद्देनजर वांगचुक को पहले ही जेल से बाहर आ जाना चाहिए था। यह 'बिल्कुल स्पष्ट मामला' है। इस बात से थोड़ी निराशा हुई है कि वांगचुक की गिरफ्तारी का कड़ा विरोध नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि हम चुप नहीं रह सकते और वांगचुक की गिरफ्तारी के खिलाफ सामूहिक और मुखर विरोध की अपील की।

अंगमो ने कहा कि यह सिर्फ सोनम वांगचुक के बारे में नहीं है, बल्कि इस देश में लोकतंत्र की स्थिति के बारे में है, इस देश के लिए काम करने वाले लोगों को अवैध रूप से हिरासत में रखने के लिए सत्ता का इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर यह सोनम के साथ हो सकता है, तो किसी और के साथ भी हो सकता है। जलवायु कार्यकर्ता और शिक्षाविद वांगचुक को 26 सितंबर को कड़े राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका)के तहत हिरासत में लिया गया था। उनके खिलाफ यह कार्रवाई लद्दाख को राज्य का दर्जा देने और छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर हुए विरोध प्रदर्शनों के दो दिन बाद की गई थी। उक्त विरोध प्रदर्शन के दौरान केंद्र शासित प्रदेश में चार लोग मारे गए और 90 घायल हो गए थे। वांगचुक को जोधपुर की जेल में ले जाया गया था। पुलिस के मुताबिक, जलवायु कार्यकर्ता ने भड़काऊ बयान दिया, जिसकी वजह से हिंसा भड़की। वांगचुक के साथ मिलकर हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्स, लद्दाख की स्थापना करने वाली अंगमो ने पति की हिरासत को चुनौती देते हुए और उनकी तत्काल रिहाई का अनुरोध करते हुए बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की है।

अंगमो ने कहा कि यह काफी मुश्किल काम रहा है, हिरासत आदेश प्राप्त करने और सोनम से मिलने के लिए उच्चतम न्यायालय में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर करने की जरूरत थी और उसके दायर होने के बाद भी, उनके हस्तलिखित नोट्स प्राप्त करना एक चुनौती थी।

'स्वरूपों' के विवाद मामले में सुखविंदर का कानवेयर अध्यक्ष के पद से इस्तीफा

चंडीगढ़, 18 जनवरी (ब्यूरो)।

पंजाब में बंगा के विधायक सुखविंदर कुमार सुक्खी ने रविवार को 'कंटेनर एंड वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन' (कानवेयर) के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने और कैबिनेट सदस्य का दर्जा छोड़ने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि 'रसोखाना श्री नभ कंवल राजा साहिब गुरुद्वारा' के बारे में संदेह जताए जाने के बाद वह आहत हुए हैं।

सुक्खी 2024 में शिरोमणि अकाली दल छोड़कर 'आप' में शामिल हुए थे। उनका इस्तीफा पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के उस बयान के कुछ दिनों बाद आया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि 328 लापता 'स्वरूपों' (गुरु ग्रंथ साहिब के पवित्र स्वरूपों) की जांच के दौरान एसआइटी ने गुरुद्वारे से गुरु ग्रंथ साहिब की 169 पवित्र प्रतियां बरामद की हैं।

Please Support me by joining My Private Channel

✅ I Give My Earliest Newspapers updates from 5 AM in Private channel with All Editions

♦ **Indian Newspaper**

1) Times of India
2) The Hindu
3) Business line
4) The Indian Express
5) Economic Times
6) Financial Express
7) Live Mint
8) Hindustan Times
9) Business Standard

♦ **International Newspapers channel**

[Europian, American, Gulf & Asia]

♦ **Magazine Channel**

National & International

[Genaral & Exam related]

♦ **English Editorials**

[National + International Editorials]

Click Here